3 राजधानी
कोरोना पर निर्देश तोड़े तो होगी एफआईआर

8 अभिमत
श्रम बाजार को मुक्त करना जरूरी

13 कारोबार
यात्रा प्रतिबंधों के कारण सिंगापुर में फंसे 97 भारतीय यात्री

14 स्पोर्ट्स
स्थगित हो सकता है ओलंपिक !

RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 135
नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 मार्च, 2020
पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

यदि ठान ले तो महिलाएं हर संकल्प को पूरा कर सकती हैं

विविध-16

दुनिया को दहलाने वाली कोरोना महामारी को संकल्प व संयम से पछाड़ने का इरादा

22 मार्च को जनता खुद पर लगाए कर्फ्यू: मोदी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस को लेकर देश की जनता को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

- कोरोना संकट को पहले-दूसरे विश्व युद्ध से भी गंभीर बताते प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ देशवासियों से की घरों में रहने की अपील
- जनता कर्फ्यू के लिए मांगा लोगों से समर्थन- सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक करना होगा पालन
- खतरा उठाकर आवश्यक सेवाएं देने वालों का आभार जताने को तय किया रविवार शाम 5 बजे का समय, 5 मिनट तक ताली-थाली-घंटी बजाने का आग्रह
- कहा-जब बड़े देश प्रभावित हैं तो भारत पर असर स्वाभाविक

कोरोना वायरस से फैली महामारी को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर संकट करार देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे दृढ़ संकल्प और संयम के साथ इसके संक्रमण से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। भरसक घरों में बने रहने और भीड़ भाड़ से बचने पर जोर देते प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यह जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू होगा और इसका पालन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक करना होगा। इस दौरान कोई भी नागरिक बाहर नहीं निकले-अपने घर में ही रहे।

नागरिक के तौर पर इसे देखने के लिए भी सड़क पर न जाने का आग्रह करते प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के दायित्व को बड़ा बताकर उन्हें इससे अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से डॉक्टर, नर्स, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मचारी, उड़न सेवाओं के कर्मचारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, रेलवे, बस, ऑटो चालक और होम डिलीवरी करने वाले यह लोग अपनी जान का जोखिम उठाकर दूसरों की सेवा करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। ये लोग कोरोना वायरस और हमारे बीच राष्ट्र रक्षक की तरह शक्ति बनकर खड़े हैं। जनता कर्फ्यू के दिन देश को इन्हें धन्यवाद देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को धन्यवाद देने का तरीका बताते हुए कहा कि यह ऐसा होगा जो देश भर में एक-एक व्यक्ति को जोड़ देगा। उनका आग्रह है कि 22 मार्च को शाम के ठीक पांच बजे हर कोई अपने घर के दरवाजे, खिड़की, बालकनी पर खड़े होकर पांच मिनट तक ताली, थाली या फिर छोटी घंटी बजाकर इनका आभार व्यक्त करें। उनका हौसला बढ़ाएं-उन्हें सेल्यूट करें। राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन से भी उनका अनुरोध है कि रविवार को शाम पांच बजे सायरन की आवाज बजाकर सेवा को परम धर्म मानने वालों को धन्यवाद दें।

देशवासियों पर भरोसा जताते प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जब भी जो भी मांगा, लोगों ने कभी निराश नहीं किया। यह उनके आशीर्वाद की ही ताकत है कि वे साथ मिलकर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज इस संकट की घड़ी में भी वे 130 करोड़ भारतवासियों से कुछ मांगने आए हैं। उन्हें उनसे आने वाले कुछ हफ्ते-उनका समय चाहिए। अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से मुकाबले का कोई निश्चित उपाय नहीं दे सका है और न तो वैक्सीन ही बनी है। ऐसे में चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। जिन देशों में कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा रहा है वहां अध्ययन से पता चला है कि शुरुआती दिनों के बाद अचानक इस बीमारी का विस्फोट हुआ है। वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। सरकार इस ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर रखे हुए है। इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक निर्देश दिए और अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट (अलग-थलग) कर स्थिति को संभाल लिया। इस स्थिति में नागरिकों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले (शेष पेज 10)

कोरोना वायरस का कहर

चौथी मौत, भारत ने खुद को दुनिया से काटा

- सरकार ने 22 से सभी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के उतरने पर एक हफ्ते के लिए लगाया प्रतिबंध, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 173
- पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक मामले सामने आए, शेयर बाजार भी लुढ़का- सेंसेक्स 581 अंक टूटा
- केंद्र ने अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की दी इजाजत

बीकानेर में कोरोना वायरस के चलते मास्क लगाएं नर्सिंग छात्राएं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी से गुरुवार को भारत में चौथी मौत हुई जबकि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर 173 हो गई है। दूसरी ओर इसका प्रकोप बढ़ने से कई राज्यों में पाबंदियां लगाई जाने के चलते वे बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे है। इस बीच, भारत ने 22 मार्च से सभी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के उतरने पर एक हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वायरस के संक्रमण से पंजाब में पहले और देश में चौथे व्यक्ति की मौत हुई है। यह व्यक्ति मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का भी सामना कर रहा था। छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमण के पहले मामले आज सुबह दर्ज किए जाने के साथ देश में पिछले चौबीस घंटों में इसके 20 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई और राज्य ने नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।

उधर, कोरोना वायरस महामारी के कारण घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार चौथे दिन जारी रहा और बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार को 581 अंक से अधिक टूट कर 28,288.23 अंक पर बंद हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका में निवेशक सुरक्षित विकल्पों को तरजीह दे रहे (शेष पेज 10)

कमलनाथ सरकार के भविष्य का निर्णय आज

- सुप्रीम कोर्ट ने शाम पांच बजे तक शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा
- सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने और संभव हो तो इसका सीधा प्रसारण करने का भी निर्देश दिया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन पी प्रजापति को निर्देश दिया कि शुक्रवार को सदन का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण कराया जाए और यह प्रक्रिया शाम पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने सदन में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शक्ति परीक्षण की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने और संभव हो तो इसका सीधा प्रसारण करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि अगर कांग्रेस के 16 बागी विधायक विधानसभा में शक्ति परीक्षण की कार्यवाही में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करें तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि सदन की कार्यवाही के लिए सिर्फ शक्ति परीक्षण ही विषय होगा और इसमें किसी के लिए भी कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। शीर्ष अदालत ने राज्य विधानसभा के सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वहां किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो।

वहीं उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस आदेश के हर पहलू का अध्ययन करेंगे और इसके बाद अपने विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर कोई निर्णय लेंगे। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अदालत के आदेश के बाद कहा कि सत्य की जीत होती है। चौहान ने शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए संवाददाताओं से कहा, सत्यमेव जयते। न्याय की जीत हुई है। शक्ति परीक्षण में यह सरकार (कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार) पराजित होगी और (भाजपा नीत) नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा, यह सरकार अल्पमत में है और कल यह सिद्ध हो जाएगा। वहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखेगा और खरीद-फरोख्त को रोकेगा। राज्यपाल लालजी टंडन ने भी मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वर्तमान में बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायक विधानसभा की बैठक में भाग लेने आएंगे, तो भार्गव ने कहा, यह उन पर निर्भर करेगा कि वह कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। जब भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (पूर्व केन्द्रीय मंत्री) जैसे नेता पर हमला हो सकता है तो वे कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कल सदन की कार्यवाही में शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

एसएससी, सीआईएससीई ने टाली परीक्षाएं

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कोरोना वायरस के मद्देनजर ऐहतियाती तौर पर अपनी प्रमुख भर्ती परीक्षाएं गुरुवार को रद्द कर दीं। आयोग ने एक बयान में कहा, कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के मद्देजनर जनहित में ऐहतियाती कदम उठाते हुए संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर की परीक्षा (टियर-1), 2019 की जारी भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसी प्रकार, 30 मार्च से शुरू होने वाली जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट) परीक्षा 2019 को भी स्थगित कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इन परीक्षाओं का नया कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। वहीं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशंस (सीआईएससीई) ने अंतिम समय में लिए गए निर्णय में दसवीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं जो गुरुवार से शुरू होने वाली थी। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। बारहवीं कक्षा की समाजशास्त्र की परीक्षा दोपहर दो बजे से होने वाली थी और सुबह 10 बजे ही परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की गई।

रेलवे ने कुछ श्रेणियों को छोड़ अन्य रियायती टिकटें स्थगित की

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गैर जरूरी यात्राओं को हतोत्साहित करने के लिए 20 मार्च की आधी रात से रोगी, छात्र और दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की रियायती टिकटों को स्थगित करने का फैसला किया है। रेलवे ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) और यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) से किसी भी श्रेणी में रियायती टिकट जारी नहीं की जाएगी सिवाय छात्रों, दिव्यांग की चार श्रेणियों और रोगियों की 11 श्रेणियों में जारी होने वाले टिकटों के। आदेश मे कहा गया, उपरोक्त आदेश 20 मार्च 2020 को आरक्षित टिकटों और अगले आदेश तक जारी होने वाले टिकटों पर लागू रहेगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया, 53 श्रेणियों में केवज 15 श्रेणियों में ही रियायती टिकट जारी किए जाएंगे। शेष 38 श्रेणियों में कोरोना वायरस के चलते छूट को वापस ले लिया गया है।

रेस्तरां बंद, 20 से अधिक लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- स्कूल-कॉलेज 31 तक पूरी तरह बंद, बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने का काम रोका

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सभी रेस्तरां बंद करने आदेश दिए गए हैं। आप सरकार ने कहीं भी बीस से अधिक लोगों के खड़े होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, खाना खरीदकर ले जाने और घर तक खाना पहुंचाने की सुविधा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम भी रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल अनिल (शेष पेज 10)

भारत ने कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान की निंदा की

नई दिल्ली। भारत ने इस सप्ताह की शुरूआत में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए गुरुवारको पाकिस्तान की निंदा की। भारत ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय मंच था और पाकिस्तान ने इसका दुरुपयोग किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आपात दक्षेस कोष की शुरूआत हो गई है और भारत को मदद के लिए सदस्य देशों से अनुरोध प्राप्त हुए है। कुमार ने वीडियो-कांफ्रेंस के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर कहा, इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा में सीमाओं का बंधन नहीं है, इसी भावना से प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस पर दक्षेस वीडियो कांफ्रेंस का आह्वान किया था। यह मंच राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय था। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सप्ताहांत में इटली से भारतीयों के अगले समूह को निकालने की योजना है।

बाजार

सेंसेक्स	28,288	↓ 581	
निफ्टी	8,263	↓ 205	
सोना	40,718	↑ 31	/10g
चांदी	35,444	↓ 190	/kg

क्विक न्यूज

तस्करी का चार करोड़ का सोना जब्त, सात गिरफ्तार

मंगलुरु। कर्नाटक मे तीन अलग-अलग स्थानो से लगभग चार करोड़ के सोने के साथ सात लोगो को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियो ने यह जानकारी दी। डीआरआई के अनुसार विशिष्ट जानकारी पर कार्रवाई करते हुए मध्य रेलवे स्टेशन से दो व्यक्तियो को पकड़ा गया। वे तस्करी के कच्चे सोने की खेप को कोझिकोड से मंगलुरु लेकर आए थे। जो व्यक्ति उनसे सोना प्राप्त करने वाला था उसे भी रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। मंगलुरु, उडुपी और शिवमोग्गा मे तीन अलग-अलग स्थानो की एक साथ तलाशी ली गई। कोझिकोड और मंगलुरु के बीच नकदी व सोने ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली दो कारे भी बरामद की गई।

विपक्ष की नारेबाजी के बीच गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। कांग्रेस, वाम आदि सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वाकआउट किया।

उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर गोगोई जैसे ही शपथ लेने निर्धारित स्थान पर पहुंचे, वैसे ही विपक्षी सदस्यों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया। हंगामे पर आपत्ति जताते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा व्यवहार सदस्यों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। गोगोई ने अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने सभापति और अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। सदन में हंगामे पर सभापति नायडू ने कहा, आप संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं, आप उदाहरणों को जानते हैं, आप राष्ट्रपति के अधिकारों को जानते हैं। नायडू ने कहाकि आपको सदन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। किसी मुद्दे पर पर आप अपनी राय सदन के बाहर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण पूरी तरह से अनुचित था।

प्रसाद ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के कई गणमान्य लोग इस सदन के सदस्य रहे हैं। (शेष पेज 10)

निर्भया के गुनहगारों को आज दी जाएगी फांसी

सभी तिकड़म खत्म, सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक लटकाए जाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर, 2012 के सनसनीखेज निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के चार में से तीन दोषियों की फांसी के फंदे से बचने के हताशा भरे प्रयासों को विफल करते हुए बृहस्पतिवार को उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।

हालांकि फांसी के कुछ घंटे पहले चार में से तीन दोषियों ने शुक्रवार की सुबह होने वाली फांसी से बचने के लिए एक और दांव चलते हुए गुरुवार की रात दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि चारों दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि पर उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम है और हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इस मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों दोषियों को शुक्रवार को सवेरे साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी पर लटकाने के लिए निर्धारित तारीख से एक दिन पहले पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय सिंह ने बारी-बारी से शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कीं। दो याचिकाएं तो आज ही दायर की गई थीं।

इस अपराध के चौथे मुजरिम ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने सहित सारे कानूनी विकल्पों का सहारा लिया। शीर्ष अदालत के छह न्यायाधीशों ने पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका पर विचार करने के साथ इस मामले की कार्यवाही शुरू की। पवन गुप्ता ने उसके किशोर होने के दावे को पुनर्विचार याचिका में अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के 31 जनवरी के फैसले के खिलाफ

सुधारात्मक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली छह न्यायाधीशों की पीठ ने पवन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई मामला नहीं बनताा है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, मौखिक सुनवाई का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। हमने सुधारात्मक याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया है। हमारी राय में इसमें कोई मामला नहीं बनता है। अत: सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है। इस पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना शामिल थे।

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उसके बाद दोषी मुकेश और अक्षय की दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपराह्न ढाई बजे विस्तार से सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति भूषण और न्यायमूर्ति बोपन्ना भी शामिल थे। मुकेश सिंह की ओर से अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की दलीलें विस्तार से सुनीं और उसकी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर यह अपील खारिज कर दी। मुकेश का दावा था कि 16 दिसंबर, 2012 को हुई इस वारदात के (शेष पेज 10)

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 मार्च 2020

एचसीएल कर्मचारी में भी हुई कोरोना की पुष्टि

विदेश यात्रा से लौटा था संक्रमित शख्स, सेल्फ आइसोलेशन में गया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

शहर स्थित देश की एक बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का एक कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कंपनी के नोएडा ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। वह कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा कर भारत लौटा है। यह व्यक्ति सेल्फ आइसोलेशन में चला गया है। उक्त कर्मचारी में एक दिन पहले ही कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। कंपनी का कहना है कि हमारा ऑफिस सरकार और सभी स्वास्थ्य सलाहकारों के नियमों का पालन कर रहा है।

कोरोना संदिग्ध ने की आइसोलेशन की मांग

मंगलवार से क्वारंटाइन वार्ड में रह रहा थाइलैंड और सिडनी से लौटकर आया व्यक्ति अपने फ्लैट में आइसोलेट होना चाहता है। आरडब्लूए की मनाही के बाद वह नोएडा सेक्टर-39 स्थित नए जिला अस्पताल में बनाए गए क्वारंटाइन वार्ड में रह रहा है। मंगलवार को उसे वहां भर्ती कराया गया था। व्यक्ति में कोरोना के प्रभाव के लक्षण नहीं मिले हैं। वार्ड में भर्ती शख्स का कहना है कि अगर कोई कोरोना वायरस संभावित देश से वॉर्ड में आएगा तो वह उसके संपर्क में आकर संक्रमित हो सकता है। इसको देखते हुए उसने फ्लैट में ही 14 दिन तक आइसोलेट करने की गुहार लगाई है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं, इसलिए नमूने नहीं लिए गए हैं। शख्स ने बताया कि मैं खुद को 14 दिन तक फ्लैट के अंदर आइसोलेट करने को तैयार हूं। आरडब्ल्यूए चाहे तो फ्लैट का बाहर से ताला लगा दे। वहीं, इस मामले में आरडब्लयूए का कहना है कि हमने व्यक्ति को सोसाइटी में आने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उसको फ्लैट के अंदर खुद को आइसोलेट करना होगा। इस मामले में सीएमओ से बात की गई है।

स्वास्थ्य विभाग में साप्ताहिक छुट्टी रद्द

नोएडा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से अपने काम निपटाने के निर्देश दिए हैं ताकि विपरित परीस्थितियों में भी बेहतर काम हो सके। कोरोना वायरस की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनुराग भार्गव ने बताया कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी सीट पर बैठना होगा। स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मियों को एक किलोमीटर के दायरे में अलग-अलग स्थानों से काम कराएगा। इसके लिए जगह तलाश ली गई है।

दक्षिणी अफ्रीका से लौटे परिवार को अस्पताल भेजा

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौर सिटी सोसाइटी के फर्स्ट एवेन्यू में रहने वाला एक परिवार बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से लौटा। कोरोना वायरस से भयभीत सोसाइटी के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। इसके बाद परिवार को अस्पताल में भर्ती के लिए ले जाया गया। परिवार के सदस्यों को कोरोना का संदिग्ध मानकर किसी ने देर शाम पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम सोसाइटी पहुंची और इस परिवार के एक बच्चे, महिला और पुरुष को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

13 अप्रैल तक छुट्टी, कंपनी नहीं देगी सैलरी

नोएडा। कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पहुंची है। हालात की गंभीरता देखते हुए बहुत सी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। केंद्र सरकार ने भी अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है।

इस बीच नोएडा की एक कंपनी ने अपने यहां ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को 13 अप्रैल तक छुट्टी पर भेज दिया है। इस दौरान उनकी सैलरी भी नहीं बनेगी यानी लीव विदाउट पे रहेगा। यह कंपनी नोएडा के सेक्टर 67 में है और अमेरिका स्टाफिंग के लिए काम करती है। बुधवार रात अचानक से नोटिस जारी किया गया।

इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने के भीतर ज्वॉइन किया है। वे कर्मचारी अब काफी परेशानी में हैं। कंपनी ने यह भी कंफर्म नहीं किया गया है कि उन्हें 13 अप्रैल के बाद वापस नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं।

विदेश से लौटे 534 लोगों की डब्ल्यूएचओ ने मांगी लिस्ट

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजियाबाद के उन 534 लोगों की सूची मांगी है, जो एक माह के दौरान विदेश यात्रा कर लौटे हैं। डब्ल्यूएचओ की ओर से ऐसे लोगों की सूची मांगे जाने के बाद पासपार्ट ऑफिस अब इन लोगों की जानकारी जुटाने में लगा है।

सूत्रों के अनुसार, गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय के तहत आने वाले 13 जिलों में पिछले एक माह के दौरान सैंकड़ों लोग विदेश से आए हैं। इनमें अकेले गाजियाबाद से 534 लोग शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों से आए हैं। डब्ल्यूएचओ यह जानना चाहता है कि एक माह के भीतर विदेश से आने वाले लोगों के कोरोना वायरस की जांच हुई है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में डब्ल्यूएचओ की ओर से इन लोगों से संपर्क कर इनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की जाएगी।

भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव अभी दूसरे चरण में है। यही कारण है कि यूपोपियन देशों और चीन के मुकाबले यहां संक्रमित लोगों की संख्या कम है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि तीसरे और चौथे चरण में जाकर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती है। पहले दो चरणों में विदेश से आने वाले लोग व उनके परिजनों में संक्रमित वायरस पाया गया। तीसरे चरण में उन लोगों में संक्रमण मिलने की संभावना है, जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे। ये आम जनमानस होते हैं। ऐसे में डब्ल्यूएचओ की ओर से उन लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है जो पिछले एक माह के भीतर विदेश से लौटे हैं।

जूते-चप्पल पहन कर आने पर लगी रोक

गाजियाबाद। अब तक तो लोग मंदिरों में दर्शन करने से पहले जूते-चप्पल उतारते थे लेकिन, अब तो दफ्तरों में भी ये नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल, कोरोना वायरस को लेकर लोनी नगर पालिका में जूते बाहर निकाल कर अंदर जाने का आदेश दिया गया है।

सरकारी दफ्तर में लोगों का अवागमन लगा रहता है। जिससे कोरोना वायरस के फैलने के आसार ज्यादा रहते हैं। इसे लेकर लोनी नगर पालिका में जूते बाहर निकालकर अंदर जाने के आदेश दिए गए हैं। अब जो भी व्यक्ति नगर पालिका के अंदर जायेगा वो जूते बाहर उतारेगा। माना जा रहा है कि अन्य दफ्तरों में भी यह कदम उठाया जा सकता है। इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तर में जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें जूते-चप्पल उतारकर आना पड़ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक कोरोना वायरस का खतरा बना रहेगा और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खतरा टले जिससे उनकी मुश्किलें कम हो सकें।

बीमारी के डर से बिन बताए ड्यूटी छोड़कर छुट्टी पर भागे डाक्टर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

कोरोना को देश और दुनियाभर में महामारी घोषित किए जाने के बाद हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, फिर वो मरीज हों या डॉक्टर। ऐसा ही एक मामला यहां सरकारी एमएमजी अस्पताल में देखने को मिला। यहां के कुछ सरकारी डॉक्टर इस घातक बीमारी से अपना बचाव करते हुए ड्यूटी छोड़कर ही चले गए। इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया।

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल और संयुक्त जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क तैयार की गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टरों को तैनात किया गया था। एमएमजी अस्पताल में हेल्प डेस्क पर सीनियर पैथोलॉजिस्ट को तैनात किया गया था। लैब प्रभारी को अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती मरीज का सैंपल लेने को कहा गया था, जिसके बाद वह बिना सूचना दिए अस्पताल से नदारद हो गईं।

वहीं, कोरोना हेल्प डेस्क पर तैनात सीनियर डॉक्टर ने बीमार होने की बात कहते हुए बुधवार को ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया।

कोरोना से निपटने को प्रशासन की निगरानी में 17 वृद्ध आश्रम

- डीएम ने निरीक्षण के बाद लिया निर्णय

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

कोरोना से निपटने के लिए जनपद के 17 वृद्ध आश्रमों को विशेष निगरानी में रखने का जिला प्रशासन ने फैसला किया है। अभी तक किसी भी आश्रम में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे।

बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने खुद दुहाई स्थित एक वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया जहां यह पाया गया कि इस महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। डीएम ने मौके पर ही बुजुर्गों से बातचीत की और कोरोना से निपटने के लिए उन्हें मास्क, दस्ताने व सेनेटाइजर वितरित किए। जिलाधिकारी ने जिले के सभी 17 वृद्ध आश्रमों में रह रहे बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच के लिए दो चिकित्सकों को अधिकृत करने का भी एलान किया। इसके अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतिदिन दो वृद्ध आश्रमों का दौरा करेंगे और प्रतिदिन जिलाधिकारी को अपनी स्टेट रिपोर्ट सौपेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि ताजा निर्देशों के तहत सरकार की तरफ से वृद्ध आश्रमों में प्रतिदिन दो बार पोछा लगाया जाएगा और चार बार उसे सेनेटाइज किया जाएगा। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव बुजुर्गों पर ही पड़ता है इसलिए वृद्ध आश्रमों को जिला प्रशासन ने वरीयता में सबसे ऊपर रखा है। कोरोना से बचने के उपाय के लिए कुछ साइन बोर्ड भी प्रत्येक आश्रम में लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वृद्धों के बिस्तरों को भी सेनेटाइज किया जाएगा और उनकी बैड शीट प्रत्येक दिन बदली जाएगी।

सभी साप्ताहिक पैठ बाजार बंद

कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता बरतने के लिए जिले के सभी पैठ बाजारों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं। जिले में इस समय सौ से डेढ़ सौ के आसपास चिन्हित पैठ बाजार हैं जहां निम्न और मध्यम वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर रोजमर्रा की खरीददारी करते हैं। आपको बता दें कि शहर के तमाम मल्टीप्लैक्स, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब, कोचिंग सेंटर, बड़े मंदिर पहले की बंद किए जा जा चुके हैं।

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर पेनिक खबर और फर्जी पोस्ट डालने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि यदि किसी ने भी कोरोना को लेकर फर्जी ढंग से पेनिक खबर फैलाने की कोशिश की तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा।

वृद्ध आश्रम में लोगों बातचीत करते हुए जिलाधिकारी डा. अजय शंकर पांडेय।

संक्षिप्त समाचार

विकास भवन में प्रेसवार्ता के दौरान शासन के तीन वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते प्रभारी मंत्री संदीप सिंह।

प्रदेश सरकार की गिनाईं उपलब्धियां

हापुड़। उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को विकास भवन में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। प्रभारी मंत्री ने कोरोना वायरस के पीड़ितों हेतु बनाए गए आइसोलेसन वॉर्ड का निरीक्षण किया और फिर विकास भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रभारी मंत्री ने यह भी बताया की प्रदेश की योगी सरकार के इन तीन वर्षो में राज्य में कोई भी दंगा नहीं हुआ है और गरीबों तक सभी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी अदिति सिंह, जिला चिकित्सा अधिकारी रेखा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता कुमार, प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत, जिलाध्यक्ष उमेश राणा आदि अधिकारी व भाजपा नेता मौजूद रहे।

मिठाई की दुकान में पिलर से टकराकर खड़ी क्षतिग्रस्त कार।

नशे में धुत कार सवार ने ठोकी कार

गाजियाबाद। सिहानी गेट कोतवाली क्षेत्र में कार सवार नशेड़ियों के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार कार शगुन स्वीट्स की बिल्डिंग में घुस गई और पिलर से टकराकर चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को चोट नहीं आई और वह पुलिस के आने के डर से कार छोड़कर फरार हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर कार को अपने कब्जे में ले लिया। सिहानी गेट कोतवाल गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। पुलिस को जानकारी मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर कार अंबेडकर रोड स्थित शगुन स्वीट्स की बिल्डिंग में घुसी हुई है। कार बिल्डिंग में लगे पिलर से टकराकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि कार लखनऊ की है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोगों ने शराब पी रखी थी।

संसद में उठाया छात्र के ऋण माफी का मुद्दा

हापुड़। मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान शिक्षा-ऋण लेने के पश्चात छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उसके शिक्षा ऋण को माफ किए जाने के की मांग की। सांसद ने कहा कि मेरठ निवासी रघुराज सिंह के पुत्र विवेक सांगवान ने बीटेक की शिक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक से वर्ष 2009 में 3,13,800 रुपए का कर्ज लिया था। बीटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही विवेक सांगवान को कैंसर होने का पता चला। 1 नवंबर, 2013 को उसका देहांत हो गया। इसके पश्चात् छात्र के पिता को बैंक द्वारा कर्ज का सहऋणी मानते हुए वसूली हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं।

कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले दो युवक धरे गए

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

कार में लिफ्ट देने के बहाने लोगों के साथ लूट-पाट करने वाले दो लुटेरों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के साथ बीती रात एक मुठभेड़ में दोनों लुटेरे जख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसीपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बीती रात थाना फेज-3 पुलिस को कैब में लिफ्ट देकर लूट करने वाले बदमाशों की सूचना मिली। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए चेकिंग शुरू की। बहलोलपुर गांव के पास पुलिस ने संदेह पर एक ओला कैब को रुकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।

उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ विक्की निवासी गाजियाबाद तथा मनु श्रीवास्तव पुत्र विद्यासागर निवासी ग्राम बिशनपुरा के पैर में लगी। इनका एक साथी सलीम मौके से भाग गया। अपर उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने लूटपाट की कई वारदातें करने की बात स्वीकार की हैं।

गोदाम से हुई चोरी का खुलासा, छह गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

- आरोपियों से 35 लाख का माल बरामद

कविनगर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा टॉवर आरडीसी में सेंडिक्स मेमोरी कार्ड व पैन ड्राइव के डिस्ट्रीब्यूटर जितेंद्र अग्रवाल के गोदाम से 50 लाख के माल की हुई चोरी का खुलासा कविनगर पुलिस ने कर दिया है। इस संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 35 लाख का माल, ढाई लाख नकद, गैस कटर व एक कार बरामद की है। यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इनमें से अरूण नामक अभियुक्त पांच वर्ष पहले अग्रवाल एंड संस में नौकरी करता था। उसके बाद वह ओला कार चलाने लगा। इसी बीच अरूण की मुलाकात मनीश नामक एक अन्य व्यक्ति से हुई जो प्राइवेट फार्मा कंपनी में सेल्समेन का काम करता था। आर्थिक तंगी और शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अमीर बनने की चाहत ने जितेंद्र अग्रवाल के गोदाम में चोरी करने की योजना बनाई।

इसके बाद दोनों ने अपने दूसरे साथी भरत अग्रवाल से संपर्क किया जो मनीश के साथ फार्मा कंपनी में नौकरी करता था। पैसे के लालच में यह भी इनके साथ चोरी करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद 21 जनवरी 2020 की रात्रि में भरत अग्रवाल ने अपनी अंबेस्डर कार से अरूण व मनीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का यह माल राजेंद्र नगर में छुपा दिया था।

कुछ समय बीतने के बाद इन लोगों ने शिवा टावर में कंप्यूटर का सामान बेचने वाले अश्वनी खन्ना से संपर्क किया । सस्ते दाम के लालच में आकर अश्वनी खन्ना जैसे ही माल खरीदने के लिए आया था उसे पुलिस ने इनके साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ निवासी मनोज, सौरभ गुप्ता, गाजियाबाद निवासी भरत, मनीश व अरूण हैं।

नो पार्किंग जोन में चलाया अभियान

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण व ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गुरुवार को उद्योग मार्ग पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का अभियान चलाया। दोपहर से शुरू हुई यह ड्राइव शाम तक जारी रही। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन से उठाकर सेक्टर 5 में शुरू हुई भूमिगत पार्किंग में रखा गया। वहीं से लोग अपने वाहन ले रहे हैं।

बता दें कि पिछले दिनों सेक्टर-5 में बनी भूमिगत पार्किंग का प्राधिकरण ने अपने स्तर से संचालन शुरू कर दिया है लेकिन, अभी वहां वाहनों की संख्या बेहद कम है और सुविधा शुरू होने के बाद भी लोग उद्योग मार्ग पर वाहन खड़े कर देते हैं जिससे यहां जाम लगा रहता है।

नाली को लेकर हुआ विवाद, दो लोगों की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

- संघर्ष में आधा दर्जन लोग भी हुए जख्मी
- दो गिरफ्तार, अन्य को तलाश रही पुलिस

थाना दादरी क्षेत्र स्थित नई बस्ती बैरंगपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह नाली को लेकर विवाद हो गया जिसमें गोली चलने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र के नई बस्ती बैरंगपुर गांव में रहने वाले बिरेन्दर की पत्नी मीनू और विनीत की पत्नी अंजलि के बीच बृहस्पतिवार सुबह नाली के पानी को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते झगड़े में दोनों पक्षों के पुरुष भी शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से लाठी-डंडे फरसे और फिर गोली चली। गोली लगने से रविंदर, ब्रह्म सिंह तथा पड़ोस में रहने वाली महिला प्रेम घायल हो गए।

सिंह ने बताया कि घायल रविंदर और प्रेम की मौत हो गई, जबकि ब्रह्म सिंह की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घटना में कुछ और लोग घायल हुए हैं। सिर पर फरसा लगने से घायल एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने विनीत और उसकी पत्नी अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना के अन्य आरोपी सुंदर, ललित, अमित, गौरव, सत्ते, अनुज की पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

चेकिंग में दो शराब तस्करों को पकड़ा

नोएडा। पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 144 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की।

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक सूचना के आधार पर, थाना बीटा-2 क्षेत्र के सेक्टर 33 के पास से एक वाहन को जांच के लिए रोका और जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 144 पेटी हरियाणा मार्का शराब मिली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन में सवार सुमित और योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे काफी दिनों से शराब तस्करी के धंधे में संलिप्त हैं।

शहीद के नाम की शिलापट तोड़े जाने से गुस्साए लोगों द्वारा लगाए गए जाम के दौरान पूर्व विधायक मदन भैया पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए।

बजट नहीं मिलने से इलेक्ट्रिक सिटी बस स्टैंड अधर में

जल निगम ने तकनीकि औपचारिकताएं की पूरी, फंड मिलने पर 6 माह में पूरा होगा निर्माण

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त अनुभाग से तीस करोड़ का बजट समय पर रिलीज न होने के कारण फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम का महत्वकांक्षी इलेक्ट्रिक सिटी बस स्टेंड के निर्माण पर ब्रेक लग गया है। हालांकि इस बस स्टेंड को तैयार करने की सभी तकनीकि औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। निगम ने इस बस स्टैंड को तैयार करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्यदायी सीएंडएस इकाई को सौंपी हुई है।

हालांकि यह प्रोजेक्ट पहले शहर में सौ सिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए था, लेकिन बाद में शासन ने इसको घटाकर 50 बसों तक सीमित कर दिया। सूत्रों की माने तो जैसे ही सीएंडएस को तीस करोड़ स्वीकृत बजट मिल जाएगा, छह माह के अंदर यह पूरी परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। बस स्टैंड का नक्शा आदि सब तकनीकी रूप से स्वीकृत हो चुका है। त

ैयार नक्शे के मुताबिक यह बस स्टैंड मेरठ रोड तिराहे, हिंडन विहार के समीप नगर निगम की 22 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल जमीन पर बनेगा। इस परियोजना के तहत एक बड़ा प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, ड्राइवर रेस्टरूम, इलेक्ट्रिक पंप सब स्टेशन, टायलॉट ब्लाक व रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के नक्शे की स्वीकृति मिल चुकी है।

इसके अलावा 100 किलो लीटर का आरसीसी टैंक का निर्माण भी कराया जाएगा। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बताया कि इस इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनने से शहर के सभी लिंकरोड आवासीय कॉलोनियों से जुड़ जाएंगे जिसके चलते आम नागरिकों को मेट्रो स्टेशन सहित किसी भी गंतव्य पर बहुत कम खर्चे पर पहुंचने की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के चलने से शहर का पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। गाजियाबाद शहर इस समय प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर है। प्रदेश शासन के वित्त अनुभाग से फंड रिलीज होने में हो रही देरी के संबंध में जिलाधिकारी डा.अजय शंकर पांडेय से बात चीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में सचिवालय स्तर पर पत्राचार चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द यह फंड वहां से रिलीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक बस स्टैंड के बनाने की प्रक्रिया परवान चढ़ जाएगी।

असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया शहीद के नाम पर लगा पत्थर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

- गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

टीला शहबाजपुर-जावली गांव चौराहे पर चार दिन पूर्व बनाया गया शहीद स्मारक बुधवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर टीला गांव के लोगों ने बृहस्पतिवार सुबह गाजियाबाद रोड जाम कर हंगामा काटा। पुलिस और पूर्व विधायक ने लोगां को समझाकर शांत किया। गांव के लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ससंद में आतंकवादी हमले में शहीद हुए टीला शहबाजपुर गांव के देशराज मावी का गांव के बाहर चार दिनों पूर्व स्मारक बनाया गया था। बुधवार रात असमाजिक तत्वों ने इस स्मारक को छतिग्रस्त कर दिया था। बृहस्पतिवार को टीला गांव के दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्मारक तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बंथला भोपुरा मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

कोरोना पर निर्देश तोड़े तो होगी एफआईआर

● उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक में लिया गया फैसला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी के सभी रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, 31 मार्च तक पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए हैं।

उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही पहले के 50 लोगों के एक जगह एकत्र होने के आदेश में संशोधन करते हुए इसे 20 तक सीमित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार का दिशा-निर्देश नहीं मानने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लोगो से अपील करते हुए कहा कि सभी सहयोग करें अन्यथा सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार को आवश्यक सेवाओं के मामले में फैसला लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस के कुल 10 मामले सामने आए हैं। कुल संख्या में से, एक की मृत्यु हो गई, तीन लोग ठीक हो गए और बाकी छह की हालत सामान्य है।

फोटो: रंजन डिमरी

समीक्षा बैठक में एलजी अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी बसों, इंटर स्टेट बस टर्मिनलों और मेट्रो ट्रेनों को रोजाना सेनिटाइज (कीटाणुरहित) किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी परिवहन वाहनों को भी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हर बस डिपो पर मुफ्त में कीटाणुरहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से संबंधित सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बाहर से यानी दूसरे देशों से आए अलग रखे जा रहे लोगों के हाथ पर स्टैम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 या उससे अधिक लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षाविदों, सेमिनारों, सम्मेलनों के लिए किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले 50 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी। निजी कंपनियों को सलाह दी गई है कि जहां संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें।

बैंकों और दूसरी जगह लेन-देन को ऑनलाइन ही अंजाम दें। सामाजिक रूप से लोगों से दूरी बनाकर रखें। जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक यात्रा करने से बचें। पुलिस को ब्रीथ एलाइजर से जांच रोकने को कहा गया है। होटलों से अलग-थलग रखे गए व्यक्ति के शुल्क का टैक्स माफ करने को कहा गया है। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर की उपलब्धता दर्शाने को कहा गया है।

सुंदर नगर मार्केट 31 मार्च तक हुआ बंद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत दक्षिणी दिल्ली का रिहायशी बाजार सुंदर नगर मार्केट 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। व्यापार निकाय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीमारी के चलते दिल्ली में बंद होने वाला यह पहला बाजार है। शहर में कोविड-19 के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग इससे संक्रमित हैं।

सुंदर नगर बाजार व्यापार संगठन के अध्यक्ष कोमल जैन ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें लगा कि हमारे सदस्यों, व्यापारियों, कर्मचारियों के साथ ही हमारे ग्राहकों जो अधिकतर विदेशी होते हैं, की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्केट बंद रखना सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक बाजार बंद रखेंगे और बाद में स्थिति की समीक्षा करेंगे। जैन ने बताया कि यह बाजार के 80 साल के इतिहास में पहली बार है जब यह स्वेच्छा से बंद हो रहा है।

राजधानी के निजी व सरकारी सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया। अभी तक स्कूल छात्रों के लिए बंद थे और परीक्षाएं चल रही थीं।

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि सभी परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित की जाती हैं। स्कूल शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी बंद रहेंगे। विभाग ने कहा कि शिक्षकों को वार्षिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन का काम घर से करना होगा जबकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन का काम सीबीएसई ने निलंबित कर दिया है।

आप सरकार ने 26 मार्च को एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी की अगर कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च के बाद भी स्कूलों को बंद रखा गया तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सरकारी आदेश में कहा कि वर्तमान योजना के अनुसार, यदि स्थिति सामान्य होती है तो एक अप्रैल को स्कूल खोलेंगे और नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई-लिखाई शुरू हो जाएगी।

हालांकि, यदि 31 मार्च के बाद भी स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें एक वैकल्पिक योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि छात्रों की पढ़ाई को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

मतदाता पहचान पत्र के लिए सिर्फ ऑनलाइन करें आवेदन

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोगों से कहा कि वे मतदाताओं से संबंधित डेटा में किसी भी बदलाव के लिए मतदाता केन्द्रों पर न आकर ऑनलाइन आवेदन करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे मतदाता सूची में किसी भी बदलाव के लिए मतदाता केन्द्रों पर जाने के बजाय भारतीय चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल यय्य.तमपद.टत या मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर आनलाइन आवेदन करें।

ज्ञात हो कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना नहीं चाहती है।

सोशल मीडिया से होगी हिंसा भड़काने वालों की पहचान

● विस समिति ने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से मांगी मदद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शांति और सद्भाव के लिए विधानसभा की समिति ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से उन अपराधियों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहेगी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा की हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने हिंसा के मद्देनजर अफवाहों और भड़काऊभाषणों को फैलने से रोकने के लिए गठित की गई समिति ने 14 शिकायतकर्ताओं और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोपी एक व्यक्ति के बयान दर्ज किए।

इस समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि समिति ने उन 14 शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जिन्होंने वीडियो और संदेशों समेत भड़काऊ सामग्री की ओर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ सामग्री को साझा करने के आरोपी एक व्यक्ति को भी तलब किया गया था। इस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया है जो दंडनीय है और इसके तहत तीन साल तक की कैद हो सकती है। इस व्यक्ति ने दावा किया कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी और उसने समिति से माफी मांगी।

मां विनय को खिलाना चाहती हैं पसंदीदा पूड़ी, सब्जी व कचौड़ी

नई दिल्ली। घड़ी की सुइयों के अनवरत रूप से चलने के साथ निर्भया के दोषियों की उम्मीदें धूमिल पड़ती जा रही हैं। परिवार, मां, पत्नी बच्चे सभी निराश, हताश और परेशान दिख रहे हैं। चारों दोषियों को एक साथ शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले एक दोषी विनय की मां अपने बेटे को उसकी मनपसंद पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी खिलाना चाहती है।

विनयज की मांग ने बताया कि तिहाड़ में जेल कर्मियों ने खाना या कुछ और नहीं ले जाने दिया, लेकिन अगर वे अनुमति देंगे तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ पूड़ी, सब्जी और कचौड़ी ले जाना चाहूंगी। उसने कहा कि वह आखिरी बार अपने बेटे से जेल में जल्द ही मिलने जाएगी।

सुबह ही फांसी क्यों और कौन-कौन होता है मौजूद

● ब्लैक वॉरंट जारी होने के बाद दोषी जेल का कोई काम नहीं करता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसे लेकर समाज में हलचल और उत्सुकता होना लाजमी है। फांसी से जुड़े अनेक सवाल लोगों के जहन में आते हैं। उनमें एक सवाल यह भी होता है कि फांसी सुबह-सुबह ही क्यों दी जाती है।

जब फांसी दी जाती है तो उस समय वहां कौन-कौन लोग मौजूद होते हैं और दोषी से कौन मिल सकता है। तिहाड़ जेल सूत्रों के अनुसार फांसी वाला दिन जेल के लिए आम नहीं होता। सुबह तीन बजे से ही जेल में हलचल शुरू हो जाती है। जिसे फांसी दी जानी है और जो फांसी देगा यानी जल्लाद उसे करीब तीन-चार बजे के बीच उठा दिया जाता है।

इस बीच कैदी को नहाने और नाश्ता करने को कहा जाता है। फांसी सुबह सूरज निकलने से पहले दी जाती है। जेल फांसी की प्रक्रिया पूरी होने से पहले जेल में उस दिन कोई दूसरा काम नहीं होता। ब्लैक वॉरंट जारी होने के बाद दोषी जेल का कोई काम नहीं करता। उसे खेलने, थोड़ा घूमने या फिर पढ़ने की छूट होती है। इस दौरान भी उसपर पूरी निगरानी रहती है। वह उस केस में फांसी की सजा पाए अन्य कैदियों से मिल भी सकता है। पवन जल्लाद के अनुसार फांसी देते वक्त कैदी के हाथ पीछे बांधे जाते हैं। फिर फांसी के तख्ते के ऊपर पहुंचते ही पैर भी बांध दिए जाते हैं। जेल के नियमों के अनुसार फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले कैदी के मुंह पर काला कपड़ा पहना दिया जाता है ताकि वह फंदे को देख न पाए।

फांसी के वक्त फांसीघर में ज्यादा लोगों को नहीं रखा जाता। वहां कैदी, जल्लाद, डॉक्टर, एसडीएम, जेल सुपरिंटेंडेंट और 10 से 12 पुलिसवाले होते हैं। डॉक्टर मौत की पुष्टि करता है और वही डेथ सर्टिफिकेट जारी करता है। फांसी देने वाले दिन अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह-सुबह कैदी से उसकी कोठरी में मिलने जाते हैं।

मुझे और बेटे को भी दो फांसी : अक्षय की पत्नी

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्नी बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस अदालत के बाहर बेहोश हो गई।

उसने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए। अदालत के बाहर चीखते हुए उसने कहा कि मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे भी मार दो। मैं जीना नहीं चाहती। मेरा पति निर्दोष है। सिंह की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया। हालांकि पीड़िता के परिजन के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वकील ने कहा कि अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है। अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
उत्तर प्रदेश पुलिस

कोरोना को दबाएं
अपनी आवाज़ को नहीं

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं
न घबराएं, 112 मिलाएं,
अपना पंजीकरण कराएं

■ महिला पुलिस कर्मी घर आएंगी, आपका पंजीकरण करेंगी, हिंसक को सचेत करेंगी
■ अब हिंसा हुई तो होगी 'प्रबल प्रतिक्रिया' (enhanced response)
▪ तुरंत पुलिस के 2 वाहन आएंगे ▪ कानूनी कार्रवाई करेंगे

@112UttarPradesh +91-7570000100 @112UttarPradesh +91-7233000100

अब डर की नहीं कोई बात
जब यूपी पुलिस है आपके साथ

बाजार बंद होने की अफवाहों से सामान खरीदने उमड़े लोग

सिर्फ घरेलू सामान को ही खरीदने में लगे रहे लोग

कोरोना को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के सदर बाजार में पंसारी की दुकान पर सामान खरीदने को लगी भीड़।

कोरोना वायरस को लेकर भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। इसी भ्रम में शहर के लोग आ गए और दौड़ पड़े बाजारों में घरेलू उपयोग का सामान खरीदने को। यहां सदर बाजार में थोक-परचून की दुकानों में खूब भीड़ रही। पूछने पर लोगों ने भी कहा कि बाजार बंद होने की बात सुनी जा रही है। इसलिए वे महीनेभर का सामान खरीद रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन ने फिलहाल बाजार बंद होने जैसी किसी भी बात से इनकार किया है।

गुरुवार की सुबह जैसे ही शहर का प्रमुख सदर बाजार खुला। सदर बाजार, चूड़ी बाजार के साथ थोक के सामान की ट्रंक मार्केट खुली तो घरेलू उपयोग का सामान खरीदने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दुकानों के बाहर काफी भीड़ हो गई। लोग करीब एक माह तक का कोटा रखने के लिए सामान की पूरी सूची बनाकर आए थे। इन ग्राहकों में महिलाओं की संख्या अधिक थी। यहां न तो कोई मोलभाव करवा रहा था और न ही किसी के पास इतना समय था। दुकानदारों के पास भी इतना समय नहीं था कि वे किसी चीज के दाम ग्राहकों को बताएं। यानी दुकानों पर सामान खरीदने वालों की इतनी मारामारी रही कि न तो उन्हें सामान के दाम पूछने की सुध थी और न ही सामान मिलाने की। पर्ची के हिसाब से दुकानों के भीतर से ही सब सामान पैक करके दिया जा रहा था। सबसे अधिक भीड़ ट्रंक मार्केट की दुकानों और सदर बाजार के अंदर पंसारी की आधा दर्जन दुकानों पर थी। वहीं बाकी की घरेलू सामान की दुकानों में भी भीड़ अच्छी-खासी रही।

ग्राहकों ने भी कही बाजार बंद होने की बातें

यहां सदर बाजार में पटेल नगर से सामान खरीदकर घर जा रही **मेवा देवी** ने कहा कि बाजार बंद होने वाले हैं। कोरोना वायरस के डर से सभी परेशान हैं। इसलिए वह 15 दिन का सामान एक साथ खरीदकर ले जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने सामान खरीदा था। **नेहा देवी** ने कहा कि सभी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बाजार बंद हो रहे हैं। जो कई दिन तक नहीं खुलेंगे। परिवार बड़ा होने के चलते वह एक महीने का राशन खरीदकर ले जा रही है। **चरण सिंह मियां** वाली कॉलोनी से सामान खरीदने ट्रंक मार्केट पहुंचे थे। उनका पौने घंटे से नंबर ही नहीं आया था। उन्होंने अपनी पर्ची दुकानदार को दे रखी थी, जो कि कई पर्चियों के नीचे थी। फिर भी वे दुकान के ठीक बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी यही जानकारी दी कि बाजार बंद होने वाले हैं। इसलिए वे एक महीने का एडवांस में सामान खरीदने आए हैं।

बाकी दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा

घरेलू सामान को छोड़ दें तो यहां बाजारों में बाकी दुकानों में सन्नाटा ही पसरा रहा। इक्का-दुक्का ग्राहक ही कपड़े व अन्य सामान की दुकानों में जा रहे थे। लोगों की सबसे अधिक दिचलस्पी किरयाणा का सामान खरीदने की थी। यहां तक कि लोग मिठाई खरीदने में भी सावधानी बरत रहे थे। सदर बाजार के एक कोने डाकखाना चौक की ओर रेवाड़ी स्वीट्स है, तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद की ओर श्याम स्वीट्स है। बाजार के बीच में बसंत स्वीट्स है। इन तीनों दुकानों पर सामान्य तौर पर ग्राहकों की खूब भीड़ रहती है, लेकिन गुरुवार को यहां कम ही ग्राहक दिखाई दिए। मिठाइयां कम खरीद रहे थे।

संक्षिप्त समाचार

छह महीने से फरार चल रहा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

नूंह। जिले की पिनगवां थाना पुलिस ने छह महीने से फरार चल रहे आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान साहिद पुत्र इब्राहीम निवासी शाहचौखा के रूप में हुई है, जो करीब छह महीने से फरार चल रहा था। जिसे पिनगवां पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ इंस्पेक्टर रतन लाल की लगातार कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी रतन लाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आरोपी को अदालत ने पिओ घोषित कर दिया था। उसी दिन से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। जिसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पीओ आरोपियों के खिलाफ लगातार धर पकड़ जारी है, जितने भी आरोपी पीओ हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

सैकड़ों की संख्यां में लगे पेंशनधारकों को घर भेजा

सोहना। सोहना एसडीएम डॉ चिनार ने शहर के मुख्य डाकघर पहुंच पेंशन वितरण का कार्य तुरंत प्रभाव से रुकवाया। जहां पर 200 से 300 की संख्या में पेंशनधारक लाइन में लगे हुए थे। गुरुवार को सोहना के मुख्य डाकघर में पेंशन वितरण का कार्य शुरू किया था। जहां पर सुबह आठ बजे से पेंशनधारकों ने पेंशन लेने के लिए आना आरंभ कर दिया था। नौ बजे पेंशनधारको ने खिड़की पर लाइन लगानी शुरू कर दी। जो देखते-देखते डाक परिसर में 250 से 300 पेंशनधारक एकजुट हो गए। पेंशन कॉपी जमा कराने के लिए पेंशनधारकों में हा-हाकार मच गया। पेंशन लेने वालों में वृद्धों से लेकर विधवा महिलाएं व दिव्यांगजनों की संख्यां भारी मात्रा में थी। पेंशन वितरण की सूचना जैसे ही सोहना एसडीएम चिनार को मिली। उन्होंने तुरंत तहसीलदार को साथ लेकर डाकघर परिसर में पहुंच गई। एसडीएम ने डाकघर के मुख्य गेट पर ताला जड़वाते हुए पेंशन वितरण का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण से ठप करने के आदेश जारी कर दिए। पोस्टमास्टर को चेतावनी देते हुए अपना कार्यालय कार्य करने तक समित रहने को कहा है। पेंशन वितरण के कार्य को छोड़ अन्य कार्यों को कहा गया है।

दो गुटों के झगड़ें में बरसे ईंट-पत्थर, आठ घायल

सोहना। भोंडसी थाना के गांव बेरका में दो गुटों के बीच झगड़ें में पत्थर, ईंट बरसने तथा लाठी डंडें चलने से चार महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सोहना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां से डॉक्टरों ने एक महिला सहित तीन लोगों को गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया। बुधवार की रात करीब आठ बजे भोंडसी थाना के गांव बेरका में 14 वर्षीय किशोर अपनी परचून की दुकान के पास बैठकर खेल रहा था। उसी दौरान शराब के नशा में धुत पड़ौसी रवि वहा पर आ गया। जो 14 वर्षीय किशोर को गालियां देने लगा। जो शाम के समय मजदूरी करने के पिता को किशोर ने पड़ौसी रवि द्वारा गालियां देने की बात कही। यह मामला दोनों गुटों में बढ़ गया। जिसको लेकर जमकर तू तड़ाक हुई। किशोर के चाचा विनोद का आरोप है कि उसके ऊपर ईंट व पत्थर फेंकर हमला किया। जिसको लेकर दोनों गुटों में जमकर लाठी व डंडें चले, लेकिन पहले से ही मकानों की छत्तों पर रखें ईंट व पत्थरों को रवि गुट की महिलाओं द्वारा फेंकने का आरोप लगाया है। इस झगड़ें में दोनों पक्ष से चार महिलाएं सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का सोहना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायलों में रवि व उसकी भाभी सबसे पहले अस्पतात पहुंचे। जिन्हें डॉक्टरों ने गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद महेश, विनोद, सतबीर सिंह, सुमन, रेखा व फुलवती को भी अस्पताल में दाखिल कराया। जहा से विनोद सहित दो को गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया। भोंडसी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भारतेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक उनके पास किसी भी गुट की तरफ से शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने व जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा।

सेनिटाइजर और मास्क पर कालाबाजारी

सोहना। सोहना शहर में मेडिकल स्टोर संचालक सेनिटाइजर व मास्क पर जमकर कालाबाजारी कर रहे है। मास्क व सेनिटाइजर 100 से लेकर 120 रुपये की कालाबाजारी पर बेचे जा रहे है। बाजार में खुले मेडिकल स्टोर संचालक अब धड़ल्लें से सेनिटाइजर और मास्क पर कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमा रहे है। मेडिकल स्टोर संचालकों पर प्रत्येक ग्राहक को मास्क और सेनिटाइजर न देने का आरोप भी लग रहा है। ग्राहक योगेश का कहना है कि जो मास्क 10 रुपये का मिलता था। वह आज के समय में 30 से 40 रुपये में मिल रहा है। 20 रुपये वाला मास्क 60 से 70 और 80 रुपये ब्लैक में बेचा जा रहा है। अशोक का कहना है कि दुकानदार यह काला बाजारी भी चोरी से कर रहे है। उन्हें डर है कि कही स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी चोरी को पकड़ न ले। इसलिए सभी ग्राहक को यह सब नहीं बेचा जा रहा है। गौरव का कहना है कि जैनरिक सेनिटाइजर को तीन से पांच गुणा कीमत पर बेचा जा रहा है। जिस सेनिटाइजर की कीमत 40 रुपये है। जबकि उसके ऊपर एमआरपी 175-180 अंकित है। उसे दुकानदार ग्राहक को खुश करते हुए 150 से 160 रुपये में बेच रहा है।

सामाजिक संगठन ने 250 मास्क यात्रियों को बांटें

सोहना। सोहना के सामाजिक संगठन स्वॉशक्ति ने सामान्य बस स्टैंड पर यात्रियों को निस्वार्थ सेवा करते हुए 250 मास्क वितरण किए। मास्क वितरण करने वालों में किन्नर समाज ने भी अहम भूमिका निभाई। एक तरफकोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन और न्यायालय आए दिन नई-नई हिदायतें देते हुए लोगों की सुरक्षा में लगे है। वहीं सामाजिक संगठन भी अब आगे आने लगे है। शहर के स्वॉशक्ति सामाजिक संगठन की कार्यकर्ता महिलाओं ने सामान्य बस स्टैंड पर यात्रियों को फ्री में मास्क वितरण किए। जो शहर में स्थापित मेडिकल स्टोरों पर ब्लैकमेल के बावजूद लोगों को नहीं मिल रहे है। मास्क वितरण करने वालों में संगठन की प्रधान भावना, अधिवक्ता सीमा डागर, किन्नर समाज से सोनिया व अन्य सदस्य भी मौजूद थी। प्रधान भावना ने बताया कि मार्केट में लोगों को मास्क आसानी से नहीं मिल रहे है। यह मास्क संगठन ने अपने निजी खर्चे से खरीदें है। जो यात्रियों को वितरण करने के लिए आगे आए है। उन्होने बताया कि बस में यात्रा करने वालों को मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है।

सदर बाजार में कोरोना को लेकर किया जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के सदर बाजार में कोरोना से जागरूकता को लगाया गया बोर्ड।

कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने सभी सावधानियां बरतने का आग्रह शहरवासियों से किया है। प्रशासन ने शहरवासियों से यह आग्रह भी किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जिम्मेदार नागरिक बनकर इस आपदा का सामना करने में प्रशासन को सहयोग दें।

जिला प्रशासन की इस मुहिम में कई स्वयंसेवी संस्थाएं व बुद्धिजीवी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। शहर के व्यस्ततम सदर बाजार में गुरुवार को हाथों में कोरोना वायरस से बचाव का स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर स्वयंसेवकों ने जागरुकता अभियान भी चलाया।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। यदि जरूरी नहीं है तो 31 मार्च तक घर से बाहर न निकलें। सावधानियां ही बचाव है।

उन्होंने बाजार में आए लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि वे मास्क पहनें और सैनेटाइजर से हाथ साफ रखें, हाथ व गले मिलने को तब तक तिलांजलि दे दें, जब तक वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसी प्रकार का अभियान शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चलाया गया।

गैस एजेंसी के टैम्पो की टक्कर से बाइक सवार की मौत

गुरुग्राम। एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठे उसके साथी को गैस एजेंसी के टैम्पो चालक ने सामने से टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार युवक को अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को दी शिकायत में चांदनगर निवासी मांगेराम ने बताया कि उसका 19 वर्षीय बेटा रामनितेश बाइक से दोस्त रोहित के साथ फर्रूखनगर किसी काम से गया था। रामनितेश बाइक चला रहा था। भारत गैस गोदाम के सामने गैस एजेंसी की तरफ टैम्पो लेकर आ रहे चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक सवार घायल हो गए। रामनितेश को गुरुग्राम अस्पताल में उपचार को लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

श्रम कानूनों के उल्लंघन पर श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

कपारो मारुति प्रबंधन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के विरोध में प्रदर्शन करते श्रमिक।

कपारो मारुति प्रबंधन पर संस्थान में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने आरोप लगाए हैं कि प्रबंधन श्रम कानूनों का उल्लंघन कर उनके साथ भेदभाव की नीति अपना रही है। कई वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को न तो कानून के हिसाब से ओवर टाइम दिया जा रहा है और न ही बोनस आदि का भुगतान किया गया है।

श्रमिकों को लीव कार्ड, हाजिरी कार्ड, ईएसआई, पीएफ स्लिप आदि भी नहीं दी जाती है, जिससे श्रमिकों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर गुरुवार को श्रमिक संगठन एटक की अगुवाई में मिनी सचिवालय पर पीड़ित श्रमिक एकत्रित हुए और उन्होंने एटक के जिला प्रधान सुरेश गौड़ व महासचिव अनिल पंवार की अगुवाई में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर उपायुक्त के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही कर श्रमिकों को न्याय दिलाया जाए। अनिल पंवार ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि प्रबंधन ने संस्थान में कई श्रमिकों को बंधक बनाया हुआ है। उनको संस्थान से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। श्रमिकों से जबरदस्ती काम कराया जाता है। कोरोना वायरस का बहाना बनाकर श्रमिकों को श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाला जा रहा है। प्रबंधन नई भर्ती कर पुराने श्रमिकों से अधिक उन्हें वेतन दे रही है।

कोरोना के प्रति बचाव के उपायों पर प्रशासन प्रयासरत

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जिला में कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव उपायों के बारे में जमीनी स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि आम जनता इन बचाव उपायों को जाने और समझकर स्वयं को इस वायरस संक्रमण से बचा सके।

उपायुक्त अमित खत्री ने गुरुवार को जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सिंह व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान को ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस को जिला में फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि आम जनता को बचाव उपायों के बारे मे जागरूक किया जाए, क्योंकि उपचार से बेहतर बचाव है। उन्होंने कहा कि सभी जागरूक होकर सावधानी बरतेंगे, तो इस वायरस के प्रसार को हम रोक सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से गुरुग्राम की सभी ग्राम पंचायतों में मुनादी करवाई जाएगी और कोरोना वायरस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी डूज एंड डोंट्स यानी करने योग्य एवं न करने योग्य कार्यों के बारे में पोस्टर, फ्लैक्स आदि डिस्पले सामग्री से ग्रामीणों को अवगत करवाया जाएगा। इसी प्रकार जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे नियुक्त राजस्व विभाग के अमले का इस प्रचार में सहयोग लिया जाएगा।

संक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम की

शहरी क्षेत्र में जगहों को सेनिटाइज या डिसइंफेक्ट करने अथवा संक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निभाई जा रही है। लघु सचिवालय में भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव उपायों के बारे में स्टैंडीज तथा प्रचार सामग्री डिस्पले की गई है, ताकि यहां आने वाले लोगों को इन उपायों की जानकारी मिल सके। यही नहीं कंस्ट्रक्शन वर्करों को इन उपायों के बारे में अवगत करवाने के बारे में श्रम विभाग तथा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला में अन्य बिल्डर अथवा डेवेलेपर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंगों में लगे श्रमिकों तथा कारीगरों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

रोडवेज बसों में नियमित स्प्रे करवा रहे

अमित खत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन के तहत चलाई जा रही रोडवेज बसों को प्रतिदिन नियमित रूप से संक्रमण मुक्त करने के लिए उनमें स्प्रे करवाया जा रहा है। यही नहीं अब बसों में बचाव उपायों अथवा डूज एंड डोंट्स को चस्पा करवाया जाएगा, ताकि उनमें सफर करने वाली सवारियों को इन उपायों की जानकारी हो सके। इसी प्रकार रेलवे में सावधानियां बरतने के लिए रेल मंत्रालय के गुरुग्राम में नियुक्त स्टेशन अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। मैट्रो स्टेशन तथा मेट्रो के अंदर डी-कंटेमिनेशन कार्य करवाने के लिए संबंधित एजेंसियों को हिदायत दी गई हैं।

जिला में मास्क, सेनिटाइजर हैं पर्याप्त, घबराने की जरूरत नहीं

बिना संक्रमित व्यक्ति को मास्क की जरूरत नहीं

गुरुग्राम। जिला में फेस मास्क तथा हैंड सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके लिए जिलावासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से यह भी कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव उपायों के प्रति हर व्यक्ति को सजग रहने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को फेस मास्क लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है।

फेस मास्क वही व्यक्ति लगाए जो खांसी या जुकाम से पीड़ित हो। इस बारे में बुधवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी जानकारी दे चुके हैं। फिर भी गुरुग्राम जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर जरूरतमंद को फेस मास्क तथा हैंड सेनिटाइजर वाजिब दामों पर उपलब्ध हों। इस दिशा में जिला प्रशासन तथा ड्रग कंट्रोल अधिकारी की टीम पूरी तरह से सतर्क है। बुधवार रात्रि को प्रशासन को सूचना मिली कि मानेसर में काफी संख्या में मास्क किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध है, तो टीम ने उस स्थान का निरीक्षण किया और वहां पर औद्योगिक उद्देश्य के लिए लाए गए लगभग 4300 फेस मास्क पाए गए। इस टीम ने उस डिस्ट्रीब्यूटर को ये सभी मास्क गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल को अपनी खरीद कीमत पर देने के लिए राजी कर लिया और सभी 4300 मास्क नागरिक अस्पताल को मिल गए हैं। ड्रग कंट्रोल अधिकारी अमनदीप चैहान के अनुसार ये मास्क स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ को दिए जाएंगे।

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से...

कोरोना वायरस के दौर में बशीर बद्र का शेर हो रहा सार्थक

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के लघु सचिवालय स्थित कार्यालयों में कोरोना वायरस से बचाव को हाथ न मिलाकर हाथ जोड़कर अभिवादन करने का लगाया गया नोटिस।

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो...। उर्दू शायरी में बड़ा नाम बशीर बद्र का किसी जमाने में लिखा यह शेर आज सटीक बैठ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लोगों के बदले व्यवहार ने इस शेर को सार्थक कर दिखाया है। पहले लोग गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। आज इन दोनों से ही परहेज कर रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रमाण करके अभिवादन करने लगे हैं। लोगों का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है।

देसी और विदेशियों में गले मिलकर स्वागत करने की परम्परा को कोरोना वायरस का ग्रहण लग गया है। वैसे भारत की परम्परा हाथ जोड़कर प्रणाम, स्वागत करने की रही है। पौराणिक समय में गुरुकुलों में गुरुओं, शिक्षकों द्वारा अपने शिष्यों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा करना संस्कारों में प्रमुख होता था। समय के साथ इस परम्परा को जाले लगते गए और कब यह परम्परा लुप्त हो गई, पता ही नहीं चला।

हाथ जोड़ने की बजाय लोग एक-दूसरे को गले लगाकर, हाथ मिलाकर मिलने लगे। स्वागत करने लगे। वर्षों पूर्व समाज की कुछ बातों, घटनाओं को कवियों, शायरों, साहित्यकारों ने अपनी कलम से लिखा था, वह आज कहीं न कहीं सत्य साबित हो रही हैं। यहां तक कि पुराने समय में बनी फिल्में भी हमारे आज के समाज पर, व्यवहार पर सटीक बैठ रही हैं। बशीर बद्र के शेर की तरह फिल्म साकी का एक गीत है-पास नहीं आइए-हाथ ना लगाइए, लीजिए नजारा दूर-दूर से, कीजिए इशारा दूर-दूर से...।

यह गीत भी ऐसे लगता है जैसे कि आज के हालातों के लिए गाया गया हो। आज हालात ऐसे ही हो चुके हैं। हालांकि फिल्म में इसके मायने अलग हैं। तपाक से गले मिलने वालों से आज कोई गले नहीं मिल रहा और न ही हाथ मिल रहा है। हाथ जोड़कर प्रणाम की संस्कृति को लोग अपनाने लगे हैं।

भारतीय संस्कृति के हैं साइंटिफिक रीजन

कोरोना वायरस ने गले मिलने वालों में दूरियां बना दी हैं। एक-दूसरे से हाथ मिलाने वालों को दोनों हाथ जोड़ने को मजबूर कर दिया है। लोग हाय, हेलो को भूलकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में आ चुके हैं। अमेरिका जैसी सुपरपावर के राष्ट्रपति भी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति भी अब लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। वे भी हाथ मिलाने, गले मिलने की पाश्चात्य संस्कृति (वेस्टर्न कल्चर) को पीछे छोड़ चुके हैं। हाथ जोड़ने, पैर छूने की भारतीय संस्कृति सिर्फ एक परम्परा नहीं है, बल्कि इसके साइंटिफिक रीजन) वैज्ञानिक कारण भी हैं। हालांकि हमारे ग्रामीण अंचल में आज भी राम-राम करने की संस्कृति काफी हद तक जिंदा है।

नई पीढ़ी को देना होगा संस्कृति का ज्ञान

आज पैरेंट्स अपने बच्चों की सफलता अच्छी अंग्रेजी बोलने, वेस्टर्न कल्चर में ढल जाने को मानते हैं, लेकिन वे गलत हैं। उनकी इस सोच से समाज में पाश्चात्य संस्कृति (वेस्टर्न कल्चर) हावी हो गई है। वे अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। घर के अधेड़, बुजुर्ग आज की युवा पीढ़ी को बोझ लग रहे हैं। देश में अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब साफ है कि वेस्टर्न कल्चर में डूबी आज की पीढ़ी को अपने मां-बाप, दादा-दादी स्टेट्स के हिसाब से जम नहीं रहे।

अब वृद्धाश्रमों, अनाथालयों की भीड़ करें कम

एक बीमारी क्या आई, सबको अपनी संस्कृति समझ आ गई कि हाथ मिलाने में नहीं, हाथ जोड़ने में ही भलाई है। इस हाथ जोड़ने की संस्कृति, परम्परा के साथ अब समय आ गया है अपने-अपने बुजुर्गों को सहारा देकर वृद्धाश्रमों, अनाथालयों से भीड़ कम करने का। हमें अच्छी सीख लेकर घर, परिवार, समाज में एक-दूसरे के सुखों के साथ दुखों को भी सांझा करना चाहिए। यह कड़वी सच्चाई है कि कुछ समय पूर्व जो देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे। एक-दूसरे को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे, आज उन परमाणु शक्तियों को बीमारी के रूप में आए एक वायरस ने हिला कर रख दिया है। इसलिए जिन्दगी को आनंद से जिएं। ठीक उसी तरह, जिस तरह फिल्म आनंद में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना कहते हैं-बाबू मोशाय...जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।

कोरोना वायरस के बीच घरेलू कामगारों ने स्वास्थ्य पर जताई चिंता

गुरुग्राम। घरेलू कामगार यूनियन (जीकेयू) ने कोरोना बीमारी के बीच हजारों घरेलू कामगारों के स्वास्थ्य के लिए कोई भी इंतजाम न होने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा है कि प्रशासन इस क्षेत्र में काम करने वालों की भी चिंता करे, ताकि उनका इस बीमारी से बचाव किया जा सके।

घरेलू कामगार यूनियन के संयोजक डॉ. माया जॉन के मुताबिक गुरुग्राम प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदमों का अभी तक अभाव है। सरकार द्वारा यात्रा प्रतिबंध के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार ने जनता के बड़े हिस्से, सामान्य श्रमजीवी जनता जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसे घरेलू कामगार के स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा को एकदम नजरअंदाज कर दिया है। कोरोना के फैलाव के संबंध में जाने-माने चिकित्सकों का कहना है कि इसका फैलाव दर्ज हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। इसलिए इलाज की सुविधाओं और अस्पतालों की कमी के कारण सामान्य गरीब जनता के जीवन पर इस बीमारी का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है।

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि एम्ब्रिओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्राण्ड नाम इंटरनैशनल फर्टिलिटी सेन्टर से बदल कर आरआईएसएए आईवीएफ पता एच-6, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016 कर लिया है। इंटरनैशनल फर्टिलिटी सेन्टर अब आरआईएसएए आईवीएफ के नाम से जाना जाएगा।

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Bihari Lal, S/o Sh. Nathu Ram, R/o H.No.B-203, Gali No.2, Mukund Vihar, Karawal Nagar, North-East, Delhi-110094 has severed his relations with his son Jitender & Dharmender and their respective wives and debarred him from all movable-immovable properties due to their misconduct towards my clients. Anybody deals with them shall do at his/her own risk, cost & consequences. My client shall not be responsible for their any acts.

Aknit Srivastava (Advocate)
G-521, 5th Floor, G-Block, Lawyers Chamber Block, Karkardooma Courts, Delhi-110032
Mob: 9811294368

सार्वजनिक सूचना

ललित कुमार (लोकस कंसल्टिंग) के प्राधिकार-पत्र के समापन की सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि श्री ललित कुमार (लोकस कंसल्टिंग) को जारी किया गया प्राधिकार-पत्र दिनांक 01.02.2020 को दिनांक 03.03.2020 से प्रभावी इम्प्रेषन्स सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उनके पास अब किसी भी व्यक्ति से किसी भी क्षमता या पद्धति में कम्पनी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और उनके साथ कोई भी लेनदेन स्वयं अपने जोखिम एवं दायित्व पर होगा और कम्पनी उपरोक्त कथित श्री ललित कुमार द्वारा किये गये किसी भी कार्य प्रतिबद्धता, मौद्रिक लेनदेन या डील के लिए किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं होगी।

कृते इम्प्रेषन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(अमर पौल सिंह) उपाध्यक्ष (स्ट्रेटिजी)
प्लॉट नं. 603-604, उद्योग विहार फेज-5, गुरुग्राम-122016, हरियाणा

फटाफट खबरें

क्षयरोग जागरूकता शुरू

फरीदाबाद। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एडीशनल एसएमओं डॉ. एके यादव ने बृहस्पतिवार को जागरूकता एम्बुलैंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसके बारे में बताया कि यह एम्बुलैंस विश्व क्षयरोग दिवस तक लोगों को जागरूक करेंगी। बृहस्पतिवार को हरी झंडी दिखाकर एम्बुलैंस को रवाना करने के मौके पर डॉ. एके यादव के अलावा क्षयरोग जांच केन्द्र से चंचल, विजय और पवन के अलावा अन्य स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि यह एम्बुलैंस स्वास्थ्य केन्द्र और बल्लभगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षयरोग के प्रति जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा कि इस वैन में क्षयरोग विभाग से एक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर व एक लेबोरेटरी सुपरवाइजर तैनात रहेगा, जो लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे।

शातिर झपटमार व चोर गिरफ्तार

फरीदाबाद। झपटमारी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को अपराध शाखा सेक्टर 85 की टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीन वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। इसके अलावा दो चोरी करने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता सुबेसिंह के मुताबिक एनआईटी इलाके में रहने वाला भूपेंद्र काफी समय से लूटपाट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गतदिवस अपराध शाखा सेक्टर 85 को सूचना मिली कि भूपेंद्र फिलहाल गुरूग्राम में वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। अपराध शाखा की टीम ने घेराबंदी कर तुरंत आरोपी को दबोच लिया और यहां ले आए। अपराध शाखा प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी नवीन के साथ मिलकर इन वारदातों का अंजाम देता है। उनके खिलाफ फरीदाबाद और गुरूग्राम में कई मामले दर्ज हैं। नवीन फिलहाल नीमका जेल में बंद है। आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन, मोबाइल फोन और देशी पिस्तौल बरामद की है। इसके अलावा अपराध शाखा ने चोरी के मामले में बदरपुर दिल्ली निवासी अजित और स्वर्ण को गिरफ्तार किया है।

फैली झूठी अफवाह

फरीदाबाद। सूचना आई थी कि नीलम बाटा रोड़ स्थित एचडीबीआई बैंक में कैशियर को बुखार होने पर बैंक को पूरी तरह से बंद होने की सूचना आई थी। इस विषय में जब वहां के निवासियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कर्मचारी को मामूली बुखार था। जिस पर उसकी जांच की गई है, उसकी जांच रिपोर्ट कल आऐगी। वहीं दुसरी तरफ उन्होंने कहा कि बैंक को बंद नहीं किया गया है। वही दुसरी तरफ वहां के निवासियों ने कहा कि कैशियर के कारण आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों में पब्लिक डिलिंग का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल कर्मचारियों व अधिकारियों को फाईनेंस का काम जारी करने के निर्देश दिए है। कैशियर को बुखार था। उसे इलाज के लिए घर भेजा था। यूको बैंक एम्पलाइजर यूनियन के नॉदन जोन के जोइंट सेकेट्री बीआर सिंगला से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बैंकों में पब्लिक डिलिंग को बंद करने का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। यह केवल अफवाह उड़ाई जा रही है।

तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

फरीदाबाद। किसान सभा के बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उन्होंने पिछले दिनों हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। ज्ञापन में किसानों की बर्बाद हुई फसल की विशेष गिरदावरी करने की मांग की गई। ज्ञापन देने के अवसर पर किसान सभा के प्रधान नवल सिंह, सीटू के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल, मोहना गांव के किसान नेता देवी सिंह अत्री, एवं बुखार पुर के किसान नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बे मौसमी बारिश और तेज आंधी तूफान एवं भयंकर ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अभी तक किसानों की फसल की गिरदावरी नहीं की गई है । किसान परेशान हैं उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बर्बादी से बचाने के लिए किसानों की फसलों की तत्काल गिरदावरी आरंभ करके उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए।

कोरोना को लेकर सर्तक हुआ विभाग,जारी किए छह नम्बर

विदेशों से लौटे 15 नए लोग बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आए हैं

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

लोग अस्पतालों के चक्कर काटने से बचें व अस्पताल में आने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक जरूरी कदम उठाया है। जिसके तहत बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग ने छह चिकित्सकों के मोबाइल नम्बर उनके फोटो के साथ जारी किए हैं। लोग इन डॉक्टरों से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर अपनी बीमारी के बारे में बातचीत कर सकते है। इस बारे में डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉ. मोहित अग्रवाल से 9999907640, डॉ. विकास गोयल से 9891425930, डॉ. एसएस दहिया 9818672032, डॉ. प्रवीन अरोड़ा से 8076297718, डॉ. ऋषिराज गौतम से 9416352200, डॉ. जयसिंह देशवाल के नंबर 8572010083 जारी किए हैं।

15 नए लोगों की जांच शुरू

कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी सर्तकता बरते हुए हैं। विदेशों से लौटे 15 नए लोग बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आए हैं, जिनकी स्क्रिनिंग का काम स्वास्थ्य विभाग ने पूरा कर लिया है। अब इन पर अगले 28 दिन तक निगरानी रखी जाएगी। अब तक जिले में 185 ऐसे लोग हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने नजर रखी हुई है। इनमें 25 गुड़गांव स्थित पेटीएम कंपनी में काम करने वाले लोग हैं और बाकी विदेशों से लौटे हुए लोग हैं। बुधवार तक इन लोगों की संख्या 170 थी। गुरुवार को 15 नए लोग स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आए हैं, जिनकी स्क्रिनिंग की गई। इनमें से किसी में भी कोरोना का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। 185 में से 24 लोग ऐसे हैं, जिनका कोरंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है।

उसके बाद भी इनके स्वास्थ्य का हाल लगातार लिया जा रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत ने बताया कि अभी तक जिले में किसी भी व्यक्ति में कोरोना की पुष्टी नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लोगों को साफ-सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम व सर्दी की समस्या है, वह मास्क का इस्तेमाल करें। बार - बार हाथ साफ करें। साबुन आदि से कम से कम 20 सैकेंड तक हाथ साफ करें।

हमलावरों की गिरफ्तारी को नोएडा पुलिस ने डेरा डाला

फरीदाबाद। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं ओमैक्स हाइट्स सोसायटी निवासी पंकज विश्वामित्र पर 12 मार्च को नोएडा में हुए जानलेवा हमले मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस ने डेरा डाल दिया है। नोएडा के सेक्टर-58 थाने में फरीदाबाद गांव चंदीला बड़ौली, बुढैना के कई युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज है। अब तक फरीदाबाद पुलिस ही आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर रही थी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। अब नोएडा पुलिस ने डेरा डाल लिया है। बुधवार को भी नोएडा पुलिस की टीमें गांव बड़ौली व बुढ़ैना पहुंची। नोएडा पुलिस का कहना है कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ओमैक्स हाइट्स सोसायटी में रखरखाव का जिम्मा आरडब्ल्यूए के हाथ ही होता है। आरडब्ल्यूए में जिम, सुरक्षा, साफ-सफाई के लिए आरडब्ल्यूए ठेका छोड़ती है। यह ठेका लाखों का होता है। कुछ स्थानीय लोगों ने ये ठेके हासिल कर सोसायटी में पैठ बना ली थी। उनके बाउंसर सरेआम लोगों को धमकाते थे, युवती व महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे।

झुग्गियों में कैम्प लगाकर जांच करते दो गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

स्लम इलाके में कैम्प लगाकर लोगों की जांच कर उन्हें अवैध रूप से दवाईयां देने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो फर्जी लोगों को पकड़ा है। सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओं डॉ. मान सिंह और डॉ. एके यादव ने इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस विषय में डॉ. एके यादव ने बताया कि एमएमओं डॉ. मान सिंह को सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध कैम्प लगाकर लोगों की जांच करके दवाईयां दे रहे है। जिस पर वह दोनों मौके पर पहुंचे तो वहां कैम्प में कुछ आरोपी एचबी, शुगर, चश्मे का नम्बर, वजन की जांच कर रहे थे। जब टीम ने उनसे पुछताछ शुरू की, तो कुछ मौके से भाग निकले। लेकिन दो को उन्होंने पकड़ लिया और पुछताछ शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी। सेक्टर-सात पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पकड़े गए आरोपी महेश और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुछताछ में आरोपी ने खुद को बीएससी की डिग्री धारक बताया। उनके कब्जे से कुछ अपात्तिजनक सामान और अंग्रेजी दवाईयां, एंटी बायटिक्स, आई ड्राप्स पकड़ी है। उन्होंने दवाईयों को सील कर दिया और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। डॉ. मान सिंह ने बताया कि आरोपी स्लम इलाकों में जाकर भोली भाली जनता को ठगने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा। ताकि झोलाझाप व ठगी करने वाले चिकित्सकों पर पाबंदी लग सके।

एचएसईबी वर्कर यूनियन ने की नारेबाजी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सबडिवीजन इंडस्ट्रियल एरिया सबअर्बन सेक्टर-58 बल्लभगढ़ पर कर्मचारियों ने एकत्र होकर बिजली निगम बल्लभगढ़ के एक्शन व एसडीओ के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एचएसईबी वर्कर यूनियन के बैनरतले सबयूनिट सचिव अशोक लाम्बा की अध्यक्षता में जोरदार नारेबाजी की। जिसमे सबडिवीजन के सभी बिजली कर्मचारियों ने काम काज ठप्प कर निगम अधिकारियों के अड़ियल रविये के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। सबडिवीजन के प्रधान सत्यप्रकाश चौहान ने निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके दफ्तर के दो आउटसोर्स सहायक लाइनमैन कर्मियों को बाहर करने का जो फरमान एक्शन बल्लभगढ़ दवारा जारी किया गया है। वह सरासर बेबुनियादी और भेदभाव की नीति से जारी किया है। प्रदर्शन के इस मौके पर यूनिट प्रधान कर्मवीर यादव ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में बिजली कर्मचारीयों के हितों की रक्षा करने वाली हमारी एचएसईबी वर्कर्स यूनियन इसे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नही करेगी और इसके लिये ऐसे द्वेषपूर्ण आदेशों की खिलाफत में अपना भारी विरोध दर्ज कराती है और जब तक अपने इन साथियों को निकाले जाने के फरमान को एक्शन बल्लभगढ़ द्वारा वापिस या निरस्त नही किया जाता है। तब तक हरएक बिजली कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कर ऐसे अड़ियल अफसरों के खिलाफ रोष प्रकट करेगा।

कोरोना से बचाव को हैंडवॉस और सेनेटाइज

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सेक्टर-24 स्थित स्लेजहैमर कम्पनी में कोरोना को लेकर जहां एक तरफ जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बचाव के लिए कम्पनी प्रबंधन की तरफ से सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

कम्पनी के एमडी प्रदीप मोहंती के दिशा निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। जिसके तहत बृहस्पतिवार से कम्पनी में सभी कर्मचारियों के हाथ साबुन से धुलवाकर उन्हें सेनेटाइजर से साफ करवाने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है।

वहीं पूरी कम्पनी के हर कोने में इस वायरस से बचाव के लिए सेनेटाइज किया जा रहा है। कम्पनी के सभी कर्मचारियों को सुरक्षा बरतने की सलाह के साथ मास्क भी बांटे गए। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें बुख़ार हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो वह अवकाश लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाये। वहीं दुसरी तरफ डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को भी फोलो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नियमित रूप से अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। खांसते अथवा छींकते वक्त मुंह को ढंक कर रखना चाहिए। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी कार्यालय का किया दौरा

फरीदाबाद। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ की मनोनीत वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता द्वारा चंडीगढ़ में अपने पद का कार्यभार संभालने के बाद वीरवार को प्रथम दौरा सेक्टर-12 स्थित जिला रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यालय का किया गया। इस अवसर पर सुषमा गुप्ता का जिला रेडक्रॉस सचिव विकास कुमार, डॉ. एमपी सिंह (विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन), सहसचिव बिजेंद्र सौरोत, जिला प्रशिक्षण अधिकारी इशांक कौशिक, सहायक पुरुषोत्तम सैनी, उपसंरक्षक बीरेंद्र गौड़, सर्व मास्टर ट्रेनर दर्शन भाटिया तथा स्वावलंबन ट्रस्ट की अध्यक्ष मेघना श्रीवास्तव सहित कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि नव मनोनीत हरियाणा वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता फरीदाबाद जिला रेडक्रॉस सोसायटी से वर्षों से जुडी हुई है और रेडक्रॉस के विभिन प्रोजेक्ट्स में कार्यकारणी सदस्य के रूप में कार्य करती रही हैं। इससे पहले वे हरियाणा राज्य कार्यकारणी की सदस्य रही हैं। इस मौके पर थैलेसीमियाग्रस्त लोगों के लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुषमा गुप्ता द्वारा किया गया। उनके द्वारा रेडक्रॉस के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं की एक मीटिंग ली गई, जिसमें जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव विकास कुमार के साथ सभी ने इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार फरीदाबाद रेडक्रॉस की गतिविधियों को और अच्छे तरीके से चलाया जाए। सुषमा गुप्ता द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि फरीदाबाद रेडक्रॉस द्वारा संचालित प्रोजेक्टों और गतिविधियों को और बेहतर ढंग से चलाने में वे पूर्ण सहयोग करेंगी। इस मौके पर सुषमा गुप्ता ने करोना वायरस के चलते लोगों को जागरूक किया।

पार्टनर बनाने का झांसा देकर ठगे तीन करोड़

फरीदाबाद। एक नामी गरामी कंपनी में पार्टनर बनाने का झांसा देकर सेक्टर 15 निवासी एक महिला से चार लोगों ने तीन करोड़ छह लाख रुपये ठग लिए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-15 निवासी शशि खुराना ने बताया कि वर्ष 2015 में बीमारी से उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके पति रबड़ का कारोबार करते थे। शशि कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। पति के जानकार कंवरजीत ने शशि से कहा कि वह उनके कारोबार को संभाल लेगा। शशि उसकी बातों में आ गईं। कंवरजीत ने शशि को बताया कि वह सरकारी कंस्ट्रक्शन के ठेके लेता है। उसने शशि को ऑफर दिया कि अगर वे उनकी कंपनी में निवेश करेंगी तो वह हर महीने उन्हें मोटा मुनाफा देता रहेगा। उसने तीन-चार करोड़ रुपये निवेश करने की बात कही। शशि उस पर भरोसा करती थीं, इसलिए तीन करोड़ रुपये निवेश कर दिए। आरोप है कि 27 मार्च 2019 को कंवरजीत, उसकी पत्नी तथा बेटे ने शशि और उसके बेटों को आफिस में आने से रोक दिया। जब उसने कंवरजीत से अपना पैसा और मुनाफा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है मामले की जांच की जा रही है

परीक्षाएं की रद्द, लेकिन खुले रहे स्कूल

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने गत 15 मार्च से शुरू हुई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जहां दसवीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। वहीं दुसरी तरफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने गत 15 मार्च से शुरू हुई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाकर स्कूल 19 मार्च को भी खुले। नहर पार के स्कूलों में शिक्षा विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया।

केन्द्र सरकार ने सीबीएसईकी 10वीं और 12वीं की सभी बोर्ड परीक्षाएं जो 19 मार्च से 31 मार्च, 2020 के मध्य होनी थीं, उन्हें स्थगित करने की घोषणा की है। परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा 31 मार्च, 2020 या स्थिति सुधरने तक घोषित कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उत्तरी दिल्ली में दंगों के कारण रद्द हुई परीक्षाओं की दुबारा उपरोक्त तिथियों के बीच होने वाली परीक्षाएं भी अगली सूचना तक रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपियों के जांच के कार्य को भी 31 मार्च, 2020 तक फिलहाल रोक दिया गया है।

देरी व सही जानकारी न देने पर प्रदूषण अधिकारी पर जुर्माना

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

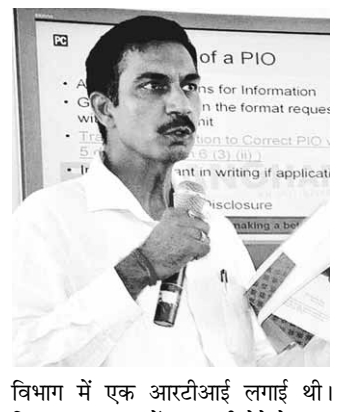

राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने गत 12 मार्च को उपायुक्त कार्यालय में मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित जिला क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी सुनीता कनोडिया, दिनेश कुमार व विजय चौधरी को अपील करता एक संघर्ष संस्था के अध्यक्ष अजय बहल को सही व पूर्ण जानकारी आगामी सात दिनों में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी की थी। इस सुनवाई में मामले में देरी व सही जानकारी उपलब्ध कराए जाने के लिए विजय चौधरी पर 10 हजार रुपये और जय भगवान, पूर्व कालीन जन सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर अपील कर्ता अजय बहल को क्षतिपूर्ति देने के आदेश किए यह आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सचिव को जारी किए गए हैं।

यह है मामला

अजय बहल ने जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर जन सूचना के अधिकार के तहत जिले में चल रहे विभिन्न वाहन रखरखाव, कार्यशाला, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को जानने के लिए व इनके द्वारा किए जा रहे प्रदूषण की जानकारी बारे जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग में एक आरटीआई लगाई थी। विभाग द्वारा शुरू में जानकारी देने के नाम पर टाल मटोल किया जाता रहा।

लेकि बाद जानकारी दी भी तो पूरी तरह सही नहीं थी।

जिसके कारण अजय बहल अपील में चले गए। अपील के दौरान हुई में लंबे समय तक सही वह पूर्ण जानकारी न मिलने पर राज्य सूचना आयोग हरियाणा में द्वितीय अपील दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा गत 24 जुलाई 2019 को व 18 दिसंबर 2019 को पहले ही विभाग के जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च 2020 को चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है।

पार्टनर बनाने का झांसा देकर ठगे तीन

फरीदाबाद। एक नामी गरामी कंपनी में पार्टनर बनाने का झांसा देकर सेक्टर 15 निवासी एक महिला से चार लोगों ने तीन करोड़ छह लाख रुपये ठग लिए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक सेक्टर-15 निवासी शशि खुराना ने बताया कि वर्ष 2015 में बीमारी से उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके पति रबड़ का कारोबार करते थे। शशि कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। पति के जानकार कंवरजीत ने शशि से कहा कि वह उनके कारोबार को संभाल लेगा।

शशि उसकी बातों में आ गईं। कंवरजीत ने शशि को बताया कि वह सरकारी कंस्ट्रक्शन के ठेके लेता है। उसने शशि को ऑफर दिया कि अगर वे उनकी कंपनी में निवेश करेंगी तो वह हर महीने उन्हें मोटा मुनाफा देता रहेगा। उसने तीन-चार करोड़ रुपये निवेश करने की बात कही। शशि उस पर भरोसा करती थीं, इसलिए तीन करोड़ रुपये निवेश कर दिए। आरोप है कि 27 मार्च 2019 को कंवरजीत, उसकी पत्नी तथा बेटे ने शशि और उसके बेटों को आफिस में आने से रोक दिया। जब उसने कंवरजीत से अपना पैसा और मुनाफा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है मामले की जांच की जा रही है

जेसी बोस विश्वविद्यालय आज से पूर्णत: बंद

विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्गों पर थर्मल स्कैनर भी लगाए जाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

वाईएमसीए स्थित जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2020 तक विश्वविद्यालय परिसर को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उचित सफाई और सैनिटाइजिंग की जायेगी। साथ ही, विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्गों पर थर्मल स्कैनर भी लगाए जाएंगे।

इस आशय का निर्णय कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा नॉवेल कोरोनावायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न एहतियाती कदमों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्णय लिये गये। बैठक में कुलसचिव डॉ. एसके गर्ग, सभी डीन, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम के दृष्टिगत विश्वविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 तक कक्षाएं पहले ही स्थगित कर दी है। सभी छात्रावासों को खाली करवा लिया गया है। इस दौरान होने वाली सभी परीक्षाओं और शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों को रद्द अथवा स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों की समीक्षा करते हुए कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने अधिकारियों को परिसर में सभी प्रकार की पब्लिक डीलिंग को प्रतिबंधित करने और कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उचित सफाई और सेनिटाइजिंग करने के निर्देश दिये। कुलपति ने विश्वविद्यालय को पूर्णत: बंद करने का निर्देश देते हुए विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुक्सान न हो। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री और असाइनमेंट के ई-संसाधन उपलब्ध करवाये और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहे ताकि विद्यार्थी अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछ सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके।

प्रशासनिक कार्यों के लिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय भी लिया गया कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विभागाध्यक्षों द्वारा आवश्यकता अनुसार बुलाया जा सकता है।

अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों को लेकर राज्यसभा में जताई गई चिंता

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों को लेकर चिंता जताई और आम लोगों को जल्द तथा वहनीय न्याय मुहैया कराने की जरूरत पर बल दिया।

सदस्यों ने अदालतों खासकर निचली अदालतों के आधारभूत ढांचे में सुधार की भी मांग की। ए सदस्य विधि एवं न्याय मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग ले रहे थे। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी को ढंग से न्याय मिल सके इसलिए सरकार मुकदमों के लिए अच्छी नीति लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकतर मुकदमों में सरकार एक पक्ष है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी की न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्याय मित्र और ई पोर्टल जैसी पहल की गई हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अपनी वेबसाइट के जरिए अपने निर्णयों को देश की छह-सात भाषाओं में उपलब्ध कराने की पहल की है। उन्होंने कहा कि विधि मंत्रालय के समक्ष एक बड़ी समस्या न्यायिक आधारभूत ढांचे की है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.8 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत न्याय प्रदान करने के तंत्र पर खर्च किया जा रहा है।

न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के प्रतिबद्ध होने को दावा करते हुए यादव ने अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को लेकर चिंता जताई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यादव ने एक देश, एक चुनाव को देश के विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों के लिए अलग अलग मतदाता सूची होती है। इससे मतदाताओं के नामों में दोहराव की समस्या भी आती है। उन्होंने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का सुझाव दिया। कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने इस मंत्रालय के बजटीय आवंटन का पूरा उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने अदालतों में बुनियादी ढांचे का पर्याप्त विकास किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि कई अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं हैं। उन्होंने मौजूदा तंत्र को दुरूस्त करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कानून बना दिए गए हैं। लेकिन उनके लिए विशेष अदालतों की कमी है।

बीजद के प्रसन्न आचार्य ने अदालतों में दशकों से मामलों के लंबित होने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब आरोपी लंबे समय तक जेल में रहा लेकिन अंतत: लंबी सुनवाई के बाद उसे रिहा कर दिया गया। आचार्य ने अदालतों में बड़ी संख्या में रिक्तियों होने पर चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि अदालतों में इतनी छुट्टियां क्यों होती है। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल किया और कहा कि दुनिया में कहीं भी न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि ओड़िशा सहित कई राज्यों में उच्च न्यायालयों की पीठें स्थापित किए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है। चर्चा में भाग लेते हुए अन्नाद्रमुक के एस आर बालासुब्रमण्यम ने भी अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक बजटीय आवंटन किए जाने की मांग की।

जापान के पास खड़े जहाज पर पॉजिटिव पाए गए 16 भारतीय इलाज के बाद घर लौटे

नई दिल्ली (भाषा)। जापान तट पर खड़े जहाज में सवार और कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में शामिल 16 भारतीय नागरिक उसी देश में चिकित्सा संस्थान में इलाज के बाद भारत लौट चुके हैं। सरकार ने गुरूवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने सदन को बताया कि डायमंड प्रिंसेज क्रूज पोत पर चालक दल के 132 सदस्यों सहित 138 भारतीय सवार थे। इनमें से 119 भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया की विशेष उड़ान से 27 फरवरी 2020 को निकाल लिया गया। लौटने के बाद उन्हें हरियाणा के मानेसर में भारतीय सैन्य केंद्र में पृथक रखा गया था।

फ्लाइट अटेंडेंट और ग्राउंड स्टाफ, कोलकाता के एन.एस.सी.वी.आई एयरपोर्ट पर गुरुवार को कोरोनवायरस (कोविड-19) महामारी के मद्देनजर सुरक्षात्मक फेस मास्क पहने हुए

रेलवे ने 31 मार्च तक 84 और ट्रेनों को किया रद्द

भाषा। नई दिल्ली

रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे और यात्रियों की कम संख्या के कारण बृहस्पतिवार को 84 और ट्रेनों को रद्द कर दिया जो 20 से 31 मार्च के बीच नहीं चलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही रद्द ट्रेनों की कुल संख्या 155 पर पहुंच गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया जाना था उनकी पहचान कल रात कर ली गई और यह फैसला 20 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा। इन ट्रेनों में आईआरसीटीसी संचालित दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और एक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया, इन 155 ट्रेनों में टिकट कराने वाले सभी यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सूचित किया जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने पर लगने वाला शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यात्रियों को 100 प्रतिशत किराया वापस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक विशेष ट्रेनों जैसे कि महाराजा, बुद्धिस्ट, भारत दर्शन और राज्य विशेष ट्रेनों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। मुंबई-अहमदाबाद और नई दिल्ली-लखनऊ के बीच तेजस सेवाओं और इंदौर-वाराणसी के बीच हाल ही में शुरू हमसफर सेवा को रद्द करने का फैसला बुधवार रात को लिया गया। राष्ट्रीय परिवाहक ने अपने कैटरिंग कर्मचारियों के लिए जोनल मुख्यालयों को दिशा निर्देश भी जारी किए थे जिसमें कहा गया कि बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में मुश्किल होने की शिकायत करने वाले किसी भी कर्मचारी को भारतीय रेलवे में भोजन बनाने से जुड़े किसी भी काम में तैनात न किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 169 हो गए। देश के विभिन्न हिस्सों से 18 नए मामले सामने आए। इन मामलों में 25 विदेशी नागरिक शामिल हैं जिनमें से 17 इटली, तीन फिलीपीन, दो ब्रिटेन, एक-एक मामला कनाडा, इंडोनेशिया और सिंगापुर का है। इनमें अभी तक दिल्ली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में तीन मौत के मामले भी शामिल हैं।

क्विक न्यूज

समाज को कोरोना वायरस से लड़ाई में दिहाड़ी मजदूरों की मदद करनी चाहिए

कोयंबटूर (भाषा)। कोरोना वायरस के प्रकोप से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बीच ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने समाज से दिहाड़ी मजदूरों की मदद का आह्वान किया है। उन्होने लोगो से दिहाड़ी मजदूरो की मदद की अपील करते हुए ट्वीट कर कहा कि अपनी और परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी पर निर्भर लोगो के समक्ष रोजगार की कमी से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होने समाज के लोगो से कहा कि ऐसे लोगो को कम से कम दिन भर का भोजन और पोषण प्रदान करे क्योकि भुखमरी से अशांति पैदा हो सकती है।

'मुंहासे के उपचार के लिए आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का उपयोग करती हूं'

नई दिल्ली (भाषा)। भाजपा सांसद डॉ. प्रीतम मुंडे ने गुरुवार को लोकसभा मे कहा कि वह मुंहासे के उपचार के लिए आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का उपयोग करती है क्योकि इसमे लौग का तेल होता है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर निचले सदन मे चर्चा मे हिस्सा लेते हुए मुंडे ने कहा कि मुंहासे के उपचार के लिए वह एलोपैथी क्रीम का उपयोग नही करती है। पेशे से त्वचारोग विशेषज्ञ एवं महाराष्ट्र के बीड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मुंडे ने कहा, मै जानती हूं कि मेरे डाक्टर मित्र इसकी आलोचना करेगे लेकिन मुंहासे के उपचार के लिए मै टूथपेस्ट का उपयोग करती हूं क्योकि इसमे लौग का तेल होता है। मुंडे ने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और हमारे घरो मे छोटी-छोटी चीजो मे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग होता रहा है। मोदी सरकार के दौरान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को काफी बढ़ावा मिला है। मुंडे ने अपने क्षेत्र सहित देश के विभिन्न हिस्सो मे आयुर्वेद अस्पताल खोलने की मांग की।

पंजाब में आज आधी रात से बंद होगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

चंडीगढ (भाषा)। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते 20 से अधिक लोगो के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने के अलावा शुक्रवार आधी रात से सार्वजनिक परिवहन सेवाओ को निलंबित करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। सरकार ने राज्यभर मे शादी समारोह स्थल, होटल, रेस्तरां, बैकेट और खाना खाने के स्थानो को भी बंद करने का फैसला किया है। होम डिलीवरी और खाना पैक करा कर ले जाने वाली सेवाएं चालू रहेगी। स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्र ने यहां कहा, सार्वजनिक परिवहन बसे, टेम्पो और ऑटो रिक्शा शुक्रवार आधी रात से बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए दैनिक आधार पर पंजाब सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय मंत्री समूह की बैठक मे ए फैसले लिए गए। मंत्री समूह ने लोगो के एकत्रित होने की सीमा 20 तक कर दी है। पहले यह सीमा 50 लोगो की थी। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयो मे आम लोगो का प्रवेश भी निषेध रहेगा। उन्होने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वी और 12वी कक्षाओ की परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। उन्होने कहा कि सभी आयुक्तो, उपायुक्तो, पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षको को अपने-अपने थानो को छोड़कर न जाने के निर्देश दिए गए है।

जयपुर में गुरुवार को कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर सुनसान बदी चौपड़ के पास का दृश्य

राज्यसभा में तृणमूल सदस्य को लॉकेट हटाने के लिए कहा गया

नई दिल्ली (भाषा)। राज्यसभा में गुरुवार को आसन ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य डोला सेन को गले में पहना गया उनका लॉकेट हटाने को कहा जिस पर नो एनआरसी, नो सीएए लिखा हुआ था। आसन ने उन्हें यह निर्देश तब दिया जब सदन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी। तृणमूल सदस्य डोला सेन जब बोलने के लिए खड़ीं हुईं तो पीठासीन उपसभापति कहकशां परवीन ने उन्हें अपना लॉकेट हटाने को कहा। डोला सेन ने कहा कि यह उनका आभूषण है। इस पर आसन ने उनसे सदन की गरिमा का सम्मान करने को कहा। आसन के जोर देने पर डोला सेन ने गले में पहना लॉकेट उतार दिया।

झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों के लिए झामुमो, भाजपा और कांग्रेस का एक-एक उम्मीदवार मैदान में

भाषा। रांची

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले द्विवार्षिक चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के शिबू सोरेन, भाजपा के दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर समेत कुल तीन उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं।

झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बताया किइन चुनावों के लिए बुधवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया अत: दो सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या तीन है। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिनमें से एक सीट के लिए झामुमो ने अपने अध्यक्ष शिबू सोरेन को प्रत्याशी बनाया है जबकि भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को और कांग्रेस ने रामगढ़ के जिलाध्यक्ष शहजादा अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह दोनों सीटें निर्दलीय परिमल नाथवाणी और राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा होने से रिक्त हो रही हैं।

झारखंड की 81 सदस्ईय विधानसभा में झामुमो के 29, भाजपा के बाबूलाल मरांडी के साथ कुल 26, कांग्रेस के 16, झामुमो से निष्कासि दो, आज्सू के दो, राजद का एक, भाकपा माले (लिबरेशन) का एक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक और दो निर्दलीय विधायक हैं। अब राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना तय हो गया है। इन चुनावों में झामुमो के मुखिया शिबू सोरेन का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय है क्योंकि झामुमो के वर्तमान विधानसभा में अपने ही 29 विधायक हैं।

इसी प्रकार आज्सू के समर्थन के साथ अब भाजपा के दीपक प्रकाश का भी राज्यसभा में पहुंचना तय माना जा रहा है क्योंकि अब विधानसभा में उन्हें भाजपा के 26 विधायकों के साथ आज्सू के दो विधायकों का भी समर्थन प्राप्त हो गया है जिसे मिलाकर उन्हें अब कम से कम 28 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा उन्हें निर्दलीय अमित यादव ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि भाजपा के विद्रोही निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी उन्हें समर्थन हासिल होगा। वर्तमान में 81 सदस्ईय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 27 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्रॉस वोटिंग न होने पर कांग्रेस प्रत्याशी को इन चुनावों में 23 से अधिक विधायकों के मत मिलने की संभावना नहीं है।

सरकार जल्द लाएगी एमएसएमई की नई परिभाषा

भाषा। नई दिल्ली

सहकारी क्षेत्र, एनएफसी से भी मिलेगा ऋण : गडकरी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए बृहस्पतिवार को सरकार ने कहा कि जल्द ही इस क्षेत्र की नई परिभाषा लाई जाएगी तथा सहकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी बैंकिंग कंपनियों से इस क्षेत्र की इकाइयों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है।

एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है तथा इस लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के मामले में न्यूनतम कर्ज का लक्ष्य तय करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ताजा प्रयासों के बाद अभी तक 22 हजार लोगों को बैंकों से कर्ज दिया गया है।

गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक ऋण मिल सके, इसके लिए अब सहकारी क्षेत्र के बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनएफबीसी) को भी इस क्षेत्र को ऋण देने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि वैश्विक कारणों, पूंजी की कमी, जीएसटी एवं नोटबंदी के चलते इस क्षेत्र के लिए कुछ समय परेशानियां खड़ी हो गई थीं जैसा कोई भी नई व्यवस्था के आने के बाद स्वाभाविक रूप से होता है।

विपक्ष द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के बजट में कटौती के आरोपों को सिरे से नकारते हुए गडकरी ने कहा कि 2015-16 में बजट 2620 करोड़ रूपए था जो 2018-19 में बढ़कर 6552 करोड़ रूपए और 2019-20 में अब तक 7011 करोड़ रूपए हो गया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में वितरित की गई सब्सिडी क्रमश: 1020 करोड़ रुपए, 2070 करोड़ रुपए और वर्तमान वर्ष में अभी तक 1661 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार उक्त अवधि में इस क्षेत्र में स्थापित की गई इकाइयां क्रमश: 44367, 73427 और 55737 हैं। इस क्षेत्र में इस अवधि में प्रदान किए गए रोजगार क्रमश: 303362, 587467 और 445896 हैं। इस क्षेत्र को इस अवधि में क्रमश : 20 हजार करोड़ रुपए, 3168 करोड़ रुपए और 3456 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने खादी क्षेत्र में हो रही प्रगति की सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि खादी उद्योग क्षेत्र में सरकार ब्रांडिंग पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जाए और इसमें कार्पोरेट कल्चर लाया जाए। गडकरी ने कहा कि पिछले साल इस क्षेत्र में 3215 करोड़ का कारोबार हुआ, जो इस साल साढ़े तीन हजार करोड़ से ऊपर जाएगा। ग्रामोद्योग क्षेत्र में हुए कारोबार की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2015-16 में यह 40384 करोड़ रूपए था जो वर्तमान वर्ष में बढ़कर 60343 करोड़ हो गया।

उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की परिभाषा को लेकर काफी विवाद था। इसे लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों से बातचीत की गई और उनके सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कानून मंत्रालय से भी विचार विमर्श कर लिया गया है। अभी प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अधिवेशन (संसद का वर्तमान सत्र) समाप्त होने से पहले एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा आ जाएगी। केवीआईसी के आधुनिकीकरण और पेशेवर बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग तीन महीनों में इस संस्था को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और इस क्षेत्र को निर्यातोन्मुख बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

गडकरी ने स्वीकार किया कि एमएसएमई इकाइयों को सरकारी विभागों और उपक्रमों से बकाया धन मिलने में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और इसके कारण कई बंद होने के कगार पर पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन इकाइयों को मजबूती देनी है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के रोजगार को बरकरार रखना है तो एमएसएमई इकाइयों का भुगतान अनिवार्य रूप से तीन महीने के अंदर करना होगा।

कोरोना वायरस से मौत की अफवाह फैलाने के आरोप में एक गिरफ्तार

जम्मू (भाषा)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कोरोना वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जिला विकास आयुक्त (डीडीसी), किश्तवाड़, रजिंदर सिंह तारा ने लोगों को सलाह दी कि वे फर्जी सूचनाओं पर ध्यान न दें। जिला के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मौत कोरेना वायरस के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारणों से हुई। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के पालमर्द गांव के रहने वाले व्यक्ति की जम्मू के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

झारखंड सशस्त्र पुलिस (जेएपी) के जवानों ने गुरुवार को रांची में झारखंड विधानसभा में कोरोनावायरस के खिलाफ एहतियात के तौर पर मास्क पहना हैं

श्रद्धालुओं के लिए 31 तक बंद हुआ श्री जगन्नाथ मंदिर

भाषा। पुरी

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण यहां श्री जगन्नाथ मंदिर शुक्रवार से 31 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा।

मंदिर के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि मंदिर के पुजारियों एवं सेवकों को मंदिर में पूजा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश कल से 31 मार्च के लिए निलंबित रहेगा। मंदिर के अंदर पूजा अनुष्ठान जारी रहेंगे। इन अनुष्ठानों को करने के लिए पुजारियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्य रामचंद्र दसमहापात्र ने कहा कि मंदिर में पूजा-अनुष्ठान करने और अन्य रस्मी कार्यक्रम करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए एक बैठक की जाएगी।उन्होंने मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाने के बारे में कहा कि ऐसा पिछले लंबे समय में संभवत: पहली बार हुआ है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों को पुरी में दो दिन में होटल खाली करने और यहां नहीं आने की सलाह दी है।

मुंबई के हाजी अली, माहिम दरगाह श्रद्धालुओं के लिए बंद

मुंबई (भाषा)। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुंबई की माहिम दरगाह के साथ-साथ ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। माहिम दरगाह के प्रबंध न्यासी और हाजी अली दरगाह के न्यासी सुहैल खंडवानी ने पीटीआई से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। इन दोनों धार्मिक स्थलों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें मुस्लिमों के साथ-साथ गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 लोकसभा में पारित

भाषा। नई दिल्ली

लोकसभा ने गुरूवार को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को मंजूरी दी जिसमें गुजरात के एक आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान है।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 में आयुर्वेद और संबद्ध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के लिए जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। जामनगर स्थित इस संस्थान की स्थापना 1952 में की गई थी। इसके बाद वहां स्नातकोत्तर संकाय स्थापित किया गया। अभी वहां आयुर्वेद पर एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुसार आयुर्वेद के विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए एवं इस संकाय में शिक्षा के मानकों को उन्नत करने हेतु स्वायत्तता प्रदान की जाए। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपद एसो नाइक ने कहा कि इसके माध्यम से आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना सुगम होगा। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आदि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के तहत इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 102 अस्पतालों को लेकर काम हो रहा है।

नाइक ने सांसदों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के अस्पताल खुलवाने के लिए प्रस्ताव भेजें और सरकार उन पर सकारात्मक तरीके से जवाब देगी। उन्होंने साथ ही बताया कि आयुष चिकित्सा के तहत इलाज कराने वाले लोगों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 27 बीमा कंपनियों से बात हुई है। आयुष मंत्री ने साथ ही बताया कि देश में इस समय 704 आयुष कालेज तथा 11 राष्ट्रीय संस्थान काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों खासकर केरल में आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना संबंधी कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब में कहा कि अभी मंत्रालय को अस्तित्व में आए छह साल ही हुए हैं और आने वाले दिनों में देशभर में ऐसे 5 से 10 संस्थान और खोले जाएंगे।

पारंपरिक भारतीय ज्ञान संपदा को बचाने की लोकसभा में उठी मांग

भाषा। नई दिल्ली

हजारों साल पुराने भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करने के लिए इसके उचित दस्तावेजीकरण, प्रैक्टिशनर को पर्याप्त कानूनी संरक्षण मुहैया कराने, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और बौद्धिक संपदा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की लोकसभा में मांग उठी।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पेश करते हुए आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि आयुर्वेद की पूरे विश्व में मांग बढ़ रही है और भारत ने 14 राष्ट्रों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और दुनिया के दस विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद पीठ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के प्रसार प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने 28 देशों में 58 सूचना केंद्र काम कर रहे हैं और 10 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना की गई है।

कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि साल 2015 में आयुर्वेद उत्पादों का निर्यात 3.4 अरब डालर था जो कि साल 2022 तक बढ़कर 9.7 अरब डालर होने की संभावना है। थरूर ने कहा कि आज देश में 77 फीसदी लोग आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और अकेले केरल राज्य में 1400 उद्योगिक इकाइयां आयुर्वेद से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद से चले आ रहे इस पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण के लिए सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जर्नलों और मीडिया में कुछ साल पहले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आयुर्वेद ज्ञान के वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण की जरूरत है। इसके साथ ही इस पद्धति की प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों को कानूनी संरक्षण देने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए।

सरकार ने विधेयक में इसकी अनदेखी की है। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में कहा कि कुछ भारतीय पारंपरिक औषधियों का पेटेंट अमेरिका ने कराने की कोशिश की थी जिस पर तत्कालीन संप्रग सरकार ने पुरजोर विरोध जताया था। थरूर ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के संवर्धन के लिए केरल में राष्ट्रीय औषधीय पौध संस्थान की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की केरल में स्थापना नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए विधेयक पेश किए जाने की भी मांग की।

चेन्नई में तिरुमाला तिरुपति मन्दिर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए हवन करते हुए पुजारी

महाराष्ट्र के तीन लैब में अन्य राज्यों से आने वाले नमूनो की भी हो रही है जांच

मुंबई/पुणे। महाराष्ट्र को जो तीन प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में जुटी हैं, वे ना सिर्फ राज्य से बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले नमूनों की भी जांच कर रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इन प्रयोगशालाओं में पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान वैश्विक रेफरल लैब है जहां दक्षेस देशों से भी नमूने जांच के लिए आते हैं। यहां ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि तमाम अन्य वायरस संक्रमणों की भी जांच होती है। उन्होंने कहा, ग्लोबल रेफरल का अर्थ है कि इस प्रयोगशाला की रिपोर्ट दूसरे देशों में भी वैध है। एनआईवी के अलावा फिलहाल नागपुर स्थित इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा मुंबई के कस्तुरबा अस्पताल में अन्य दो लैब चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रयोगशालाओं की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, ए जरूरत के हिसाब से देश के किसी भी कोने से आने वाले नमूनों की जांच कर रहे हैं।

ओडिशा के सभी चर्चों में तमाम गतिविधियां बंद

भुवनेश्वर। ओडिशा के सभी चर्चों ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर ऐहतियात के तौर पर सभी गतिविधियों को 31 मार्च तक निलंबित करने का फैसला लिया है। कटक स्थित ओडिशा बैप्टिस्ट चर्च और भुवनेश्वर के चर्च ऑफ क्राइस्ट ने बुधवार को तय किया कि वे रविवार की मास (प्रार्थना) सहित सभी गतिविधियां निलंबित कर रहे हैं। मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल्स चर्च में 31 मार्च तक मास (प्रार्थनाएं) नहीं होंगी। माहिम के चर्च में बुधवार और रविवार के मास के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के डर से बंबई के आर्चबिशप कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेसियस ने सभी को 31 मार्च तक चर्च आने से छूट दे दी है। कैथोलिकों को चर्च आने की जरुरत नहीं है, मास की लाइव स्ट्रीमिंग यू-ट्यूब पर होगी। आप उससे जुड़ सकते हैं।

बंबई हाईकोर्ट ने पूछा, क्या चर्च में अब भी प्रार्थनाएं हो रही है

मुंबई। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से बृहस्पतिवार को जानना चाहा कि क्या राज्य के गिरजाघरों में अब भी प्रार्थना सभाएं हो रहीं हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर ने महिला अधिवक्ता द्वारा लिखे पत्र का संज्ञान लिया। इस पत्र में कहा गया कि एकत्र न होने के अधिकारियों की चेतावनियों और बार-बार के आग्रह के बावजूद सैकड़ों लोग गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। अदालत ने पूछा, सरकार गिरजाघरों में हो रही इन प्रार्थना सभाओं को लेकर क्या कर रही है? अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है। अधिवक्ता सविना क्रास्तो की ओर से लिखे गए पत्र के मुताबिक रोजाना दिन में दो बार प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं और लोग होली कम्युनियन का सेवन कर रहे हैं जो कि अस्वस्थ आदत है। क्रास्तो ने अदालत से इस मुद्दे का संज्ञान लेने और सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र में अब तक 47 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है।

लोस में उठे छोटे किसानों, बुजुर्ग दिव्यांगजनों तथा कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर असर के मुद्दे

भाषा। नई दिल्ली

लोकसभा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने छोटे किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाता है, इस स्थिति में सरकार को ऐसे किसानों को राहत प्रदान करना चाहिए। निचले सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने पर किसानों के बैंक खाते में मुआवजा भेजती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मथुरा में उन्हें पता चला कि जो किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है।

हेमा मालिनी ने कहा कि ऐसे में सरकार को पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए ताकि दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बुजुर्ग दिव्यांगजनों की समस्याओं का विषय उठाया और कहा कि व्हील चेयर पर जीएसटी को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर जीएसटी के कारण इसकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ऐसे में बुजुर्गों को राहत प्रदान करने के लिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े एक मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अदालत में याचिका दायर करने की मांग की। राकांपा की सुप्रिया सुले ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति का जिक्र किया और इससे निपटने में विदेश मंत्रालय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। देश में आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है और नई परिस्थिति में सरकार को आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के समक्ष आसन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारी करनी चाहिए।

तेलगू देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने मनीला हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया और सरकार से इन्हें वहां से निकालने के लिए कदम उठाने की मांग की। भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने भी मनीला में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए सरकार से प्रयास करने को कहा। भाजपा की दर्शना जरदोश ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम होने वाले संदेश का जिक्र किया और इस बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर डर पैदा किए जाने के माहौल पर सरकार से ध्यान देने की मांग की।

बीजद के अनुभव मोहंती ने भी फिलीपीन के मनीला हवाई पर फंसे भारतीय छात्रों के मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने हाल ही में यहां कुछ महिलाओं द्वारा उनसे अस्पताल जाने के लिए पैसे मांगने और गाड़ी उपलब्ध कराने की पेशकश करने को स्वीकार नहीं किए जाने की एक आपबीती सुनाते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से भिक्षावृत्ति का मामला है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति एक पेशा बन चुकी है और सरकार को इसे लेकर नीति तैयार करनी चाहिए। आप के भगवंत मान ने कहा कि पंजाब अनाज उत्पादक प्रदेश है, ऐसे में राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए।

भाजपा के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कोरोना के कारण बने माहौल के बीच जरूरी सामान की कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की मांग उठाई। भाजपा के जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि केंद्रीय दल भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाए और मुआवजा दिया जाए।

संसद सत्र जल्दी समाप्त किए जाने की रास में उठी मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस के एक सदस्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए संसद के मौजूदा सत्र को जल्दी स्थगित किए जाने की मांग की। सभापति एम वेंकेया नायडू ने कहा कि स्थगन इसका कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी भट्टाचार्य ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि सदस्यों को हर दिन सुबह कई दस्तावेज मिलते हैं। लेकिन यह पता नहीं होता कि उन दस्तावेजों की साफ-सफाई (सेनेटाइजेशन) हुई है या नहीं। मंत्री सहित सभी सदस्य उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं।

भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सत्र को स्थगित करने का अनुरोध किया था लेकिन उसके बाद भी इसे स्थगित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सदन को जल्दी स्थगित किए जाने की मांग की। सभापति नायडू ने कहा कि सत्र स्थगित किया जाना कोई समाधान नहीं है। कर्मचारियों को सेनेटाइजर दिए गए हैं। शून्यकाल में ही भाजपा के विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने देश में थैलेसीमिया के बढ़ते मामलों का जिक्र किया और कहा कि यह एक वंशानुगत बीमारी है जिस पर काबू पाया जा सकता है। भाजपा सदस्य ने कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों इस बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके बच्चे के इस बीमारी से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है। इस पर काबू पाने के लिए साइप्रस ने कानून बनाए हैं। साइप्रस के कानून का अध्ययन कर यहां भी कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर उसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने इस बीमारी के संबंध में जागरूकता पैदा करने और शादी के पहले जांच कराने का सुझाव दिया। शून्यकाल में ही सपा के रेवती रमन सिंह ने देश में कैंसर के बढ़ते मामलों का जिक्र किया और कहा कि हर साल 12 लाख लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हो जाती है। उन्होंने आरंभिक जांच कराने पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील है जहां जांच नहीं होती। सिंह ने आगाह करते हुए कहा कि अगर जल्दी ही कार्वाई और रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति भयावह हो सकती है।

नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन उच्चस्तरीय मंत्रियों के साथ कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए बैठक करते हुए

राज्यसभा में उठा लोगों के मोबाइल कॉल डाटा रिकॉर्ड जुटाने का मुद्दा

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्षी कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग द्वारा कॉल डाटा रिकार्ड (सीडीआर) मांगे जाने का मुद्दा गुरुवार को उठाते हुए आरोप लगाया कि देश में जनता पर निगरानी का राज लागू किया जा रहा है। यह आरोप खारिज करते हुए कानून एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीडीआर कॉल ड्रॉप समस्या से निपटने और दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से मांगे गए हैं।

सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया था। लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने नोटिस अस्वीकार करते हुए उन्हें शून्यकाल में यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी। आनंद शर्मा ने कॉल रिकार्ड से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत किसी सरकारी विभाग को नियमित आधार पर सीडीआर मांगने की अनुमति है।

शर्मा ने कहा कि भारत में लोगों पर निगरानी का राज कायम होता जा रहा है और इससे लोगों की निजता का अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्रसाद ने कहा कि वह आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई निगरानी नहीं हो रही है, कोई फोन टैपिंग नहीं हो रही है और कोई कॉल रिकार्डिंग नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी की निजता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बुधवार को कहा था कि वह कॉल ड्राप की समस्या के विश्लेषण और दूरसंचार सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से सीडीआर एकत्रित कर रहा है। लेकिन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें ग्राहक का निजी ब्योरा नहीं जुटाया जा रहा है। डीओटी का दावा है कि इसके लिए ऐसे क्षेत्र में, जहां कॉल ड्राप यानी मोबाइल फोन पर बातचीत नेटवर्क की कमी के करण बीच में ही कट जाने की शिकायतें हैं, वहां जाने वाले ग्राहकों के कॉल डाटा रिकॉर्ड जुटाए जाते हैं लेकिन इसमें उनकी निजता का हनन नहीं किया जाता है। डीओटी ने एक बयान में कहा था कि किसी ग्राहक की ओर से की गई या प्राप्त की गई केवल उन्हीं कॉल के कॉल ड्रॉपाया कॉल विवरण जुटाए जाते हैं जो वह किसी विनिर्दिष्ट सेल टावर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर करता हैाप्राप्त करता है। बयान में इस बात को दोहराया गया है कि ऐसे मामले में कॉल करने वालों या कॉल प्राप्त करने वाले का नाम और पता जुटाया नहीं जाता है।

कोरोना वायरस से बचने की दवाई देने वाले डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

भाषा। मुम्बई

महाराष्ट्र के पालघर में एक डॉक्टर के खिलाफ कोरोना वायरस से बचने की दवाई देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आयुर्वेद एमडी, डॉक्टर सरवर राजे खान ने वसई शहर में अपनी क्लीनिक के बाहर कथित तौर पर कोरोना वायरस फ्लू से बचने की दवाई उपलब्ध होने का बोर्ड लगाया था। वालीव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि क्योंकि विज्ञापन भ्रमित करने वाला था इसलिए उसके खिलाफ भादंवि की धारा 188 और कोरोना वायरस के इलाज को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने वायरस के संबंध में अफवाह फैलाने और भ्रामक जानकारी देने के खिलाफ आदेश भी जारी किया है। खान ने कथित तौर पर एक बोर्ड लगाया था, जिस पर लिखा था रोकथाम इलाज से बेहतर है, कोरेना फ्लू से बचने की दवाई उपलब्ध है।

माकपा ने प्रधानमंत्री से कहा राष्ट्र के नाम संबोधन में जनगणना टालने और एनपीआर छोड़ने की घोषणा करें

नई दिल्ली। माकपा पोलित ब्यूरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह कोरोना वायरस के खतरे के चलते जनगणना की प्रक्रिया को स्थगित करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का परित्याग करने की घोषणा करें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को बताया कि मोदी कोरोना वायरस से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबले को लेकर गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माकपा की ओर से जारी बयान में कहा गया, कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी के फैलने के खतरे और सामाजिक दूरी जैसे एहतियात को देखते हुए माकपा पोलित ब्यूरो का स्पष्ट विचार है कि एक अप्रैल से शुरू होने वाली एनपीआर की प्रक्रिया का परित्याग कर देना चाहिए। सरकार और सभी एजेंसियां एक मत होकर महामारी को नियंत्रित करने और लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें। माकपा ने कहा, पहले ही 13 राज्यों की सरकारों ने एनपीआरा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का विरोध किया है।

देश में 15 प्रदेशों में हज हाउस, और बनाने की योजना नहीं: नकवी

नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि देश में 15 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में हज हाउस हैं तथा केंद्र सरकार की देश में और हज हाउस बनाने की कोई योजना नहीं है लेकिन राज्य इसका निर्माण कर सकते हैं। सरकार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है और इसकी सतत निगरानी की जाती है।

निचले सदन में छेदी पासवान के प्रश्न के लिखित उत्तर में नकवी ने कहा कि देश में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के तहत 15 हज हाउस हैं जो असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चित बंगाल में हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि देश में हज हाउस निर्मित करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई निधि उपलब्ध नहीं कर रही है। यद्यपि राज्य सरकारें अपनी राज्य हज समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों में हज हाउस का निर्माण कर सकती हैं।

नकवी ने कहा कि इसके अलावा भारतीय हज समिति इस प्रयोजन के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जहां तक भारतीय हज समिति के माध्यम से हज पर जाने वाले यात्रियों की हवाई यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी का संबंध हैं, यह सब्सिडी 2018 में बंद कर दी गई थी। एक अन्य सवाल के जवाब में नकवी ने कहा कि देश में हज यात्रियों की संख्या को लेकर भारत और सउदी अरब सरकार के बीच द्विपक्षीय रूप से चर्चा होती है और इसके अनुरूप ही प्रति वर्ष हज कोटा तय होता है। अल्पसंख्यकों से जुड़े प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल मंत्रालयाविभागों की योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है। यह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। सरकार इन समुदायों के लिए कल्याण योजनाएं भी चला रही हैं।

गृह मंत्रालय ने एनजीओ को वार्षिक रिटर्न भरने के लिए एक बार 60 दिन की छूट दी

नई दिल्ली। विदेशों से चंदा प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए एक बार 60 दिन की छूट दी है। अब वे 18 मई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम उन सभी एनजीओ और एसोसिएशनों को वार्षिक रिटर्न फाइल करने को कहता है जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति मिली है। हालांकि, कई एनजीओ और एसोसिएशनों ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह उनके एफसीआरए प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने साथ ही 2017-18 का रिटर्न नहीं भर पाने की वजहाकारण भी बताएं हैं। उनके द्वारा बताए गए कारणों में अकाउंटेंट या सीए फर्म पर उनकी निर्भरता, सीए द्वारा तय समय सीमा का उल्लंघन किया जाना, बाढ़, सीए द्वारा लॉग-इन और पासवर्ड में आने वाली दिक्कतें शामिल हैं। ज्यादातर एनजीओ ने एक समान दिक्कत बताई है, जिसमें कहा गया है कि एफसीआरए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इन संगठनों के ऑनलाइन खातों का कामकाज देखने वाले सीए आदि को जानकारी नहीं थी कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय इसकी सख्त निगरानी करता है। इन एनजीओ और एसोसिएशनों का कहना है कि उनकी मंशा कभी भी कानून के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने की नहीं है।

श्रीनगर में कोरोना वायरस के खौफ के कारण पूरी तरह बंद शापिंग माल के बीच से गुजरता एक व्यक्ति

गोगोई का नया कार्यक्षेत्र

राज्यसभा के नामित सदस्य

वैसे पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए राष्ट्रपति का नामांकन स्वीकार करने में तकनीकी रूप से कुछ गलत नहीं है। विधि के उनके विशिष्ट ज्ञान और व्यापक अनुभव को देखते हुए वे एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं और उच्च सदन में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। वे समाज में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले हैं। इसके साथ ही वे पहले सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश नहीं हैं जिनको कार्यपालिका से लाभ प्राप्त हुआ हो। पिछली सरकारों ने भी अपनी 'मित्रता' के लिए न्यायाधीशों को पुरस्कृत किया है। वे पूर्व-उदाहरणों का संदर्भ दे सकते हैं और हम जानते हैं कि कानून क्या है। जस्टिस एस. फजल अली सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनको 1952 में ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। कांग्रेस ने सत्ता में रहते अनेक उल्लेखनीय न्यायविदों को यह अवसर दिया है। 1950 के दशकारंभ में असम उच्च न्यायालय से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस बहरुल इस्लाम ने एक दशक तक राज्यसभा की सेवा की थी। कांग्रेस ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों में राजीव गांधी को क्लीन चिट देने वाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्र को सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया था और 1988 में उनको कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया। इस बात पर काफी बहस हुई है कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से लाभ नहीं लेने चाहिए, जिनमें जांच आयोगों की अध्यक्षता शामिल है। आशंका है कि इससे निष्पक्ष निर्णय देने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। फिर जस्टिस गोगोई के राज्यसभा में जाने पर इतनी बेचैनी क्यों

है? केवल 'कूलिंग आफ' समय न होने से यह नतीजा निकालना अनुचित है कि उनको राफेल या अयोध्या फैसले के लिए 'पुरस्कार' मिला है। शायद आलोचना का कारण सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा खुलेआम अपने मनपसंद लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है। लेकिन कोई भाजपा को इसलिए जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय से यही काम करती रही है। गोगोई की ज्यादा आलोचना इसलिए भी हो रही है कि उनको एक समय 'विद्रोही' जज माना जाता था। अत: अब इसे न्यायपालिका पर कार्यपालिका के बढ़ते वर्चस्व के रूप में देखा जा रहा है जो एक समय विरोधी दृष्टिकोण अपना सकती थी। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र के बाद वरिष्ठतम जज के रूप में गोगोई ने जनवरी 2018 में प्रेस कान्फ्रेंस कर मिश्र द्वारा मनमाने ढंग से अदालत के संचालन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने संवेदनशील फाइलें निपटाने के मामले में चयनित दृष्टिकोण का आरोप भी लगाया था।

इसलिए उनसे उम्मीद थी कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। यह भी विश्वास था कि वे प्रचंड बहुमत प्राप्त कार्यपालिका से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन बाद के फैसलों से उनकी 'विद्रोही' छवि एक सीमा तक टूटी। अपने पूर्ववर्ती की रूस्टर व्यवस्था का विरोध करने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक रूप से सर्वाधिक संवेदनशील मामलों में सरकार के लिए सुविधाजनक स्थिति सुनिश्चित की। वे बेहतर तरीके से जानते हैं कि राज्यसभा नामांकन तत्कालीन सरकार की सेवा का पुरस्कार होता है। गोगोई ने यह कह कर राज्यसभा में अपने नामांकन को उचित ठहराया है कि 'यह विधायिका के समक्ष न्यायपालिका का दृष्टिकोण रखने का अवसर है।' आने वाला समय ही बतायेगा कि वे भारत के सम्मानित नागरिक के रूप में राजनीतिक उथलपुथल वाले समय में नैतिक विजय कैसे प्राप्त करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके प्रति आलोचकों द्वारा अत्यन्त कठोर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

श्रम बाजार को मुक्त करना जरूरी

देश में अधिकांश कानून या तो आदिमकालीन हैं या वर्तमान यथार्थ के अनुकूल नहीं हैं। नौकरी देने संबंधी नियमों पर पुनर्विचार की जरूरत है। श्रम बाजार को मुक्त करने से भारत में अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले उद्यम फले-फूलेंगे।

प्रफुल्ल गोराड़िया
लेखक लोकप्रिय स्तम्भकार हैं)

वर्ष 1991 से उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा बिजनेस सुगमता के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है तथा इस पर उदारतापूर्वक बहस हुई है। लेकिन रोजगार बाजार को मुक्त करने के लिए बहुत कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि, नए व वैकल्पिक श्रम कानूनों के बारे में काफी चर्चा हुई है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी के बारे में काफी बात हुई है। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि इस प्रकार की सतही बातचीत से अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? बार-बार सरकारें जनता को खुश करने के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाती हैं। कुछ श्रमिक या ट्रेड यूनियन नेता ऐसी बातों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन बात इतने पर समाप्त हो जाती है। ऐसे कदमों से रोजगार नहीं बढ़ता है। विडंबना है कि ऐसे कदमों से मजदूरी और घटती है।

औद्योगिक विवाद कानून, 1947 सभी नौकरियों के लिए निर्देशक सिद्धान्त हैं जिसमें अधिकारियों व कार्यकारियों का सर्वोच्च स्तर शामिल नहीं है। कानून पास करने के समय तत्कालीन सरकार का इरादा इसे केवल कामगारों पर लागू करना था। उस समय लागू कम वेतनों के कारण इसमें क्लर्क कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। किसी अन्य निर्देश के अभाव में स्थिति यहां तक बिगड़ी कि कोई कर्मचारी श्रम अदालत में मुकदमा दायर कर सकता था। इसके परिणामस्वरूप हर जिम्मेदार सेवायोजक द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियों के पहले दो बार नहीं तीन बार सोचता है। जहां तक उपलब्ध नौकरियों का सवाल था, ये श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। एक सीमा तक सेवायोजक आउटसोर्सिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसी फर्जी नियुक्तियों से राष्ट्रीय स्तर पर रोजगारों के सृजन में सहायता नहीं मिलती है।

औद्योगिक विवाद कानून तथा उससे जुड़े कानूनों ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसे समझने के लिए पश्चिम बंगाल पर गौर किया जा सकता है। यह राज्य एक समय भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रांत था, लेकिन अब यह उद्योगों की कब्रगाह बन गया है। उद्योगों की कब्रगाह बनने वाला केरल दूसरा राज्य है, हालांकि यह काफी छोटा प्रदेश है। औद्योगिक विवाद कानून ने ऐसे ट्रेड यूनियनवाद को प्रोत्साहित किया जिसने राज्य की शुरुआती आर्थिक प्रगति को पटरी से उतार दिया। एकाधिकारी व नियंत्रित व्यापार व्यवहारों के शिखर समय में बहुसंख्य बड़े बिजनेसों के मुख्यालय कोलकाता में थे। लेकिन औद्योगिक विवाद कानून से पैदा ट्रेड यूनियनवाद ने उनको प्रभावी रूप से वहां से भगा दिया। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत औद्योगिक विवाद कानून पर पुनर्विचार करे।

प्रथमदृष्टया यूनियनों का उद्देश्य अपने सदस्य कामगारों के कल्याण की सुरक्षा व उसका प्रोत्साहन है। इस कारण अधिकांश यूनियनें एक या दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गईं। इससे पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता मिली। मूल रूप से किसी ट्रेड यूनियन की शक्ति उसके सदस्यों की संख्या है और उनका कल्याण प्राथमिकता में निचले स्थान पर आता है। इसके साथ ही कामगारों की यूनियन की अवधारणा क्रांति की इच्छा से पैदा होती है जो बुर्जुआ संस्थानों को गिराने में सहायता व उसके उत्प्रेरण से आगे बढ़ती है।

भारतीय परिदृश्य की विडंबना उसकी भारी जनसंख्या है। इस प्रकार एक ओर जनसंख्या लाभांश का संतोष हमारे सामने आता है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी तथा कानून व श्रम अदालतें सेवायोजकों के खिलाफ पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। दूसरी विडंबना यह है कि पूरे देश में अधिक रोजगारों की मांग हो रही है। लेकिन अब तक इस लेख में वर्णित किसी बिंदु से नौकरियां बढ़ने में सहायता नहीं मिल सकती है। वास्तव में इससे नौकरियों का दायरा घट सकता है। तीन साल पहले जारी मार्गन स्टेनले की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के श्रम कानूनों ने फर्मों को छोटा बने रहने पर मजबूर किया है जो कम लोगों को नौकरी दें या अधिक पूंजी वाली तकनीक का प्रयोग करें। कोई आश्चर्य नहीं कि जीडीपी के दृष्टिकोण से भारत में विनिर्माण का हिस्सा उभरते बाजारों में सबसे कम है। उत्पादक रोजगार सृजन में भारत का हिस्सा बहुत कम है।

आवश्यकता है कि औद्योगिक विवाद कानून समेत ये सारे कानून समाप्त किए जाएं। एक कामगार अनुबंध विधेयक पास किया जाना चाहिए जो सेवायोजक व कर्मचारी के बीच हो। इसमें वेतन या मजदूरी समेत परस्पर सहमति से अनेक शर्तें शामिल की जा सकती हैं।

यदि देश का श्रम बाजार 60-70 साल पुराने नियमों में बंधा रहे तो देश में उत्पादक रोजगार वृद्धि कैसे हो सकती है? एक और तत्व को अनदेखा किया गया है कि काम अपने आप में एक प्रकार का प्रशिक्षण तथा अनुभव है। यदि कोई बच्चा समुचित स्कूली शिक्षा से वंचित रहे तो जल्दी रोजगार पाने की उसकी क्षमता काफी सीमा तक घट जाती है। दूसरी ओर यदि उनको अनेक वर्षों तक कोई काम न मिले तो उसका आत्मविश्वास टूटेगा तथा उसे सीखने का अवसर नहीं मिलेगा न अनुभव प्राप्त होगा, जबकि यह बेहतर कॅरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है भले ही यह चाहे जितना मामूली क्यों न हो। पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी पर जोर देना इस पुरानी कहावत को खारिज करना है। एक व्यक्ति को बेहतर वेतन सुनिश्चित करने से नौ संभावित लोगों का कॅरियर दांव पर लगता है। न्यूनतम वेतन के कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रभावित होने से इन नौ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है।

एक समय था जब कोई बेरोजगार व्यक्ति अपने परिवार पर निर्भर रह सकता था जो अपनी जमीन पर खेती करता था। लेकिन अब बढ़ती जनसंख्या तथा अधिकांश खेतों का आकार घटने के कारण बेरोजगार या बिना आमदनी वाले व्यक्ति के लिए यह विकल्प समाप्त हो गया है। इसलिए कुछ आमदनी जरूरी है। वेतन न मिलने से कम वेतन मिलना ज्यादा अच्छा है। इस स्थिति का एक पक्ष यह भी है कि इससे उद्यामियों को प्रोत्साहन मिलता है। समृद्ध दुनिया में हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग असीम हो सकती है, बशर्ते कि ये ज्यादा महंगी न हों।

भारतीय संविधान में श्रम कानून समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसलिए इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र व राज्य, दोनों का है। इसका अर्थ ऐसे अनेक कानून बनना है जो कभी-कभी एक दूसरे को आच्छादित करते हैं।

उदाहरण के लिए, श्रम के मुद्दे पर 44 केन्द्रीय व लगभग 160 राज्य कानून हैं। इनमें से अधिकांश आदिम कालीन या स्वतंत्रता के पहले बने थे। आवश्यकता है कि इन कानूनों को वर्तमान यथार्थ के अनुसार फौरन बदला जाए। अनेक कानून एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, 19 कानूनों का संबंध काम व औद्योगिक संबंधों से है तथा 14 सामाजिक सुरक्षा व समाज कल्याण के बारे में हैं।

इसलिए आवश्यकता है कि औद्योगिक विवाद कानून समेत ये सारे कानून समाप्त किए जाएं। इनके स्थान पर एक कामगार अनुबंध विधेयक पास किया जाना चाहिए जो सेवायोजक व कर्मचारी के बीच हो। इसमें वेतन या मजदूरी समेत परस्पर सहमति से अनेक शर्तें शामिल की जा सकती हैं। केवल समान शर्त यह होनी चाहिए कि वेतन का 25 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जाए जिसका भुगतान ठीक पांच साल बाद हो। हर महीने मिलने वाले ये ड्राफ्ट कर्मचारी को रोजगार-पश्चात लाभ के रूप में होंगे। इससे कर्मचारी आश्वस्त होगा कि यदि सेवायोजक अपना बिजनेस बंद कर दे तो भी उसका इतना लाभ सुनिश्चित रहेगा। इससे अधिक श्रमशक्ति प्रयोग करने वाली अनेकानेक परियोजनाओं को आगे बढ़ने तथा फलने-फूलने का अवसर मिलेगा।

कोरोनावायरस से निपटने की ब्रिटिश योजना

"यदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना गलत सिद्ध हुई तो कोरोना संक्रमण से अनेक ब्रिटेनवासियों की मृत्यु हो सकती है। अधिकांश विशेषज्ञ उनको गलत मानते हैं।"

गुइन डायर
(लेखक स्वंतत्र पत्रकार हैं)

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 11 मार्च को कहा था कि वो ब्रिटिश जनता के साथ हैं, लेकिन अनेक ब्रिटिश परिवारों को समय से पहले अपने परिजनों को खोना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मार्च को कहा था कि शांति बनाए रखें, ये समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। अंग्रेजी बोलने वाले दो सबसे बड़े लोकलुभावन नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप दो महीने से कोविड-19 वायरस को अफवाह बताकर खारिज कर रहे थे, जबकि उनके विरोधी बाजार की समस्याओं को उजागर करते हुए उनके पुन: निर्वाचन पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार, 13 मार्च को उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। लेकिन, विगत रविवार को वो फिर कल्पना कर रहे थे कि हमने वायरस पर असाधारण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।

दूसरी ओर, जानॅसन ने बुरी खबर बहुत गंभीर तरीके से पेश की। वो गंभीर थे और कह रहे थे कि बहुत से लोग मर जाएंगे लेकिन हमें एक योजना बनानी चाहिए। यदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना गलत सिद्ध हुई तो कोरोना संक्रमण से अनेक ब्रिटेनवासियों की मृत्यु हो सकती है। अधिकांश विशेषज्ञ उनको गलत मानते हैं। महामारी विज्ञानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलिसम हेंग ने कहा था कि जब मैंने ब्रिटेन की योजना के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह एक व्यंग्य है। उन्होंने यह बात द गार्जियन से शनिवार को कही थी। लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप के उलट बोरिस जानसन वैज्ञानिकों की बात सुनते हैं और अब उनके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वैलेस व मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस विटले ने एक योजना बनाई है, जिसे अन्य विशेषज्ञ गलत बता रहे हैं।

हार्ड इम्यूनिटी ऐसे समय पैदा होती है जब किसी समुदाय के बहुसंख्यक लोग किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा विकसित कर लेते हैं। इससे वायरस संक्रमण की श्रंखला पर सवाल उठते हैं और पहले से प्रतिरक्षा प्राप्त कर चुके लोग लंबे समय तक इसे धारण नहीं कर पाते हैं। बोरिस जॉनसन की यही योजना है।

उनके अनुसार कोरोनावायरस को फैलने के बावजूद जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत उसके खिलाफ प्रतिरक्षा क्षमता विकसित कर लेगा और बच जाएगा। इसके बाद, महामारी की दूसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि प्रतिरक्षा के कारण प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्य से, इस योजना में अनेक गलतियां हैं। ब्रिटेन की 60 प्रतिशत जनसंख्या लगभग 40 मिलियन है।

इसमें, 40 वर्ष से कम आयु वाले वयस्कों में केवल 0.2 प्रतिशत कोविड-19 से ग्रसित हैं। इसे देखते हुए मृत्यु दर वृद्ध लोगों में तेजी से बढ़ सकती है और 60 वर्ष से अधिक आय वालों में यह 3.6 प्रतिशत हो सकती है।

इस प्रकार, 70 वर्ष से कम आयु वालों में लगभग 45,000 लोगों की मौत हो सकती है। यह विश्व युद्धों में मारे गए ब्रिटिश सैनिकों से अधिक है। इसके साथ ही, यह इस शर्त पर आधारित है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कोविड-19 से प्रभावित गंभीर लोगों को गहन चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकती है। यदि ब्रिटेन चीन के रास्ते पर चलता है तो पांच कोरोना संक्रमित रोगियों में से एक को गहन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। 40 मिलियन लोगों में इस अनुमान के अनुसार 8 मिलियन लोगों को गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी।

ब्रिटिश अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाइयों में 4,300 बिस्तर हैं। शायद एनएचएस इनकी संख्या बढ़ाकर 10,000 और कर ले। लेकिन, इससे 8 मिलियन गंभीर रोगियों को इस वर्ष आईसीयू बिस्तर नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार, 45,000 में से अधिकांश लोग मर जाएंगे। इस तरह यह पूरी योजना एक प्रकार का पागलपन है। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों में कोविड-19 की मृत्यु दर 8 प्रतिशत है। 80 वर्ष व उससे अधिक आयु वालों में यह 15 प्रतिशत है। इस प्रकार 70 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को वायरस संक्रमित होने की संभावना 70 वर्ष से अधिक आयु वालों की तुलना में अधिक लगती है। इसके साथ ही, कोविड-19 के अन्य पार्श्व प्रभाव भी हो सकते हैं। जिसने निबटने में दशकों लगेंगे। अनेक जीवित बचे लोगों में दीर्घकालीन समस्याओं की खबरें है। पुन: संक्रमण भी संभव है। कुछ संक्रमित लोग परीक्षण में नकारात्मक पाए जाने के बाद पुन: संक्रमित हुए हैं।

संभव है कि बोरिस जॉनसन के सलाहकार सही हों और बाकी सब गलत। हो सकता है कि संक्रमण की दूसरी लहर रोकी जा सके। लेकिन, हम यह नहीं जानते कि कोविड-19 की दूसरी लहर कैसी होगी। कोरोनावायरस जैसे सार्स के मामले में विलियम हेंग के अनुसार संकटग्रस्त लोगों को दोबारा निकट भविष्य में वायरस संक्रमण से बचना होगा। एशियाई देशों में नए संक्रमणों की संख्या घटी है जिन्होंने जल्दी परीक्षण प्रारम्भ किए तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। चीन में 81,000 संक्रमित लोग थे लेकिन विगत सोमवार को आई रिपोर्ट से केवल 7 नए मामलों का पता चला है। ब्रिटेन में कोई अधिकारी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है और वह जानबूझकर संक्रमण को अनदेखा कर रहा है। परीक्षण, संक्रमित लोगों का पता लगाना व सामाजिक दूरी बनाए रखना कोविड-19 से बचने का अच्छा रास्ता हो सकता है, लेकिन दूसरे देशों में संक्रमण बढ़ने पर यह नियम लागू नहीं होता। हाल ही में, दो दौर की बंदी के बाद 230 मिलियन चीनी फिर से काम पर लौट आए हैं।

लेकिन, यह रणनीति निश्चित रूप से ठीक है, जबकि प्रमुख ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, दि लांसेट के प्रधान संपादक, रिचर्ड हस्टन के अनुसार बोरिस जॉनसन की नीति जनता के साथ एक मज़ाक है। इस प्रकार मिनी ट्रंप और असली ट्रंप के बीच कोई अंतर नहीं है, और हार्ड इम्यूनिटी की मूर्खतापूर्ण बात का कोई अर्थ नहीं है। ब्रिटेन की जनता समझने लगी है कि जॉनसन की सरकार वास्तव में कोई योजना नहीं बना रही थी और वे अब इस पागलपन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं।

आप की बात

चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियां

डब्लूएचओ ने प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर 22.8 चिकित्साकर्मियों की संस्तुति की है और बाद में उसे बढ़ाकर 44.5 कर दिया गया। लेकिन, भारत में प्रति 10 हजार पर इनकी संख्या केवल 16 है। इस भारी कमी के कारण अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच नहीं पाते हैं, या उनको झोला छाप डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। अकसर हमें इसके दुष्परिणाम सघन जनसंख्या वाले इलाकों में देखने को मिले हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। पिछले साल अनेक बच्चे बिहार के मुजफ्फरनगर में गंभीर इंसेफेलाइटिस से मर गए थे। इस स्थिति से उपयुक्त चिकित्सीय देखभाल के द्वारा निबटा जा सकता है, हालांकि इनकी मौतों का कारण बच्चों में कुपोषण व अस्पताल की खराब व्यवस्थाएं भी हैं। कार्यबल के अभाव का मुद्दा संपूर्ण स्वास्थ्यरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है लेकिन आयुष्मान भारत द्वारा प्रस्तुत भारी मांग कहीं ज्यादा चुनौतियों को सामने लाएगी, जहां उच्च सापेक्ष मांग-आपूर्ति अंतर पैदा हो रहा है। निजी अस्पताल विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पैकेज में भाग नहीं ले रहे हैं। इस तरह समस्या का समाधान होने में पैदा बाधाएं बनी हुई हैं।

– **सविता वर्मा**, प्रयागराज

सीएए से दायित्व का निर्वहन

नागरिकता संशोधन कानून-सीएए न केवल हिंदुओं, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान के सभी उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को तेजी से भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव करता है। इसमें 'विशेष रूप से एक भी उत्पीड़ित मुसलमान को न लेने' का कहीं उल्लेख नहीं है। वास्तव में हालिया सप्ताहों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के अनेक मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है जिसके प्राविधान कानून में मौजूद हैं। सीएए ने वह वादा पूरा किया है जिसे भारत के नेताओं ने 1947 के बाद से अनदेखा किया था। अंतरराष्ट्रीय राजनय, शोध, सार्वजनिक संबंधों व मानवाधिकार पर सक्रिय सफादी केन्द्र के मेंडी सफादी ने कहा है, 'हाल के वर्षों में बांग्लादेश ऐसा देश बन गया है जहां बड़े पैमाने पर नस्ली हत्यायें तथा मुख्यत: मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं व लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। बड़ी संख्या में हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया ताकि मुसलमान उनकी जमीनों पर कब्जा कर सकें।' इस तरह सरकार ने मुस्लिम देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देकर कर्तव्य का निर्वहन किया है।

– **नीरज खंडेलवाल**, सीतापुर

आशंका प्रेरित विरोध

नस्ली असमी समूहों ने लगातार विधेयक का विरोध करते हुए इसे असम समझौते तथा हाल में जारी एनआरसी सूची के खिलाफ बताया है। उनका तर्क है कि इससे 'अहोम' पहचान प्रभावित होगी तथा मूल निवासियों का अपनी जमीन, संसाधनों व अवसरों पर अधिकार घटेगा। भाजपा इसके माध्यम से एनआरसी से बाहर छूटे लाखों हिंदू परिवारों का स्वत: पुनर्वास करना चाहती है। असमियों को इससे औपनिवेशिक काल में बंगाली हिंदू प्रवासियों की याद ताजा हो जाती है जिन्होंने उनके बिजनेसों व सामाजिक-आर्थिक संजाल पर कब्जा कर लिया था। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के कारण भी बड़ी संख्या में प्रवासी आ गए थे। असमवासियों को डर है कि यदि बराक घाटी के अवैध आप्रवासी बांग्लाभाषियों को नागरिकता मिल गई तो वे स्थानीय लोगों से अधिक हो जाएंगे जैसा त्रिपुरा में हुआ। वहां हिंदू बंगालियों ने मूल निवासियों के राजनीतिक स्पेस पर कब्जा कर लिया। असम में भाषाई व सांस्कृतिक गौरव ने भावनात्मक जनान्दोलनों को जन्म दिया है।

– **सुनील राज,** कानपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

फरमाया

संसद में मेरी उपस्थिति से विधायिका के समक्ष न्यायपालिका का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
– **रंजन गोगोई**
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश

यह नामांकन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं निष्ठा को पुन: परिभाषित करता है। यह अंतिम किला भी ध्वस्त हो गया।
– **मदन बी. लोकुर**
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

राज्यसभा चुनाव में बाहुबल व धनबल प्रयोग की भाजपा की राजनीति उजागर हो गई है। गुजरात कांग्रेस सदस्यों को रिश्वत देकर इस्तीफे दिलाए गए।
– **नवाब मलिक**
राकांपा नेता

यूपी में कोरोना नियंत्रण में लेकिन सतर्क रहें: योगी

मुख्यमंत्री ने की नवरात्र तथा अन्य धार्मिक आयोजन मंदिरों के बजाय घरों पर करने की अपील

● धर्म गुरुओ से आगे आकर वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार करने का किया आग्रह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिये उनकी सरकार ने काफी पहले से प्रयास शुरू कर दिये थे। इसी का परिणाम है कि राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की जंग जीतने के लिये लोगों से सहयोग मांगा है और नवरात्र तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान घरों पर ही मनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना फ्लू को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग डेढ़ माह पहले ही उपाय शुरू कर दिये थे। इसका परिणाम है कि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस बीमारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाये हैं। जनता के सहयोग से इस पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि कहीं भी भीड़ न इकट्ठी हो। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो, इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने धर्म गुरुओं से आगे आकर कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार करने की अपील की है। इस दिशा में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उन्होंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलें में धर्म गुरुओं से सम्पर्क व संवाद स्थापित कर उनके माध्यम से धार्मिक स्थलों पर एकत्रित न होने के लिए आमजन को जागरूक कराएं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ बल को निर्देशित किया है कि वे शहरों में इस बीमारी की रोकथाम में जनता को सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक नगर निगम में नियमित रूप से फॉगिंग करायी जाए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों मे वाहनों में माइक लगाकर कोरोना वायरस से बचाव का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए।

गेहूं खरीद टलने के आसार

● खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को पत्र लिखकर पन्द्रह दिनों के लिये खरीद का समय बढ़ाने की अनुमति मांगी

लखनऊ। कोरोना के चलते पहली अप्रैल से होने वाली गेहूं खरीद टलने के आसार हैं। करीब दो हफ्ते खरीद को टाला जा सकता है। खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को पत्र भेजकर कोराना का हवाला देते हुये खरीद को बढ़ाने की अनुमति मांगी है। राज्य में गेहूं खरीद का पंजीकरण कई दिनों पहले शुरू हो चुका है और योगी सरकार खरीद नीति को मंजूरी भी दे चुकी है। गेहूं खरीद नीति में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1925 रुपया प्रति कुन्तल के समर्थन मूल्य को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही सरकार गेहूं की छनाई और ढुलाई के रूप में 20 रूपये प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किसानों को करेगी। यह भुगतान योगी सरकार अपने पास से करेगी। खास बात यह है कि पिछले साल 50 लाख मीट्रिक टन की तुलना में सरकार ने खरीद का लक्ष्य पांच लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर 55 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। गेहूं खरीद के मौजूदा प्लान के मुताबिक पहली अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है। इसके लिये खाद्य एवं रसद विभाग सहित अन्य क्रय एजेन्सियों को कुल 45 सौ क्रय केन्द्र खोलने हैं। खरीद को लेकर शासन को लिखे गये पत्र में खाद्य एवं रसद विभाग ने कहा है कि कोरोना के खतरे के चलते निर्धारित समय पर क्रय केन्द्रों का खुल पाना कठिन होगा।

यूपी के बारे में देश-दुनिया नए तरह से सोचने पर मजबूर: डॉ. दिनेश शर्मा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी सरकार के तीन साल के कार्यकाल को अविस्मरणीय बताते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि तीन वर्षों में विकास और बदलाव की जो इबारत लिखी गई है उसने यूपी के बारे में अब देश और दुनिया को नए तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह तीन साल का समय छोटा जरूर है पर परिवर्तन ऐसे हैं जो कई दशकों तक लोगों के जीवन में सकारात्मक असर दिखाते रहेंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी कई मायनों में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में विकास और जन कल्याण के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब पीछे देखने का नहीं बल्कि आगे बढ़कर सपने पूरे करने का समय आ गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर आम लोगों को जीवन की सभी मूलभूत सुविधाए प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया है। आम आदमी को गैस, मकान, शौचालय, बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाए उपलब्ध कराई गई हैं। डॉ शर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है। इसीलिए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सरकार आमूलचूल बदलाव लेकर आई है। प्रदेश की तबाह हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को फिर पटरी पर लाने कवायद अब रंग लाने लगी है। पिछली सरकारों के समय में नकल के लिए कुख्यात हो चुका यूपी आज नकल विहीन परीक्षा के माडल के तौर पर उभरा है। प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबे लागू की गई हैं जो देश भर में सबसे कम दाम पर उपलब्ध हैं। निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक के लिए भी कानून बना है। शैक्षिक पंचाग बनाकर शिक्षण कार्य कराने का अनूठा प्रयोग भी इस सरकार में हुआ है। स्कूलों में अवकाश कम किए गए जिससे कि अधिकतम शिक्षण कार्य हो सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के प्रसार की पुख्ता व्यवस्था के साथ ही शोध पर विशेष जोर दिया गया है।

सीएसआर कॉन्क्लेव के सफल आयोजन पर यूनीसेफ ने योगी सरकार को सराहा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को यूनिसेफ ने 4 और 5 मार्च को आयोजित हुए राष्ट्रीय शिक्षा सीएसआर कॉन्क्लेव के सप ऊल आयोजन के लिए बधाई दी है। यूनिसेफ ने कहा कि इस कॉन्क्लेव में राष्ट्र निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यूनिसेफ की ओर से यूपी स्टेट चीफ रूथ लियानो ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से प्री-स्कूल शिक्षा के महत्व और उस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एक उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल कार्यक्रम छोटे बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हुए उन्हें एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व स्तर में ऐसे तथ्य सामने आये हैं कि गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अगर अच्छे होंगे तो आने वाले समय में शैक्षणिक उपलब्धि में सहायक होंगे। यूनिसेफ के द्वारा भारत में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिन बच्चों ने 5 वर्ष की आयु में स्कूल की तत्परता का स्तर प्राप्त किया है उन बच्चों ने स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के परिणामों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार प्री-स्कूल शिक्षा में प्रिशिक्षित किया जाए और एक सक्षम वातावरण के साथ उन्हें समर्थन दिया जाए तो बच्चों के आजीवन सीखने के लिए मजबूत नींव स्थापित करने में वो सफल होंगी। यूनिसेफ प्री स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के अपने प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है।

कलेक्ट्रेट में माई ट्री लखनऊ एप का उद्घाटन करते वित्तमंत्री सुरेश खन्ना व अन्य

किसानों के लिये विशेष राहत पैकेज केन्द्र को भेजा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● किसानों के नुकसान की भरपाई के लिये यूपी सरकार ने मांगे 358.57 करोड़

● करीब आठ लाख किसानों की कुल 2.89 हेक्टेअर फसल को हुआ नुकसान

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के 37 जिलों के किसानों को हुये भारी नुकसान पर योगी सरकार ने आज केन्द्र सरकार को विशेष राहत पैकेज का प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की इस पहल से प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव में जनहानि, पशुहानि, कृषि तथा मकानों के नुकसान की भरपाई के लिये केन्द्र से कुल 358.57 करोड़ की धनराशि योगी सरकार ने आपदा मोचक निधि से मांगी है।

विदित हो कि बीते फरवरी और मार्च माह में राज्य में बेमौसम बारिश के साथ-साथ कई बार ओलावृष्टि हुई है। जिसमें गेहूं, दलहन सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम योगी ने किसानों के नुकसान को देखते हुये इसकी भरपाई करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करके केन्द्र सरकार को मेमोरेन्डम भेजने के निर्देश दिये थे।

राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के बाद केन्द्र सरकार को आज विशेष राहत पैकेज के मेमोरेन्डम का प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 351.44 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है जबकि जनहानि के लिये 2.72 करोड़, पशुहानि के लिये 57.96 लाख तथा मकानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये 3.84 करोड़ की धनराशि मांगी गई है। जिसमें राज्य सरकार ने आपदा मोचक निधि से 249.02 करोड़ की धनराशि विभिन्न जिलों को स्वीकृति की है। केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव के मुताबिक ओलावृष्टि तथा बारिश से कुल 822100 किसान प्रभावित हुये हैं। जिसमें 794590 किसाना लघु और सीमांत है। इनमें से 2.89 लाख हेक्टेअर फसल को 33 फीसदी से अधिक का नुकसान हुआ है। इन्हीं किसानों को विशेष राहत पैकेज से नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक फसल के नुकसान का किसानों को कुल 351.43 करोड़ की धनराशि किसानों को दी जानी है, जिसमे विशेष राहत पैकेज के दायरे में आने वाले किसानों को छोड़कर बाकी को कृषि विभाग की फसल बीमा से मदद मिलेगी। राहत आयुक्त के मुताबिक राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार अभी तक किसानों की मदद के लिये 273.51 करोड़ की धनराशि स्वीकृति कर चुकी है। जिसमें 24.49 करोड़ फरवरी तथा 19 मार्च तक करीब 249 करोड़ की धनराशि हैं।

इन जिलों के किसानों को होगी नुकसान की भरपाई

लखनऊ। बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से जिन 37 जिलों के किसानों के नुकसान की भरपाई होगी उनमें लखनऊ भी शामिल है। इसके अलावा मीरजापुर, मथुरा, सीतापुर, चित्रकूट, अलीगढ़, प्रयागराज, बुलंदशहर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, बाराबंकी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, अमेठी, हरदोई, गोण्डा, आजमगढ़, सोनभद्र, कानपुर नगर, चंदौली, इटावा, अयोध्या, लखीपुर खीरी, एटा, पीलीभीत, बदायूं, औरैया, जालौन, गोरखपुर, जौनपुर, फतेहपुर, वाराणसी, शहजहांपुर, सुलतानपुर, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फनगर, मुरादाबाद, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कन्नौज, कानपुर नगर, हापुड़, संतकबीर नगर, मेरठ, मऊ, अम्बेडकर नगर, सहारनुपर, कासगंज, देवरिया, अमरोहा, बरेली, सम्भल, मैनपुरी, बस्ती, बांदा, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, महोबा, कुशीनगर, महाराजगंज, ललितपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बागपत, बिजनौर, रामपुर, आगरा, फरुर्खाबाद, शामली, झोसी, उन्नाव, हाथरस तथा बहराइच हैं।

पिछले तीन साल में गुंडाराज, भ्रष्टाचार चरम पर: अखिलेश

● मुस्लिमों के उत्पीड़न में नंबर वन है उत्तर प्रदेश की सरकार: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार के तीन साल पूरे होने पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को खराब स्वास्थ्य सेवाएं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में, जातिवाद को बढ़ावा देने में और अल्पसंख्यकों व मुसलमानों के उत्पीड़न में नम्बर वन करार दिया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले तीन साल के दौरान गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर है।

सपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछले तीन साल की सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर है। वह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों की आय आधी रह गई है। सपा के 14 विधायक और विधान परिषद सदस्य 29 फरवरी को महोबा गए और वहां उन 65 किसानों के परिजन से मुलाकात की जिन्होंने वित्तीय संकट के चलते आत्महत्या की। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे का खंडन किया कि भाजपा की सरकार नंबर एक है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने, शिक्षा, मिड डे मील, फर्जी मुठभेड़, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, बलात्कार पीड़ितों के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मोर्चे पर विफलता के मामले में नंबर एक है। उन्होंने कहा कि यह दमदार नहीं बल्कि अनिर्णायक सरकार है। बीजेपी सरकार पर पिछली सपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को अपना नाम देने का आरोप लगाते हुये अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जातिवाद को बढ़ावा देने और मुस्लिमों के उत्पीड़न में नम्बर वन हैं। मौजूदा योगी सरकार को झूठ बोलने में नम्बर वन कहा जाये तो गलत नहीं होगा। इस सरकार को सपा की योजनाओं को अपना बताने की बजाय चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वायदों को निभाने के लिये काम करना चाहिये। पूर्वांचल एक्सप्रेस और मेट्रो रेल की प्रक्रिया सपा सरकार के शासनकाल में शुरू हुयी वहीं राज्य में एम्स के निर्माण के लिये उनकी सरकार ने ही केन्द्र को जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा कई परियोजनाएं उनके ही कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी जिन्हें मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है। श्री यादव ने कहा कि सरकार को अपना संकल्प पत्र पलटना चाहिए, गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में दमदार सरकार नहीं, बल्कि निर्णय न लेने वाली सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार के काम को अपना बताने की आदत को छोड़कर मुख्यमंत्री को सच बोलना चाहिए। उनको कम से कम अपनी सरकार के शुरू किये गये एक काम तो बताना चाहिये। उनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुयी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर ही काम चल रहा है। वह सिर्फ यह ही बता दें कि गोरखपुर में मेट्रो कब शुरू होगी। भाजपा सरकार में दंगा नहीं होने के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब दंगा कराने वाले सरकार चला रहे हों तो ऐसे में इन वारदातों का कोई सवाल नहीं है और वैसे भी भाजपा खुद के राजनीतिक लाभ के लिये दंगा कराती है। सपा सांसद आजम खां के प्रति हमदर्दी का इजहार करते हुये उन्होंने कहा कि श्री खां के साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। मुसीबत की इस घड़ी में पूरी पार्टी श्री खां और उनके परिवार के साथ खड़ी है।

कोरोना को लेकर सपा ने रद किए सभी कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये योगी सरकार के ऐहितयाती उपायों को नाकाफी बताते हुये सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिये सतर्क रहना होगा।

उन्होने कहा कि सपा अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये हैं और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह नवरात्र का व्रत अपने घरों में रह कर करें। इस अवधि में अपने फोन के करीब रहें एवं किसी की मदद के लिए आगे आएं। अब 22 अप्रैल के बाद सपा की साइकिल फिर से फर्राटा भरेगी। उन्होंने ने कहा कि कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में निर्यात काफी प्रभावित हुआ है। यहां का कारोबारी अपने सामान का निर्यात नहीं कर पा रहा है। अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है जबकि प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने की बात कही जा रही है जो सरकार की मौजूदा नीतियों और हालात से संभव नहीं है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण को महामारी मानने को ही तैयार नहीं हैं। इससे तो लगता है कि वह इस आपदा को लेकर जरा भी गंभीर नहीं हैं। प्रदेश के किसी भी अस्पताल में इसकी जांच की अच्छी सुविधा नहीं है। न अस्पतालों में न दवाई है ना इलाज मिल पा रहा है। ऐसे में जनता कोरोना से कैसे मुकाबला करेगी। पार्टी ने 23 मार्च से अपना साइकल चलाने का कार्यक्रम निरस्त किया है।

गरीब मरीजों के लिए अस्पतालों में निशुल्क इलाज: डॉ. बद्री विशाल

● 2019-20 में अब तक 40.21 लाख रुपये कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज पर खर्च

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गरीब मरीजों के इलाज को लेकर सरकार काफी सजग है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को इलाज पर अपनी गाढ़ी कमाई न खर्च करनी पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा के साथ ही राज्य आरोग्य निधि की भी स्थापना की गयी है। मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। गुरुवार को यह जानकारी महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ. बद्री विशाल ने दी है।

उन्होंने बताया कि असाध्य व जटिल रोगों की जांच और इलाज के लिए पहले रोगियों को प्राथमिक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इलाज किया जाता है, वहां इलाज की सुविधा न होने पर जिला अस्पताल रेफर किया जाता है और वहां भी इलाज संभव न होने पर प्रदेश के मेडिकल कालेज व चिकित्सा संस्थानों में इलाज के लिए रेफ र किया जाता है। महानिदेशक, परिवार कल्याण ने बताया कि वर्ष 2008 से चल रही इस योजना का लाभ अभी तक प्रदेश के तमाम ऐसे लोग उठा चुके हैं जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे किन्तु पैसे के आभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में 1.37 करोड़, 2018-19 में 40.59 लाख और 2019-20 में अब तक 40.21 लाख रूपये कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज पर खर्च किये गए हैं।

इन बीमारियों का होता है इलाज

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष के तहत कई असाध्य व जटिल बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है। जिसमें प्रमुख रूप से हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दा व मूत्र रोग, अस्थि रोग, थैलेसीमिया आदि हैं। इन बीमारियों के उपचार पर खर्च होने वाली डेढ़ लाख तक की राशि की स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति कर सकती है, इससे अधिक की राशि की स्वीकृति राज्य स्तर पर गठित समिति करती है।

जनता की आशाओं को पूरा करने में विफल साबित हुई सरकार

● यूपी करे सवाल, क्या किया तीन साल शीर्षक से बुकलेट जारी कर कांग्रेस ने साधा योगी सरकार पर निशाना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश सरकार के तीन साल के कार्यकाल के पूरे होने पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी करे सवाल, क्या किया तीन साल शीर्षक का बुकलेट जारी करके योगी सरकार सरकार पर तीखा निशाना साधा। योगी सरकार के तीन साल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक वेबसाइट भी लान्च की, जिसमें पिछले तीन साल के योगी सरकार के छात्र, युवा, महिला, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी कारनामे दर्ज हैं।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के आज तीन साल पूरे होने पर एक दिन पूर्व ही कल मुख्यमंत्री द्वारा की गयी अपनी आत्म प्रशंसा पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार जन मुद्दों पर सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही है, जनहित की लड़ाई लड़ती रही, अपना आरोप पत्र जनता के समक्ष आपके द्वारा रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले तीन वर्षों में समाज के किसी भी वर्ग की आशा और आकांक्षा को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण इस सरकार में हमारी बहन, बेटियों के साथ रहा, जहां उन्नाव में तीन-तीन बलात्कार की क्रूरतम घटनाएं हुईं, वहीं शाहजहांपुर में इस घटना के अंजाम के आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद एवं पूर्व गृह राज्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित बच्चियों के साथ न्याय करने के बजाए लगातार अपने को बचाने में लगी रही। ऐसे में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा बेईमानी साबित होता है। नेता विधान परिषद दल दीपक सिंह ने कहा कि यह सरकार किसानों और युवाओं से किये गये अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरीके से अक्षम साबित रही। जहां बेरोजगारी इन तीन सालों में साढ़े 12 लाख बढ़कर 40 लाख से ऊपर चली गयी वहीं किसानों की आत्महत्या दर देश में सर्वाधिक है। विधायक सोहेल अंसारी ने बुनकरों की समस्या पर कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है परन्तु अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े तबके बुनकर, जिसमें बड़े भाग का जीवन लूम और करघा पर आधारित है उसके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कुछ नहीं किया।

अनुसूचित जाति के चेयरमैन आलोक कुमार पासी ने इस सरकार में दलित उत्पीड़न और दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात की बात उठाते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार पूर्व में दिए गए दलित के अधिकारों और हितों को समाप्त करने पर उतारू है और आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती हैं।

कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप

- होली के चलते टर्की से लौटा था इनवर्टर व्यवसाई
- होली के बाद बिगड़ी हालत
- लखनऊ में जांच कराने पर हुई थी पुष्टि

संवाददाता। मैगलगंज-खीरी

मैगलगंज कस्बे में कोरोना पाजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज को केजीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जबकि स्वास्थ्य महकमें की टीम करौना पीड़ित मरीज के परिजनों को जिला मुख्यालय ले गई है।

बताते चलें कि मैगलगंज कस्बा के इंवर्टर बैटरी व्यवसाई उमा शंकर पांडे 3 मार्च को कंपनी द्वारा आयोजित एक टूर पर इस्तांबुल (टर्की) गए थे। जहां से वह 8 मार्च को वापस आए थे। होली के बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी। उन्होंने स्थानीय स्तर पर इलाज कराया। उसके बाद वह सीतापुर जिला चिकित्सालय पहुंचे एवं राहत न मिलने पर वह सीतापुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. प्रमोद कुमार धवन के यहां भी इलाज कराते रहे। स्थिति सही न होने के बाद कल जब वह लखनऊ पहुंचे तब डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें कोरोना प्रभावित घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार की सुबह जब यह खबर कस्बे में फैली तो लोगों में दहशत फैल गई। जिन लोगों से वह मिले उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। दोपहर 2 बजे लखीमपुर मुख्यालय से डिप्टी सीएमओ बलबीर सिंह के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य टीम मैगलगंज कस्बे में पहुंची जहां से वह घर के सभी छह सदस्यों को अपने साथ लखीमपुर ले गए। डा. बलवीर सिंह ने बताया कि परिजनों को लखीमपुर में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम को नमूना देकर भाग गया कोरोना वायरस का संदिग्ध

मथुरा। कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा एक अधेड़ व्यक्ति सरकारी टीम का इंतजार करते-करते इतना परेशान हो गया कि जैसे ही टीम उसका नमूना लेकर वहां से गई, वह वहां से नदारद हो गया। अब स्वास्थ्य विभाग फोन से संपर्क कर उससे वापस आने की गुहार लगा रहा है। यह घटना बुधवार की है। मामले का पता चलने पर जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ शेर सिंह को हरसंभव तरीके से इस संदिग्ध को लाने और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेण्टर में बनाए गए पृथक वार्ड में दाखिल करने को कहा है। यदि जांच के नतीजे में पता चलता है कि उसे संक्रमण नहीं है तो उसे जाने दिया जाएगा। जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक कॉलोनी निवासी 47 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति खांसी, बुखार, छींक सहित कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों की शिकायत लेकर छाता के निकट स्थित केडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि वह कारोबार के लिए छह मार्च को मुम्बई गया और 11 मार्च को लौटा। इस व्यक्ति का दावा है कि ट्रेन में जिस डिब्बे में वह यात्रा कर रहा था, उसी में एक विदेशी भी था। उसने आशंका जताई कि उस विदेशी को कोरोना वायरस का संक्रमण रहा होगा और शायद वह भी उसकी चपेट में आ गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम को सूचित किया। टीम के सदस्यों को अस्पताल पहुंचने में छह घंटे लगे। इस बीच कथित पीड़ित के घरवाले उसे बार-बार फोन कर जांच का परिणाम पूछते रहे, जबकि असलियत का पता जांच के बाद चलता। जांच दल ने केडी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल जा कर उसका नमूना लिया और अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा। लेकिन तब तक कथित पीड़ित वहां से नदारद हो गया। उसके गायब होने से अस्पताल प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मच गया। उसकी तलाश की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ शेर सिंह ने बताया हम फोन पर उससे संपर्क कर रहे हैं।

उधार की रकम वापस मांगने पर युवक की हत्या

बलरामपुर। नगर कोतवाली में उधार की रकम वापस मॉंगने पर कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मार कर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को जानकारी देते हुए बताया कि नगर कोतवाली से सटे अलीजनपुरवा में बुधवार की देर रात उधार की रकम वापस मॉंगे जाने को लेकर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल मैकेनिक हारून (32) को पहले लाठी डंडों से पीटा फिर गोली मार कर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नगर कोतवाली में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की दो टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

गोवर्धन परिक्रमा मामला

पेश न होने पर एनजीटी ने लगाया प्रमुख वन सचिव पर जुर्माना

संवाददाता। मथुरा

जिले के गोवर्धन कस्बे में गिरिराज परिक्रमा के विकास को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को अनुपस्थित रहने पर राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने दी।

गोवर्धन परिक्रमा संरक्षण समिति के बाबा आनन्द गोपाल दास एवं सत्यप्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी तथा राहुल शुक्ला ने सरकारी विभागों द्वारा गोवर्धन एवं राधाकुण्ड में परिक्रमा मार्ग में सीवर और जलभराव की समस्याओं की जानकारी देते हुए सर्विस रोड के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर विभागीय प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण ने सर्विस रोड की प्रगति से अवगत कराया। तब अदालत ने जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अधिकरण को कार्यवाही जल्द पूरी कर सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। एनजीटी की मुख्य पीठ में सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव (पर्यावरण व वन) सुधीर गर्ग के उपस्थित न होने पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस बार उन पर केवल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन दोबारा ऐसा होने पर, अदालत का समय बर्बाद करने के लिए इससे कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। अदालत ने सरकारी अधिवक्ता अमित तिवारी के माफी देने के आग्रह को अनसुना कर अगली तारीख पर गर्ग को अवश्य उपस्थित होने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

कोरोना वाइरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्लेटफार्म टिकट की दर बढ़ी

बरेली। कोरोना वाइरस (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से तथा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने के काठगोदाम, रुद्रपुर सिटी, लालकुआं, हल्द्वानी, काशीपुर, पीलीभीत, कासगंज, कन्नौज, फर्रुखाबाद एवं बरेली सिटी रेलवे स्टेशनों पर 19 मार्च, 2020 (00.01 बजे) से प्लेटफार्म टिकट की दर रु. 10 से रु. 50 अगली सूचना तक कर दी है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश कुमार सिंह ने सभी रेल यात्रियों एवं रेल उपयोगकर्त्ताओं से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपने महत्वपूर्ण सहयोग रेल प्रशासन प्रदान को प्रदान करें। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशनों का अनुपालन करते हुए अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही टेऊन यात्रा करें और रेलवे प्लेटफार्मों पर बेवजह जाने से बचें।कोरोना वायरस से बचाव को जन विकास वेलफेयर सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट पर बाटे मॉस्क बरेली जन विकास वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन कुमार सक्सेना एंव सचिव सुमित शर्मा के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट गेट पर लोगों को मॉस्क एव पम्पलेट बांट के लोगों को कोरोना वायरस के वारे जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें कलैक्ट्रेट स्थित सभी ऑफिसों एंव वकीलों चौमबरों , दुकानों में जाकर पम्पलेट देकर कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कर इसके बचाव एंव लक्षण के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई एंव लोगों को सोसाइटी द्वारा जारी किये गये हेल्पलाईन नम्बर की भी जानकारी दी गई जिसपर लोगों द्वारा किसी भी कोरोना वायरस के सदिग्ध व्यक्ति की जानकारी देने पर सोसाइटी द्वारा तुरन्त उसको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जायेगी । इस मौके पर कल लोगों की सहायता एंव मदद के लिये सोसाइटी द्वारा एक हैल्पलाइन नम्बर - 8755462706 भी जारी किया गया था।

एनपीआर में बेघर परिवारों को किया जाएगा शामिलः निदेशक

प्रयागराज। निदेशक जनगणना एवं नागरिकता पंजीकरण उत्तर प्रदेश नरेंद्र शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरूवार को गांधी सभागार में जनगणना 2021 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। जिसमें उन्होंने बताया कि जनगणना का कार्य मोबाइल एप से सम्पन्न करने वाले प्रगणकों को प्रतिमाह 25000 रूपये भुगतान की व्यवस्था है। जनगणना का कार्य दो चरण में सम्पन्न होगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करना होगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना अर्थात वास्तविक जनगणना का कार्य किया जायेगा। जनगणना में लोगों से मकान, ईधन प्रकार, पेयजल एवं प्रकाश के ब्योरे की जानकारी ली जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रयागराज मंडल की जनगणना संबंधी कार्यों में तेजी लायें। प्रशिक्षण का लाभ उठाकर कार्य की गति को बढ़ायें। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं लगकर अपने अधीनस्थों के माध्यम से जनगणना सम्बंधी कार्य समय से सम्पन्न करायें। किसी भी कठिनाई या समस्या का समाधान के लिए मण्डलस्तर पर मण्डल प्रभारी, जिले स्तर पर जिले प्रभारी उपलब्ध रहेंगे।

किसानों को राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाए आर्थिक सहायताः सतीश द्विवेदी

- प्रभारी मंत्री ने की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से नुकसान की समीक्षा

संवाददाता। सोनभद्र

प्रदेश की सरकार किसान भाइयों के हितों के प्रति काफी संजीदा है। दुर्भाग्य वश कुछ दिन पहले बेमौसम की बरसात अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से जिले में किसान की फसलों की हुई नुकसानी की भरपाई सरकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। सोनभद्र जिले के 69 प्रभावित ग्रामों के 6 हजार 301 किसानों के 2 हजार 660 हेक्टेयर फसल की ओलावृष्टि से हुई क्षति नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। राबर्ट्सगंज तहसील के 26 प्रभावित गांवों के 819 किसानों, दुद्धी तहसील के 11 प्रभावित गांवों के 880 व घोरावल के 32 प्रभावित गांवों के 4 हजार 602 किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति उनके खातों में जल्द से जल्द भेजी जाए। उक्त निर्देश पर प्रदेश के राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जिले में अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हुई फसलों की नुकसानी, पशु व जनहानि की समीक्षा करते हुए सम्बन्धितों को दिये। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 69 गांवों की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई जिसके तहत 6 हजार 301 किसानों के 2 हजार 660 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है, जिसमें 6 हजार 301 किसानों को 2 करोड़ 80 लाख 63 हजार 238 रूपये के भुगतान के लिए मेमोरेण्डम शासन को भेजा गया है और अब तक कोषागार नियम-27 के तहत 1 करोड़ 4 लाख 95 हजार 325 रूपये का आहरण कर जिले के 3 हजार 188 किसानों का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया है। बाकी बचे 3 हजार 113 किसानों को जल्द से जल्द अनुदान सीधे उनके खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले में अतिवृष्टि आकाशीय विद्युत ऑधी-तूफान से हुई जनहानि पशुहानि मकान क्षति के मामले में जिले में 381 पाये गये जिसके सापेक्ष जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति के प्रभावित 381 परिवारों को कोषागार नियम-27 के तहत 42 लाख 26 हजार 800 की धनराशि आहरण कर वितरण किया जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने जिले में अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हुई फसल हानि जनहानि पशु हानि आदि का बेहतर तरीके से दोबारा परीक्षण कराकर और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली जानकारी का संज्ञान लेकर शासन की मंशा के अनुरूप सभी प्रभावित किसानों व परिवारों को अनुदान की राशि शत-प्रतिशत मुहैया करायी जाय। उन्होंने समीक्षा के दौरान सम्बन्धितों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज जिले में नहीं है, फिर भी कोरोना वायरस के बचाव सम्बन्धी व्यापक प्रचार-प्रसार गांव स्तर तक करके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के प्रति नागरिको को जागरूक किया जाय। उन्होंने कहा कि किसान फसल बीमा योजना का लाभ शत-प्रतिशत किसानों को दिया जाय। बैंकों के माध्यम से जिन किसान भाईयों का फसल का प्रीमियम काटा जा चुका है, उनको हर हाल में फसल बीमा का लाभ दिया जाय। अतिवृष्टि ओलावृष्टि सम्बन्धी समीक्षा बैठक में प्रभार मंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी के अलावा जिलाधिकारी एस. राजलिंगम पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जिलाध्यक्ष भाजपा अजीत चौबे विधायक सदर भूपेश चौबे विधायक ओबरा संजीव गौंड़ विधायक दुद्धी हरिराम चेरो सांसद प्रतिनिधि कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे।

पेज एक का शेष

22 मार्च को ...

विकासशील देश के लिए यह संकट कोई सामान्य बात नहीं है। जब विकसित देशों में इसका व्यापक प्रभाव हुआ है तब यह यह मानना कि भारत पर कोई असर नहीं होगा गलत है। इस महामारी से मुकाबले के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला संकल्प और दूसरा संयम। 130 करोड़ भारतवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि इस महामारी से पार पाने के लिए बतौर नागरिक अपने कर्तव्यों- केंद्र-राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। यह संकल्प लेना होगा कि खुद संक्रमित लोगों से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। इस वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र कारगर है कि हम स्वस्थ तो जगत स्वस्थ। ऐसी हालत में जब कोई दवा नहीं है तब खुद का स्वस्थ रहना जरूरी है। दूसरी अनिवार्यता है संयम। इसकी तरीका है घर से निकलने व भीड़ से बचे रहना। दुनिया भर में जिसे सोशल आइसोलेटिंग कहा जा रहा है, वही इसके लिए सबसे जरूरी भी है और प्रभावी भी। प्रधानमंत्री ने संकल्प व संयम पर बल देते हुए कहा कि यह कोरोना महामारी की रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगा। यदि आपको यह लगता है कि आप ठीक हैं और आपको कुछ नहीं होगा। आप घूमेंगे फिरेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे तो यह सोच सही नहीं। ऐसा करके आप अपने और अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। उनका आग्रह है कि अगले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें। यथासंभव अपना काम घर से ही करें। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए निकलना जरूरी है लेकिन अन्य लोगों को भीड़भाड़ व समारोहों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। जिस परिवार में 60-65 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग हों वे घर से कतई न निकलें। उनका यह अनुरोध भी है कि अस्पतालों पर बेवजह का दबाव बनाने से भी लोग बचें। रूटीन चेकअप के लिए वहां न जाएं और संभव हो तो सर्जरी की तारीख भी एक माह के लिए आगे बढ़ा दें ताकि अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज प्राथमिकता से किया जा सके। इसी संदर्भ में अतीत में युद्ध की स्थिति में होने वाले ब्लैकआउट का हवाला देते प्रधानमंत्री ने बताया कि सामान्य दिनों में भी ब्लैकआउट की ड्रिल की जाती थी ताकि लोगों को इसकी आदत बनी रहे। वे भी देशवासियों से जनता कर्फ्यू के लिए वैसा ही समर्थन मांग रहे हैं।

लोगों को खाने-पीने की वस्तुओं, दवा एवं अन्य जरूरी सामानों को इकट्ठा करने की होड़ से बचने की सलाह देते प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इन वस्तुओं की कोई कमी न होने पाए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल रखने को हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं इसलिए वे यह कहना चाहते हैं कि देशवासी दहशत में आकर खरीदारी न करें। वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे व्यापक प्रभाव का जिक्र करते प्रधानमंत्री ने बताया कि आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स गठित की है जो संबद्ध पक्षों से फीडबैक लेगी, स्थिति का आकलन कर कदम भी उठाएगी। देश के मध्यम, निम्न मध्यम वग और गरीबों के हितों पर इस महामारी ने गहरी चोट पहुंचाई है, यह कहते प्रधानमंत्री ने संपन्न लोगों व कारोबारियों से अनुरोध किया कि वे अपने यहां काम करने वालों के आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है कि वे लोग काम पर न जा पाएं लेकिन उनका वेतन न काटा जाएगा। उनके साथ मानवीय आधार पर संवेदनशील बर्ताव करें क्योंकि इन्हें भी अपना परिवार पालना होता है। अंत में उन्होंने कहा कि दिक्कतें तो हैं लेकिन इनके बीच ही मजबूत संकल्प व संयम के साथ कोरोना महामारी का मुकाबला करना होगा। अभी हर किसी को अपना पूरा सामर्थ्य खुद को बचाए रखने में लगाना चाहिए। जरूरी है कि इस वातावरण में मानव जाति और भारत विजयी हो। कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली है जो कि शक्ति उपासना का पर्व है। भारत पूरी शक्ति से आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ धैर्य रखते हुए खुद बचें, देश और दुनिया को बचाएं।

चौथी मौत...

हैं। प्रमुख तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में एशिया के अन्य बाजारों की तरह ही गिरावट रही। सेंसेक्स दोपहर में कुछ समय की तेजी के बाद बिकवाल के दबाव में आ गया। यह अंत में 581.28 अंक यानी 2.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,288.23 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 2,656.07 अंक का उतार-चढ़ाव आया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205.35 अंक यानी 2.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,263.45 अंक पर बंद हुआ।

इस वायरस के देश भर में फैलना जारी रहने के बीच कश्मीर घाटी सहित देश के कई हिस्से बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल, प्रशासन कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रहा है और श्रीनगर शहर में सभी सार्वजनिक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब और दिल्ली भी आंशिक रूप से बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार आधी रात से सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं स्थगित करने और लोगों के जमावड़ों में व्यक्तियों की संख्या 20 से कम करने के अलावा विवाह भवन, होटल और रेस्तरां आदि बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, होम डिलीवरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। उल्लेखनीय है कि समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस वायरस के संक्रमण से 9,020 मौतें हुई हैं जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 8,648 लोगों की मौत हुई है। वहीं, दो लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं।

केंद्र सरकार ने 22 मार्च से 29 मार्च तक देश में आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का अनुरोध किया है। इनमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो आपात एवं आवश्यक सेवाओं में काम करते हैं। सरकार के बयान में कहा गया है, राज्य सरकारें उपयुक्त निर्देश जारी करें, ताकि जन प्रतिनिधियों या सरकारी सेवकों या मेडिकल पेशेवरों को छोड़ कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों (मेडिकल सहायता पाने वालों को छोड़ कर) को घरों में ही रहने की सलाह दी जाए। सरकारी आदेश में कहा गया है, 22 मार्च 2020 की देर रात से एक हफ्ते के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान को भारत में उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि इसी तरह 10 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। इस वायरस को फैलने से रोकने की अपनी कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है और शेष कर्मचारी तीन समूहों में अलग-अलग अवधि के लिए रोजाना कार्यालय आएंगे। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में गुरुवार को इस सिलसिले में निर्देश जारी किए गए। निजी एयरलाइन इंडिगो ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की घोषणा की है जिसके तहत इसके सीईओ के वेतन में सर्वाधिक 25 फीसदी की कटौती की जाएगी। गौरतलब है कि इस महामारी से विमानन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 173 हो गई है। इनमें 25 विदेशी नागरिक... 17 इटली के, तीन फिलीपीन के, दो ब्रिटेन और कनाडा, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर का एक-एक नागरिक हैं। इन आंकड़ों में अभी तक पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक-एक व्यक्ति की हुई मौतें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज राज्य के लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ठाकरे ने विषाणु के खिलाफ युद्ध में लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा कि सरकार की अपील के बाद सार्वजनिक स्थलों पर जाने वालों और सार्वजनिक यातायात प्रणाली का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। दिल्ली में अभी तक एक विदेशी नागरिक सहित कुल 12 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में तीन विदेशियों सहित 47 मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में 19, केरल में दो विदेशियों सहित 27, कर्नाटक में 14, लद्दाख में आठ, जम्मू-कश्मीर में चार और तेलंगाना में दो विदेशियों सहित छह मामलों की पुष्टि हुई है। राजस्थान में दो विदेशियों सहित सात, तमिलनाडु तीन और पंजाब में दो, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में एक-एक मामलों की पुष्टि हुई हैं वहीं हरियाणा में 14 विदेशी नागरिकों सहित 17 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच, मुंबई में टिफिन सेवा प्रदान करने वाले डब्बावाला ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार से 31 मार्च तक अपनी सेवाएं स्थगित कर दी है। दक्षिण दिल्ली के सुंदर नगर मार्केट को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

रेस्तरां बंद...

बैजल ने सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों को गतिविधियों को अलग-अलग बांटने और सभी गैर जरूरी सेवाएं स्थगित करने को कहा है। इससे पहले एलजी बैजल ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए 20 से अधिक लोगों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जमावड़े पर रोक रहेगी। हम काबू करने के स्तर पर कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं और यह समुदाय के स्तर पर नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को पृथक रहने को कहा गया है, वे नियमों का अनुपालन करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कोरोना वायरस से 10 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि एक की मौत हुई है।

विपक्ष की ...

उन लोगों में पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं जिन्हें मनोनीत किया गया था। नायडू ने कहाकि हमें सदस्य का सम्मान करना चाहिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई सदस्यों ने गोगोई को बधाई दी। वह सदन में मनोनीत सदस्य सोनल मान सिंह के पास वाली सीट पर बैठे थे। गौरतलब है कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था।

निर्भया के ...

समय वह दिल्ली में नहीं था। शर्मा ने दलील दी थी कि दस्तावेजों से पता चलता है कि वह इस अपराध के वक्त राजस्थान के करोली में था और उसे बाद में पुलिस दिल्ली लाई थी। पीठ ने इस समय इन नए साक्ष्यों पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत ने सारे तथ्यों पर विचार किया था और इसके बाद ही अपना विस्तृत फैसला सुनाया था जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा। इसी पीठ ने इसके बाद एक अन्य मुजरिम अक्षय की याचिका पर विचार किया। अक्षय ने इस याचिका में राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका दुबारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि दया याचिका खारिज करते समय राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करने संबंधी दलील स्वीकार करने की कोई वजह नहीं है। पीठ ने अक्षय के वकील एपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दया याचिका अस्वीकार करने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। अक्षय ने राष्ट्रपति के पास बुधवार को दुबारा दया याचिका दायर की थी जो बृहस्पतिवार को अस्वीकार कर दी गई थी। सिंह ने दलील दी थी कि न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि अक्षय को एकांत में रखा गया और पुलिस और जेल में कैदियों ने उसे यातनाएं दीं जिनसे पता चलता है कि वह बीमारी से ग्रस्त है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को दायर करने के लिए बनाए गए सारे आधारों को अस्वीकार कर दिया। निचली अदालत ने पांच मार्च को इस सनसनीखेज अपराध में दोषी ठहराए गए चारों मुजरिमों-मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह- को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे। इन मुजरिमों ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस सनसनीखेज अपराध के एक आरोपी राम सिंह ने 2013 में कथित रूप से तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी किशोर था जिसे तीन साल बाद सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था।

पौने दो सौ साल में पहली बार वृंदावन के श्री गोदा रंग मन्नार मंदिर में रथ खींचने की परंपरा टली

मथुरा। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए वृंदावन के श्री गोदा-रंग मन्नार मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव के दौरान रथ को खींचे जाने की परंपरा टाल दी गई है। मंदिर की स्थापना के पौने दो सौ साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

वृन्दावन के श्री गोदा-रंग मन्नार मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा श्रीनिवासन ने गुरुवार को बताया कि मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव कार्यक्रमों के तहत भगवान रंगनाथ की रथयात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के शामिल होने व उसके पहियों में बंधे बड़े-बड़े रस्सों को खींचकर रथ को मंदिर से बागीचे तक ले जाने वाली रथयात्रा के स्वरूप में परिवर्तन कर भगवान को रथ पर विराजमान कराया गया, परंतु दूर से ही दर्शन करने की व्यवस्था रखी गई। हालांकि, रथ को खींचे जाने की परंपरा टाल दी गई। यह इस मंदिर की स्थापना के पौने दो सौ साल में पहली बार हुआ है। वहीं, दुनिया भर के कृष्णभक्तों के आकर्षण का केंद्र माने जाने वाले श्रीकृष्ण जन्मस्थान में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी के साथ-साथ दर्शन का समय भी घटा दिया गया है। यह जानकारी मंदिर के सचिव कपिल शर्मा ने दी। केशोपुरा स्थित प्राचीन केशव देव मंदिर में सुबह 10 से 11 बजे तक होने वाली कथा के साथ शाम 5 से 6 बजे तक होने वाले सामूहिक कीर्तन को बंद कर दिया गया है। मीडिया प्रभारी नारायण प्रसाद शर्मा के अनुसार दर्शन में 15 मिनट कटौती कर दी गई है जिससे दर्शनार्थियों का दबाव कम से कम रहे। ठा. द्वारिकाधीश मंदिर के मीडिया एवं विधि प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया, बुधवार सुबह से मंदिर में दर्शनों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। प्रत्एक सेवा के दौरान मंदिर खुलने का समय तो वही रखा है परंतु दर्शन बंद करने का समय 15 मिनट पूर्व कर दिया गया है। उन्होंने बताया, मंदिर के गर्भगृह में रहकर सेवा-पूजा करने वालों को कोरोना वायरस के चलते और भी ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वे अब बहुत ज्यादा आवश्यक होने की स्थिति में ही मंदिर परिसर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार, वे भक्तों से सीधे माला या अन्य कोई सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए एक टोकरी का प्रयोग करेंगे और भक्तों से पुष्प, द्रव्य व सामग्री टोकरी में ही अर्पित करवाई जाएगी। कपिल शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से मुक्ति और समग्र समाज को संकट मुक्त रखने के उद्देश्य से श्रीकृष्ण जन्मस्थान में बुधवार को सुदर्शन कवच का पाठ और हवन का आयोजन हुआ। इसमें रोगमुक्ति और विश्व शांति के लिए आहुतियां दी गईं। जन्मस्थान में श्रद्धालुओं की संख्या काफी घट गई है।

मकान को गेस्ट हाउस बना 20 विदेशियों को ठहराने वाले मालिक-मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक मकान के मालिक और उसे गेस्ट हाउस के रूप में संचालित करने वाले कथित मैनेजर के खिलाफ 20 विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस व प्रशासन को सूचना दिए अपने यहां ठहराने के आरोप में विदेशी अधिनियम की प्रासंगिक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया, ग्वालियर निवासी रमेश चंद्र अग्रवाल ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में ब्रज दर्शन धार्मिक ट्रस्ट की स्थापना कर अपने मकान को एक गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया था। उसने बिना पुलिस या जिला प्रशासन को सूचित किए उस मकान में लोगों को ठहराना शुरु कर दिया। इस बीच, जब कोरोना वायरस संक्रमण की संभावनाओं को रोकने के लिए सभी होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में जाकर वहां अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान गोवर्धन में उक्त गेस्ट हाउस में 20 विदेशी नागरिक ठहराए गए मिले। इनके बारे में कई बार सूचित किए जाने के बाद भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी।

सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लेकर सहमति कायम करने के लिए प्रयासरतः प्रसाद

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने गुरूवार को कहा कि वह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करना चाहती है और इस बारे में विभिन्न पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि इस सेवा के चार क्षेत्र होंगे और इसमें भाषा को लेकर कोई अवरोध नहीं होगा।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने उच्च न्यायालय सहित सभी पक्षों से अनुरोध किया कि इस व्यापक न्यायिक सुधार के लिए वे अपने पारंपरिक विरोध को त्याग दें और इस प्रयास का समर्थन करें। उन्होंने कहा, सरकार सोच रही है कि एआईजेएस (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा) के लिए देश भर में चार श्रेणियां हों ताकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम के लोग अपने अपने क्षेत्रों में आ सकें। भाषा कोई समस्या नहीं होगी इससे पहले उनसे यह पूरक प्रश्न पूछा गया था कि क्या एआईजेएस की परीक्षाएं 29 भाषाओं में होंगी।प्रसाद ने कहा कि इस सेवाओं को लेकर विभिन्न पक्षों से बातचीत की गई। इनमें कई उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न पक्षों ने सहमति जताई जबकि कुछ पक्ष इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर 16 जनवरी 2017 को कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, सालिसीटर जनरल तथा अन्य ने भाग लिया। लेकिन बैठक में विभिन्न पक्षों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर सहमति नहीं बन पाई।

देश में करीब 9.38 लाख शहरी बेघर

नई दिल्ली। सरकार ने गुरूवार को बताया कि देश में कुल शहरी बेघर लोगों की संख्या 9,38,348 है और ऐसे लोगों की सहायता के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोकसभा में धर्मवीर सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी बेघर लोगों की संख्या 9,38,348 है। मंत्री ने बताया कि शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय उनके प्रयासों में मदद के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय संचालित कर रहा है। पुरी ने कहा कि इसके अलावा बेघर लोगों के बच्चों के सरकारी स्कूलों, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों आदि में दाखिले के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) में सभी पात्र शहरी परिवारों को जल, स्वच्छता, जलमल प्रबंध, सड़क एवं बिजली आदि मूलभूत नागरिक आधारभूत ढांचा के साथ सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

सभापति की नसीहतः राज्यसभा के सदस्य कानून व कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करें

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को सदन में कहा कि सांसदों का कर्तव्य है कि वे कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करें और यदि कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी उन्हें बुलाए तो वह उसके समक्ष अवश्य उपस्थित हों। नायडू ने शून्यकाल में कहा, कानून निर्माता के रूप में कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह सभी मामलों में सब पर लागू होता है क्योंकि सदस्य केवल सूचित कर सकते हैं कि सदन सत्र में है और उन्हें आगे की तारीख दे दी जाए। लेकिन सदस्य कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के सम्मन या नोटिस को टाल नहीं सकते।नायडू ने कहा कि किसी जांच एजेंसी के समक्ष बुलाए जाने पर सदस्यों को सदन के सत्र का हवाला देकर उपस्थित होने से नहीं बचना चाहिए।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करते राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर और सीएए पर सूचित किया गया, देशों ने समझ का परिचय दियाः सरकार

भाषा। नई दिल्ली

भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जानकारी दी है और इन देशों ने भारतीय स्थिति के प्रति समझ दिखाई है।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार के प्रयासों के चलते देशों ने जम्मू कश्मीर संबंधी मामलों के प्रति बेहतर समझ दिखाई है और वे इसे भारत का अंदरूनी मामला मान रहे हैं। उन्हें यह बात भी अब समझ में आ रही है कि पाकिस्तान प्रयोजित सीमा पार आतंकवाद भारतीयों की जिंदगी के प्रति गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। मुरलीधर ने बताया कि कुछ देशों ने तो पाकिस्तान का आह्वान किया है कि वह किसी भी सूरत में अपने क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दे। विदेश राज्य मंत्री ने बताया, सरकार ने काफी सक्रियता के साथ जम्मू कश्मीर से संबंधित तथ्यों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों को सूचित किया है और साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य और लक्ष्यों के बारे में सूचित किया है। मुरलीधरन ने बताया कि वार्ताकारों ने सीएए पर भारतीय स्थिति को भी समझा है कि यह भारत में रह रहे वंचित वर्ग की लंबे समय से चली आ रही स्थिति में सुधार के लिए उठाया गया ठोस कदम है। उन्होंने कहा, उन्हें यह बात भी समझ आई है कि इससे भारत के किसी भी नागरिक के दर्जे में किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा या इससे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले , किसी भी भारतीय की नागरिकता पर आंच नहीं आएगी। विदेश राज्य मंत्री ने दिसंबर में सीएए को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त के प्रवक्ता की टिप्पणी को लेकर उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार ने तुरंत मानवाधिकार उच्चायुक्त के समक्ष विरोध दर्ज कराया और साफ शब्दों में कहा कि यह कानून मानवीय उपाय है और भारत के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप है।

नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद से 15 हजार जानें बचाई गईं: गडकरी

भाषा। नई दिल्ल

शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण तीन साल में 41 हजार दुर्घटनाएं घटीं: सरकार

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को लोकसभा में बताया कि 2016 से 2018 के दौरान तीन वर्षों में देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 40983 दुर्घटनाएं घटीं। गडकरी ने गिरिधारी यादव और रमा देवी के प्रश्न के लिखित उत्तर में 2016 से 2018 के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े दिए जिनके अनुसार 2016 में 14894, 2017 में 14071 और 2018 में 12018 दुर्घटनाएं घटीं। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए कारावास या जुर्माने की सजा या दोनों के प्रावधान हैं।गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

देश में पिछले साल नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद से 15 हजार लोगों की बचाने में सरकार सफल रही है और साथ ही इससे विभिन्न राज्यों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि नया मोटर कानून लागू हुए पांच महीने का समय बीत चुका है और इसके चलते 15 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2016 में देशभर में सड़क हादसों में।, 50, 785, साल 2017 में।, 47, 913 और साल 2018 में।, 51, 417 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन नया कानून पास होने के बाद से सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। इसके बाद गुजरात में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 14 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 13 फीसदी, मणिपुर में 4 फीसदी, आंध्र प्रदेश में सात फीसदी, महाराष्ट्र में 6 फीसदी, हरियाणा में। फीसदी और दिल्ली में 2 फीसदी कमी आई है। हालांकि दो राज्य ऐसे भी रहे, जहां हादसों में मौतों में वृद्धि दर्ज की गई जिसमें केरल में 4.9 फीसदी और असम में 7.2 फीसदी , शामिल हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि वाहनों के लिए जारी किए जाने वाले फास्ट टैग की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

'महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 30 दिन के भीतर दाखिल हो आरोपपत्र'

भाषा। नई दिल्ली

महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए संसद की एक समिति ने ऐसे मामलों में 30 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने, आरोपियों को जमानत नहीं देने और ऐसे मामलों को छह माह के भीतर निस्तारित करने का सुझाव दिया है। भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित स्थाई समिति ने महिलाओं की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट गुरूवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की। समिति ने नवंबर 2019 में एक युवती के साथ जघन्य बलात्कार एवं बाद में उसकी हत्या किए जाने की घटना पर पीड़ा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाए जाने का सुझाव दिया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक है। समिति ने ध्यान दिलाया कि 2012 में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की संख्या 244270 थी जो 2017 में बढ़कर 359849 और 2018 में 378277 हो गई। रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि तमाम कानून एवं कानूनी ढांचा होने के बावजूद देश में महिलाओं के प्रति अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है। समिति ने सिफारिश की कि महिलाओं से जुडे कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 30 दिन के भीतर आरोपपत्र दायर किया जाए, आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए तथा मामले को छह महीने के भीतर निस्तारित किया जाए ताकि पीड़ितिओं को समय पर न्याय मिल सके।

समिति ने ध्यान दिलाया कि बलात्कार के 86 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दायर होने पर दोष सिद्धि केवल 32 प्रतिशत मामलों में हो पाती है। समिति ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि दो साल के भीतर प्रत्एक राज्य की राजधानी में एक फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि अपराधियों के खिलाफ मजबूती से मामला पेश किया जा सके।

कोरोना वायरस के खौफ से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर सिर्फ कबूतर नजर आ रहे हैं

रजनीकांत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार के कदमों की सराहना की

भाषा। चेन्नई

सुपरस्टार रजनीकांत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार के एहतियाती कदमों की गुरुवार को सराहना की और उन लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया, जिनकी आजीविका इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित हो सकती है। अभिनेता ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने एक बयान में कहा, तमिलनाडु में कोरोना वायरस को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम सराहनीय हैं। हम लोगों को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा ने बुधवार को कहा था कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने दो सौ करोड़ की राशि को मंजूरी दी है।कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में 14 मार्च से एक सप्ताह के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में अभी तक दो लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अभिनेता ने सरकार से उन लोगों की आर्थिक सहायता करने की भी अपील की जिनकी आजीविका इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित हो सकती है।

अमरिंदर ने राज्यसभा में गोगोई को मनोनीत किए जाने पर सवाल उठाए

भाषा। चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाते हुए कहा कि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह केंद्र की मौजूदा सरकार के लिए उपयोगी रहे थे।

अमरिंदर ने कहा कि गोगोई को मनोनीत किए जाने से लोग निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित होंगे और प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा, कोई भी विवेकी व्यक्ति सरकार के इस तरह के कदम के खिलाफ होगा। सिंह ने यहां एक बयान में कहा, यह (राज्यसभा में गोगोई का मनोनयन) स्पष्ट संकेत करता है कि वह केंद्र की मौजूदा सरकार के लिए उपयोगी रहे थे। उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वे राजनीतिक फायदे के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि गोगोई के मनोयन किए जाने के मामले में प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री ने गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद छह महीने से भी कम समय के अंदर भाजपा नीत सरकार द्वारा उनके मनोनयन और पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्रा के इसी पद से सेवानिवृत्त होने के कई साल बाद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बीच अंतर होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, गोगोई के उलट, मिश्रा ने राज्यसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ा था, और वह भी सीजेआई के तौर पर सेवानिवृत्त होने के करीब सात साल बाद। सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्व रक्षा कर्मी, पूर्व न्यायाधीश और अन्य अक्सर ही राजनीति में जाते हैं तथा चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व थल सेना प्रमुख जेजे सिंह को पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में अकालियों ने उनके खिलाफ उतारा था। उन्होंने कहा कि गोगोई भी राजनीति में जाने के हकदार हैं लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के चार-पांच साल बाद चुनाव का सामना करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भले ही विभिन्न आयोगों में नामित किया हो, उनका कोई राजनीतिक या सरकार के प्रति झुकाव नहीं था, लेकिन वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह किसी मुख्य न्यायाधीश के लिए ऐसा नहीं करना चाहेंगे जैसा कि संभवतः गोगोई के लिए किया गया है।

महाराष्ट्र में 2012 के मकोका मामले में 14 लोग बरी

ठाणे। एक विशेष मकोका अदालत ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 2012 के हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में 14 लोगों को बरी कर दिया। न्यायाधीश एस एस बहलकर ने बुधवार को सुनाए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता, सशस्त्र कानून, महाराष्ट्र पुलिस कानून और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत सभी आरोपियों पर लगे आरोप साबित करने में विफल रहा। मामले के 15वें अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जुलाई 2012 की रात, पीड़ित राजेश घाटगे को ठाणे के कोपरी इलाके में गोली मारी गई थी और आरोपियों में से एक ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया था। पीड़ित इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कथित आरोपियों की पीड़ित के साथ पुरानी दुश्मनी थी जिस कारण यह हमला किया गया। बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के तर्कों में खामियां बताईं और न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

केरल में राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की लोस में मांग उठी

भाषा। नई दिल्ली

लोस में बसपा सांसद ने विशेष अभियान चलाकर आरक्षित पदों को भरने की मांग की

नई दिल्ली। लोकसभा में बसपा की एक सदस्य ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए विभिन्न संस्थानों में आरक्षण के रिक्त पदों को तत्काल भरने तथा 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए बसपा की संगीता आजाद ने कहा कि विभिन्न संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के काफी पद रिक्त हैं। कई संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर इन रिक्त पदों को भरा जाए। बसपा सांसद ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के मेधावी छात्रों को सामान्य वर्ग के तहत भी स्थान दिया जाना चाहिए।आजाद ने कहा कि 2021 में जाति जनगणना कराई जाए और इसके अनुपात में ही आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिता एवं विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जाए।उन्होंने कमजोर वर्गो को मानकों के अनुरूप छात्रवृत्ति देने की भी मांग की।

लोकसभा में गुरूवार को केरल के कई सांसदों ने आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की मांग की। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर निचले सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के संवर्द्धन के लिए केरल में राष्ट्रीय औषधीय पौध संस्थान की स्थापना की मांग की।उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की केरल में स्थापना नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया और सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग की।

केरल कांग्रेस (एम) के सी थामस ने कहा कि केरल का आयुर्वेद के क्षेत्र में सदियों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य आयुर्वेद को बढ़ावा एवं संरक्षण देने का अहम स्थान रहा है, ऐसे में यहां राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस के एंटो एंटनी ने भी केरल में आयुर्वेद के महत्व एवं योगदान को रेखांकित करते हुए वहां राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की मांग की। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने केरल में आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राचीन काल से हो रहे कार्यो का उल्लेख करते हुए राज्य में राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की मांग की।

फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग की

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड 4जी इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल किए जाने का अनुरोध किया। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा, जैसा आप जानते हैं, कल कश्मीर में कोरोनो वायरस के पहले मामले का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों ने घाटी के बड़े हिस्सों को बंद कर दिया। नेकां अध्यक्ष ने कहा कि पांच अगस्त, 2019 के बाद हुए बंद से व्यवसाय और छात्र प्रभावित हुए थे और एक बार फिर उन्हें इन पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में कहा, लोगों को घर से कामापढ़ाई करने की सलाह दी जा रही है लेकिन 2जी इंटरनेट की गति के साथ यह असंभव है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4 जी इंटरनेट सेवाएं बहाल करें। गौरतलब है कि केन्द्र द्वारा अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने के कुछ घंटे पहले पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया था। इसके कुछ महीनों बाद पोस्टपेड मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड पर 2जी सेवाएं बहाल कर दी गई थी लेकिन 4जी सेवाएं बंद रही थी।

राज्यसभा में उठा निर्मल गंगा की मांग कर रहे स्वामी शिवानंद के अनशन का मुद्दा

नई दिल्ली। निर्मल और अविरल गंगा की मांग कर रहे मातृ सदन, हरिद्वार के स्वामी शिवानंद के अनशन का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में भी उठा और आप के एक सदस्य ने मांग की कि सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्वामी शिवानंद की उम्र करीब 80 वर्ष है और वह पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। सिंह ने कहा कि निर्मल और अविरल गंगा के लिए मातृ सदन के संत लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं। इस क्रम में चार संतों ने अपना जीवन तक दे दिया। इसकी क्रम में साध्वी पद्मावती जीवन-मौत से जूझ रही हैं और 15 दिसंबर से अनशन पर हैं। सिंह ने मांग की कि सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को सुनना चाहिए। शून्यकाल में ही कांग्रेस के शमशेर सिंह ढिल्लों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शून्यकाल में ही कांग्रेस के नारायण भाई राठवा ने केंद्रीय सचिवालय सेवा में प्रोन्नति रोक दिए जाने का मुद्दा उठाया।

संघ सरकार्यवाह मानव स्वास्थ्य के लिए की गई प्रार्थना में शामिल हुए

बेंगलुरु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह सुरेश (भैय्याजी) जोशी कोरोना वायरस की महामारी के बीच मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की गई विशेष पूजा में शामिल हुए। आरएसएस कार्यकारी ने बताया, उन्होंने वेद वि गुरुकुल में ग्रह प्रायश्चित होम और धनवंतरी होम में हिस्सा लिया और कोरोना वायरस के मद्देनजर मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी, सेंसेक्स चौथे दिन 581 अंक टूटा

भाषा। मुंबई

घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार चौथे दिन जारी रहा और बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बृहस्पिवार को 581 अंक से अधिक टूट कर 28,288.23 अंक पर बंद हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका में निवेशक सुरक्षित विकल्पों को तरजीह दे रहे हैं। प्रमुख तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में एशिया के अन्य बाजारों की तरह ही गिरावट रही। सेंसेक्स दोपहर में कुछ समय की तेजी के बाद बिकवाल के दबाव में आगया। यह अंत में 581.28 अंक यानी 2.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,288.23 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 2,656.07 अंक का उतार-चढ़ाव आया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205.35 अंक यानी 2.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,263.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 7,900 के स्तर से नीचे चला गया था। कारोबारियों के अनुसार कारोबार के दौरान रुपए की विनिमय दर डॉलर के मुकाबले 75 को पार कर गया। इससे बाजार धारणा और प्रभावित हुई।

सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस को सर्वाधिक नुकसान हुआ। इसमें 10.24 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। उसके बाद क्रमश: मारुति (9.85 प्रतिशत), एक्सिस बैंक (9.50 प्रतिशत), महिंद्रा एंड महिंद्रा (9.28 प्रतिशत), टेक महिंद्रा (8.43 प्रतिशत) और ओएनजीसी (7.35 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं लाभ में रहे प्रमुख शेयरों में आईटीसी, भारती एयरटेल, कोटक बैंक और हीरो मोटो कार्प में 7.50 प्रतिशत तक की तेजी आई। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टाक ब्रोकर्स के इक्विटी शोध प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव की चिंता के बीच वैश्विक बाजरों में गिरावट आई और उतार-चढ़ाव देखा गया। उन्होंने कहा, दोपहर के कारोबार में बाजार में मामूली तेजी रही लेकिन ज्यादतर समय बाजार में गिरावट ही रही। कारोबारियों के अनुसार विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों और सरकारों के प्रोत्साहन उपायों की घोषणा के बावजूद एशिया में निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है। निवेशकों को चिंता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में जा रही है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी में सर्वाधिक 8 प्रतिशत की गिरावट आई। हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के अचानक से 750 अरब यूरो के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी रही। आर्थिक नरमी की चिंता के बीच ईसीबी ने बुधवार को 750 अरब यूरो मूल्य के सरकारी और निजी कंपनियों के बांड खरीदने की घोषणा की। इस बीच, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में 2,00,000 पहुंच गई है जबकि मरने वालों की संख्या 8,000 हो गई है।स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 18 और मामले सामने आने के बाद प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है।

क्विक न्यूज

यस बैंक : अनिल अंबानी मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए

मुंबई। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवार को मुंबई में यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ धन-शोधन मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अनुमान है कि जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 60 वर्षीय अंबानी का बयान दर्ज करेगी। बताया जाता है कि अंबानी की नौ समूह कंपनियों ने यस बैंक से लगभग 12,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसकी कथित तौर पर वापसी नही हो रही है।

विमान ईंधन, कुछ रसायनों के आयात नियम सरल

नई दिल्ली। सरकार ने जस्ते के अपशिष्ट और मिट्टी का तेल (नाफ्था) समेत कुछ जिंसों के आयात से प्रतिबंध हटा दिए है। साथ ही विमानन प्रशिक्षण केंद्रों (फ्लाइंग क्लब) को कुछ शर्तों के साथ विमान ईंधन के आयात की भी खुली छूट दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक फ्लाइंग क्लबों को छोड़ कर विमान ईंधन के अन्य उपयोक्ता इसका आयात सरकारी तेल कंपनियों के माध्यम से कर सकते है। अधिसूचना में कहा गया है कि जस्ते के अपशिष्ट, हल्के नाफ्था, भारी नाफ्था और नाफ्था की बाकी पूरी श्रृंखला के साथ विमान ईंधन के आयात को लेकर नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन किया है। अब आयातकों को जस्ते के अपशिष्ट (ड्रॉस) के आयात के लिए लाइसेस नही चाहिए होगा। इसका उपयोग पेंट उद्योग समेत कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। इसी तरह अब नाफ्था के आयात को भी मुक्त बना दिया गया है।

कोरोना वायरस संकट: यूरोपीय सेंट्रल बैंक 750 अरब यूरो मूल्य का सरकारी, निजी कंपनियों का बांड खरीदेगा

फ्रैंकफर्ट। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने बाजार में नकदी बढ़ाने के इरादे से 750 अरब यूरो (820 अरब डॉलर) मूल्य के सरकारी और निजी कंपनियों के बांड खरीदने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक नुकसान को रोकने के उपाय के तहत ईसीबी ने यह कदम उठाया है। ईसीबी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि देर शाम 25 सदस्यीय संचालन परिषद के सदस्यों की फोन पर बातचीत के बाद यह निर्णय किया गया। इससे पहले, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों ने भी आर्थिक संकट से पार पाने के लिए नीतिगत पहल की थी। ईसीबी ने कहा कि वह इस चुनौतीपूर्ण समय में यूरो क्षेत्र के सभी नागिरकों की मदद के लिए अपनी भूमिका निभाने को लेकर प्रतिबद्ध है। आलोचकों ने हाल ही में यूरो क्षेत्र की मदद के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह पर्याप्त कदम नही उठाने को लेकर ईसीबी की निंदा की थी। ईसीबी के ताजा कदम की विश्लेषकों ने सराहना की है। पिकटेट वेल्थ मैनेजमेंट के रणनीतिकार फ्रेडरिक डुकरोजेट ने कहा कि अगर राजकोषीय कदम भी उठाया जाता है तो ईसीबी की ताजा पहल यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए पासा पलटने वाला साबित होगी।

कोरोना वायरस: स्पाइसजेट अप्रैल अंत तक ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद करने को मजबूर हुई

नई दिल्ली। स्पाइसजेट ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वह आगामी शनिवार से अप्रैल अंत तक अपनी ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन रद्द करने के लिए मजबूर है। घातक कोरोना वायरस (कोविड-19) रोग के चलते पैदा हुई अभूतपूर्व परिस्थितियों में भारत सहित कई देशों ने अपनी सीमा को आंशिक रूप से बंद कर दिया है और ऐसे में दुनिया भर की प्रमुख विमानन कंपनियों ने अपने उड़ान संचालन में भारी कमी कर दी है। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर स्पाइसजेट को 21 मार्च से 30 अप्रैल, 2020 तक अपनी अधिकांश अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को अस्थाई रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा, हम स्थिति सामान्य होते ही निलंबित उड़ानों को फिर से शुरू करेंगे। प्रवक्ता ने हालांकि कहा कि उसकी कोलकाता - ढाका उड़ान तय समयसारिणी के अनुसार चलती रहेगी। उन्होंने कहा, हमारी चेन्नई - कोलंबो उड़ान 25 मार्च 2020 से दोबारा शुरू होगी, जबकि हमारी दिल्ली - दुबई और मुंबई - दुबई उड़ानें 16 अप्रैल 2020 से दोबारा शुरू होंगी।

आरबीआई ने यस बैंक को दी 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधा

भाषा। नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ने यस बैंक को नकदी की समस्या से निपटने को लेकर 60,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे बैंक को जमाकर्ताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करने में आसानी होगी। यह आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के सोमवार को कहा था कि यस बैंक से पाबंदी हटने के बाद जरूरत पड़ने पर उसे नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। आरबीआई कानून, 1934 की धारा 17 के तहत केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक को शेयर कोष और प्रतिभूतियों (अचल संपत्तियों को छोड़कर) को गिरवी रखकर कर्ज के रूप में नकदी की सुविधा उपलब्ध करा सकता है।सूत्रों के अनुसार आरबीआई के आकलन में पाया गया है कि यस बैंक के सामने नकदी की समस्या हो सकती है लेकिन ऋण शोधन में दिक्कत या ऐसी कोई अन्य कोई समस्या नहीं है।

सूत्रों के अनुसार हालांकि यस बैंक को आरबीआई से उधार की सुविधा कुछ शर्तों के साथ है। चूंकि आरबीआई कर्ज के लिए अंतिम आश्रय होता है, ऐसे में शर्त है कि यस बैंक पहले अपनी जरूर पूरा करने के लिए अपने पास तत्काल उपलब्ध नकद संपत्ति का उपयोग करेगा। उसके बाद कमी पड़ने पर रिजर्व बैंक के इस कोष में हाथ लगाएगा। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने पांच मार्च को यस बैंक पर विभिन्न प्रकार की पाबंदी लगाते हुए उसके बोर्ड को हटा दिया था और खाताधारकों को उनके खाते में जमा धन से एक माह में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार ने 13 मार्च को पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में वित्तीय संस्थानों से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यस बैंक पर लगी सभी पाबंदियां बुधवार, 18 मार्च शाम से हटा ली गई हैं।

यस बैंक के प्रशासक प्रशांत कुमार ने जमाओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया

नई दिल्ली। यस बैंक में बैंकिंग सेवाओं के पूरी तरह बहाल होने के बाद गुरुवार को बैंक के प्रशासक प्रशांत कुमार ने एक बार फिर जमाकर्ताओं को उनके धन की सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया और कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है। कुमार पुनर्गठित यस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। यस बैंक की बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह 18 मार्च 2020 को शाम छह बजे फिर से शुरू हुईं और ग्राहक 19 मार्च 2020 से शाखाओं में जाकर पूर्ण सेवाएं पाने में सक्षम हो गए हैं। कुमार ने एक बयान में कहा, बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और उसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए बैंक की शाखाएं 19 मार्च से 21 मार्च 2020 तक एक घंटे पहले सुबह साढ़े नौ बजे खुलेंगी। बैंक अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों 19 मार्च से 27 मार्च 2020 के दौरान शाम 5.30 बजे तक सेवाएं देगा। कुमार ने कहा, यस बैंक ने बैंकिंग सेवाओं को बहाल करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि शाखाओं और एटीएम में पर्याप्त नकदी हो। निकासी के लिए ग्राहकों को जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है और नकदी के मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है।

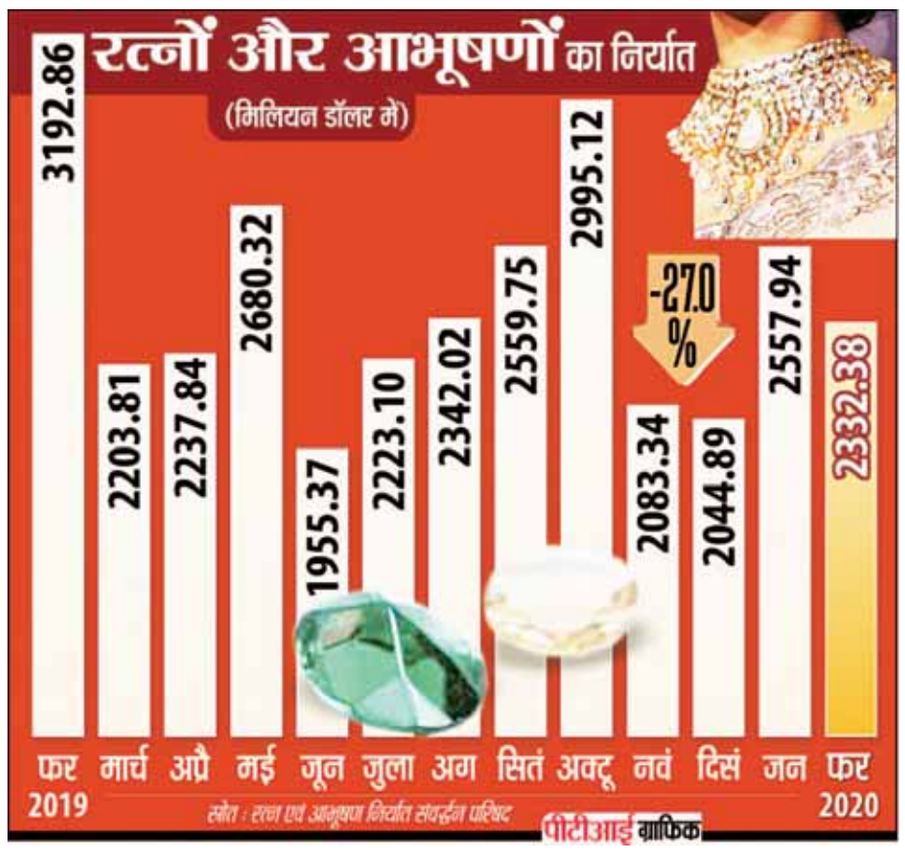

कोरोना वायरस : इंडिगो सीईओ, वरिष्ठ कर्मियों के वेतन में करेगी 25 फीसद तक की कटौती

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समेत अन्य वरिष्ठ कर्मियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती करेगी। कोरोना वायरस संकट के विमानन क्षेत्र पर व्यापक असर को देखते हुए कंपनी के सीईओ रणजय दत्ता ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। दत्ता ने कर्मचारियों को भेजे ई-मेल में कहा, आय में बड़ी गिरावट के चलते वर्तमान में विमानन उद्योग के वजूद पर ही आन पड़ी है। ऐसे में हमें हमारी नकदी की स्थिति को ध्यान में रखकर चलना होगा ताकि हमें नकदी संकट का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा, इसलिए हमें खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि श्रेणी ए और बी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी के वेतन में कटौती की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2020 से लागू होगी। कंपनी के ए और बी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन कम है और उसके सबसे अधिक कर्मचारी इन्हीं श्रेणियों के हैं। दत्ता ने कहा, वह स्वयं के वेतन में सबसे अधिक 25 प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं। कंपनी में वरिष्ठ उपाध्यक्षों के पद पर काम करने वालों के वेतन में 20 प्रतिशत, उपाध्यक्षों और कॉकपिट दल के लोगों के वेतन में 15 प्रतिशत, सहायक उपाध्यक्ष, डी श्रेणी और चालक दल के सदस्यों के वेतन में 10 प्रतिशत और सी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में पांच प्रतिशत की कटौती होगी। उन्होंने कहा कि वह जानतें हैं कि यह उसके कर्मचरियों के परिवारों के लिए मुश्किल का समय है।

सेबी ने कंपनियों को चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम की घोषणा के लिए 45 दिन की मोहलत दी

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कंपनियों को चालू वित्त वष की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा को लेकर 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। वहीं 2019-20 के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के लिए एक महीने का और समय दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि इसके अलावा कंपनी संचालन की तिमाही रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने तथा शेयरधारित प्रतिरूप और निवेशक शिकायत रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन-तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। इसके कारण लोगों की मुक्त आवाजाही समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे कारोबार और रोजाना का कामकाज प्रभावित हुआ है। सेबी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को देखते हुए सूचीबद्ध इकाइयों के के नियमों में अनुपालन में अस्थाई तौर पर राहत देने की जरूरत है। इसके कारण उक्त कदम उठाए गए हैं।

कोरोना वायरस के चलते घरेलू ऑटो क्षेत्र पर होगा नकारात्मक असर : इंडरा

नई दिल्ली। भारत रेटिंग एवं अनुसंधान (इंडरा) ने कहा है कि कोविड-19 के लगातार फैलाव का निकट अवधि में घरेलू ऑटो उद्योग पर नकारात्मक असर होगा, क्योंकि इस महामारी का केंद्र चीन का वुहान शहर ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के विनिर्माण का प्रमुख केंद्र है। इंडरा ने एक बयान में कहा कि एजेंसी का मानना है कि अगर कोविड-19 का प्रसार दो महीने से अधिक तक रहता है तो ऑटो क्षेत्र को न सिर्फ आपूर्ति पक्ष, बल्कि मांग पक्ष और निर्यात के मोर्चे से भी दबाव का सामना करना पड़ेगा। भारतीय ऑटो कलपुर्जा उद्योग और उपकरण निर्माता काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि घरेलू बिक्री में कमी और मार्जिन के दबाव के साथ ही अगर आपूर्ति पक्ष से कोई झटका लगता है तो इस क्षेत्र की कंपनियों का परिचालन प्रभावित हो सकता है।

एच-1 बी वीजाधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रंप से अपील

वाशिंगटन। उच्च कौशल वाले प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एच- ।बी वीजाधारकों की तकलीफों का जिक्र करते हुए ग्रीन कार्ड या कानूनी स्थाई निवास की गति में तेजी लाने और नौकरशाही तथा कानूनी बधाओं को हटाने का आग्रह किया है। एच- - ।बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ व्यवसायों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जहां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्यक वर्ष दसियों हजार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर हैं। ग्रीन कार्ड एक गैर-अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में स्थाई रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स ऑफ अमेरिका ने ट्रंप से अनुरोध किया है कि वह ग्रीन कार्डधारकों की तकलीफों को दूर करें और अमेरिकी नागरिकता तथा आव्रजन सेवाओं को समायोजन की स्थिति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अनुमति दें।

कोरोना वायरस: एअर इंडिया की वेतन में पांच फीसद कटौती करने की संभावना

भाषा। मुंबई

संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया कोरोना वायरस महामारी के चलते अपने कर्मचारियों के वेतन में पांच प्रतिशत तक की कटौती कर सकती है। कंपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पहले ही रद्द कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि वेतन में कटौती सभी श्रेणी के कर्मचारियों की होगी। सरकार घाटे में डूबी एअर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया में है। कंपनी ने कार्यकारी पायलटों और अन्य के मनोरंजन भत्ते को खत्म करने के अलावा चालक दल के सदस्यों को उड़ान भरने के लिए अलग से मिलने वाले भत्ते को पहले ही कम किया है। सूत्रों ने कहा, कोरोना वायरस संकट के वजह से कंपनी भारी वित्तीय दबाव महसूस कर रही है। क्योंकि कंपनी की अमेरिका, कनाडा और अन्य कुछ विदेशी बाजारों की सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इसलिए वह कर्मचारियों के वेतन में पांच प्रतिशत तक की कटौती करने पर विचार कर रही है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य सूत्र ने कहा कि लागत कम करने के लिए कंपनी ने 100 से ज्यादा पायलटों के उड़ान भरने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इन पायलटों को संविदा पर फिर से नौकरी पर रखा गया था। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता की ओर से इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है।

ट्रंप की अमेरिकी नागरिकों को 500 अरब डॉलर नकद सहायता देने की योजना

भाषा। वाशिंगटन,

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश पर कोरोना वायरस महामारी के विनाशकारी आर्थिक प्रभावों का सामना करने में नागरिकों की मदद के लिए उन्हें सरकारी खजाने से सीधे धन हस्तांतरित करने की एक विशाल एवं अभूतपूर्व योजना की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण की राशि 500 अरब डॉलर हो सकती है। इसे दो किस्तों में दिया जाएगा। यह राशि भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के छठे हिस्से के बराबर है। यदि इस राशि को सभी अमेरिकी नागरिकों में समान रूप से बांट दिया जाए तो 33 करोड़ लोगों को एक- एक लाख रुपए से अधिक मिलेंगे।

ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उनके प्रशासन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव कांग्रेस को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकियों को प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण योजना 250-250 अरब डालर की दो किस्तों में होनी है पहली, अप्रैल की शुरुआत में और दूसरी, मई के मध्य में। गंभीर आर्थिक संकट के समय में अमेरिका में नागरिकों को इस तरह की मदद दी जाती रही है,

लेकिन व्हाइट हाउस का इस बार का प्रस्ताव काफी बड़ा है और कुल धनराशि के लिहाज से दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी नागरिकों को 500 अरब अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष भुगतान दो किस्तों में करने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के आकार और आय के आधार पर सहायता दी जाएगी।

कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में खत्म हो सकती हैं लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां: संयुक्त राष्ट्र

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीतिगत कार्वाई के जरिए वैश्विक बेरोजगारी पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने कोविड-19 और कामकाजी दुनिया: प्रभाव और कार्वाईं शीर्षक वाली अपनी प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कार्यस्थल में श्रमिकों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को मदद और रोजगार तथा आमदनी को बनाए रखने के लिए तत्काल, बड़े पैमाने पर और समन्वित उपायों का आह्वान किया है। आईएलओ ने कहा कि इन उपायों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, रोजगार बनाए रखने में सहायता (यानी कम अवधि का काम, वैतनिक अवकाश, अन्य सब्सिडी) और छोटे तथा मझोले उद्योगों के लिए वित्तीय और कर राहत शामिल हैं। आईएलओ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक और श्रम संकट से दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि जैसा 2008 के संकट में देखा गया था, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीतिगत कार्वाई पर गंभीरता से अमल करें तो वैश्विक बेरोजगारी पर प्रभाव काफी कम हो सकता है।

दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9,000 से पार

भाषा। पेरिस/तेहरान/काठमांडू

दुनियाभर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या गुरुवार को 9,000 के पार पहुंच गई। एएफपी ने विभिन्न देशों के आधिकारिक सूत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर यह संख्या जारी की है।

बृहस्पतिवार तक कोरोना वायरस से कुल 9,020 लोगों की मौत हुई। इनमें से यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या 4,134 जबकि एशिया में 3,416 है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से और 712 लोगों की मौत हुई और संक्रमित लोगों की संख्या 90,293 है। यूरोप में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। एएफपी की खबर के अनुसार, ईरान में कोरोना वायरस संक्रमण से और 149 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। ईरान के स्वास्थ्य उपमंत्री अलीरेजा रिआसी ने बताया कि इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर।,284 हो गई है। देश में अभी तक कुल 18,407 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं।

एएफपी की खबर के अनुसार, स्पेन ने आज को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब यह 767 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में कुल 17,147 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। यह कल के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा है। एपी की खबर के अनुसार,

● बृहस्पतिवार तक कोरोना वायरस से कुल 9,020 लोगों की मौत हुई। इनमें से यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या 4,134 जबकि एशिया में 3,416 है

सरकारी टीवी पर न्यायिक प्रवक्ता गुलामहुसैन इस्माइल ने कहा कि ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामनेई नववर्ष, नवरोज के अवसर पर 10,000 कैदियों को माफी देंगे।

ईरान ने देश में तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर यह कदम उठाया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने से हतोत्साहित करने के लिए ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के. जहानपुर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वायरस से हर घंटे ईरान में 50 लोग संक्रमित हो रहे हैं और प्रत्एक 10 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने फिलहाल विदेश गए अपने निवासियों के देश वापसी पर रोक लगा दी है। हालांकि राज्य ने अपने नागरिकों को वापस लौटने की अनुमति दे दी है। यूएई में अभी तक 113 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। नेपाल ने गुरुवार को यूरोप, पश्चिम एशिया और जापान से आने वाले सभी यात्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह यात्रा प्रतिबंध शुक्रवार से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध उन लोगों पर भी लागू होगा जो इन देशों के रास्ते होते हुए नेपाल आना चाहते हैं। नेपाल सभी विदेशी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल पिछले ही सप्ताह रद्द कर चुका है। यह आदेश फिलहाल 30 अप्रैल तक प्रभावी है। नेपाल में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के एक मामले की पुष्टि हुई है। खबर के अनुसार, पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय वाघा सीमा को दो सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा की है। देश में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 341 मामलों की पुष्टि हुई है। एएफपी की खबर के अनुसार, जर्मनी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 10,999 हो गई है। यहां महज एक दिन में संक्रमण के 2,801 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रोग नियंत्रण संस्थान रॉबर्ट कोश इंस्टीट्यूट (आरकेआई) के अनुसार, इस वायरस के संक्रमण से अभी तक 20 लोगों की मौत हुई है। भाषा की खबर के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर श्रीलंका ने 25 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। चुनाव आयोग के प्रमुख महिन्दा देशप्रिय ने बताया कि नई तारीख की घोषणा 25 मार्च के बाद की जाएगी और यह इसपर निर्भर करेगा कि वायरस से कितनी जल्दी निपटा जा सकता है।

रूस में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई

मास्को (एएफपी)। रूस में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के साथ बृहस्पतिवार को पहली मौत दर्ज की गई। वह मास्को के एक अस्पताल में भर्ती थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह कहा। एक बयान में अधिकारी के हवाले से कहा गया है, 79 वर्षीय महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उसे 13 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे मधुमेह तथा हृदय संबंधी रोग भी था। जिन लोगों के वह संपर्क में आई थी उन्हें पृथक कर दिया गया है। संक्रामक रोगों के लिए मास्को अस्पताल संख्या-2 की प्रमुख चिकित्सक स्वेतलाना करासनोवा के हवाले से बयान में कहा गया है, बुजुर्ग रोगी लंबे समय से कई रोगों से ग्रसित थी। मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानीन ने ट्विटर पर कहा, दुर्भाग्य से कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें पहली क्षति (एक महिला के मौत के रूप में) हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस में कोरोना वायरस के अब तक 147 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते कहा था कि कोरोना वायरस से खतरे की स्थिति देश में आमतौर पर नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने बृहस्पतिवार को एक सरकारी बैठक के दौरान लोगों से यथा संभव अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आने को कहा।

अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित करने के चीन के फैसले से खुश नहीं हूं : ट्रम्प

वाशिंगटन (भाषा)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह चीन से अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित किए जाने के फैसले को लेकर खुश नहीं हैं। चीन सरकार के द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट के अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित किए जाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने बुधवार को व्हाइट हाउस में कहा, मुझे यह देखकर खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, उन तीनों मीडिया संस्थानों के साथ मेरी अपनी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि आप यह अच्छी तरह जानते हैं लेकिन मुझे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं खुश नहीं हूं। चीन ने अमेरिका के तीन बड़े अखबारों के करीब 13 अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित करने के अपने फैसले का बुधवार को बचाव करते हुए कहा कि वाशिंगटन द्वारा चीन के सरकारी मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशन घोषित करने के बाद इसके बदले में उसे यह कार्वाई करने के लिए विवश होना पड़ा। सीनेटर डायने फिनस्टीन ने कहा कि वह अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित करने के चीन के फैसले से काफी चिंतित हैं।उन्होंने कहा, यह साफ तौर पर अमेरिकी मीडिया संस्थानों को धमकाने और चीन में घटनाओं को रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता को सीमित करने का प्रयास है। पत्रकारों के खिलाफ ऐसी बदले की कार्वाई खतरनाक उदाहरण पेश करती है जो दुनियाभर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्कासित पत्रकार विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग या मकाऊसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे।

चीन में पहली बार कोरोना वायरस का कोई घरेलू मामला सामने नहीं आया : एनएचसी

कोरोनोवायरस के खिलाफ मुखौटा पहने हुए कार्यालय कार्यकर्ता गुरुवार को बीजिंग में एक मॉल और कार्यालय भवन में लालटेन की सजावट के लिए जाते हुए

भाषा। बीजिंग

चीन के वुहान शहर में करीब तीन महीने पहले कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को पहली बार ऐसा हुआ कि देश में संक्रमण का एक भी घरेलू मामला सामने नहीं आया। हालांकि संक्रमण से आठ और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 3,245 पर पहुंच गई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि बुधवार को चीनी भूभाग पर कोरोना वायरस का कोई घरेलू मामला सामने नहीं आया। उसने बताया कि हालांकि बुधवार को चीनी भूभाग पर कोविड-19 के कुल 34 नए मामले सामने आए लेकिन ए सभी विदेशों से संक्रमण के मामले थे। एनएससी ने बताया कि इन 34 नए आयातित मामलों में से 21 बीजिंग में, नौ ग्वांगडोंग प्रांत में, दो शंघाई, एक हीलोंगजियांग प्रांत में तथा एक झेजियांग प्रांत में सामने आया।पिछले साल दिसंबर से ही कोरोना वायरस का दंश झेल रहे मध्य हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में भी बुधवार को एक भी मामला सामने नहीं आया जो इस जानलेवा विषाणु के खिलाफ शहर की महीनों लंबी लड़ाई में अहम बात है। हुबेई प्रांत के स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वुहान और हुबेई में संक्रमित मामलों की कुल संख्या क्रमश: 50,005 और 67,800 रही। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि बुधवार को चीनी भूभाग पर आठ मौतें और 23 नए संदिग्ध मामले आए। सभी मौतें हुबेई प्रांत में हुई। एनएचसी ने बताया कि चीन में आयातित मामलों की संख्या बढ़कर 189 हो गई है। चीन में कोविड-19 के कुल 80,928 मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें से 3,245 लोगों की मौत हो गई और 70,420 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एनएचसी ने बताया कि बुधवार तक हांगकांग में चार मौत समेत 192 मामले, मकाऊमें 15 मामले तथा ताइवान में एक मौत समेत 100 मामले दर्ज किए गए।

क्विक न्यूज

स्पेन में मरने वालों की संख्या 767 पहुंची

मैड्रिड (एएफपी)। स्पेन ने गुरुवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब यह 767 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में कुल 17,147 लोग वायरस से संक्रमित हुए है। यह कल के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा है।

अमेरिका ने नियमित वीजा सेवाएं निलंबित कीं

वाशिंगटन (एएफपी)। अमेरिका ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नियमित वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात कहा कि दुनिया भर के अधिकांश देशों में दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में 18 मार्च, 2020 से प्रवासी और गैर-प्रवासी नियमित वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जाएगी। इस बात की कोई जानकारी नही दी गई की इस निलंबन से किन देशों को छूट दी जाएगी।

जापान के उत्तरी होकाइदो ने वायरस को लेकर आपात स्थिति हटाई

तोक्यो (एएफपी)। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइदो ने कोरोना वायरस को लेकर पिछले महीने लगाए गए आपातकाल को बृहस्पतिवार को हटा लिया गया। द्वीप ने कहा कि प्रकोप के कम होने के संकेत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। होक्काइदो प्रांत के गवर्नर ने क्षेत्र में संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद 28 फरवरी को आपात कदमों की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के तहत निवासियो से बेवजह बाहर निकलने से बचने की अपील की गई थी। हालांकि यूरोप के कई हिस्सों में जबरन लागू की गई घोषणाओं के उलट यहां ऐसी कोई जबर्दस्ती नही की गई। गवर्नर नाओमिची सुजुकी ने बुधवार देर रात कहा कि घोषणा के करीब 20 दिन बाद कोरोना वायरस का प्रसार घटता दिख रहा है। उन्होंने कहा, हम तय समय के अनुसार 19 मार्च को आपातकाल हटा लेंगे।

जापान के सम्राट की ब्रिटेन यात्रा कोरोना वायरस के कारण स्थगित

लंदन (एएफपी)। जापान के सम्राट की ब्रिटेन की इस साल वसंत में निर्धारित यात्रा को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। बकिंघम पैलेस ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ब्रिटेन में महामहिम की सरकार और जापान सरकार के बीच विचार विमर्श के बाद महारानी ने इस बात पर सहमति जताई है कि मौजूदा परिस्थिति में जापान के सम्राट और सम्राज्ञी की 2020 में वसंत में होने वाली यात्रा स्थगित की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, राजकीय यात्रा के लिए बाद की कोई तारीख तय की जाएगी।

कोविड-19 की जांच और शहरों को बंद करने में अच्छा काम करने वाले देश जल्द ही वापसी करेंगे : बिल गेट्स

भाषा। वाशिंगटन

लोगों से शांत रहने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स ने कहा कि जिन देशों ने जानलेवा कोरोना वायरस की जांच और शहरों एवं संस्थानों को बंद करने में अच्छा काम किया है वे कुछ हफ्तों में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी जल्द ही वापसी कर सकते हैं।

गेट्स ने युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट रेडिट पर सवालों के जवाब में बुधवार को कहा, अगर कोई देश जांच और शहरों एवं संस्थानों को बंद करने के संबंध में अच्छा काम करता है तो छह से 10 हफ्तों के बीच वहां बहुत कम मामले होंगे और वह फिर से सामान्य कामकाज कर पाएगा। उन्होंने कहा कि जांच और सामाजिक रूप से अलग रहने का तरीका साफ तौर पर कामयाब रहा। गेट्स ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा दौर में अमीर देशों में काफी मामले हैं। जांच और सामाजिक दूरी बनाने समेत सही कदमों के साथ अमीर देशों में दो से तीन महीनों में संक्रमण के मामले कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे आर्थिक नुकसान की चिंता है लेकिन इससे भी बदतर यह होगा कि यह विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करेगा जो अमीर देशों की तरह सामाजिक दूरी नहीं बना सकते और जिनके अस्पतालों की क्षमता काफी कम है।

उन्होंने कहा कि गेट्स फाउंडेशन दुनियाभर में कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए 10 करोड़ डॉलर देगा। साथ ही वह वाशिंगटन की मदद के लिए 50 लाख डॉलर देगा जो न्यूयॉर्क के बाद कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। गेट्स ने कहा कि फाउंडेशन डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा शास्त्र और टीके बनाने के संबंध में काम करने वाले समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि सही प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए।

इंडोनेशिया के सुराबाया में एक शॉपिंग मॉल में कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक सामाजिक दूर के प्रयास के रूप में लोग लिफ्ट के फर्श पर निर्धारित स्थान पर खड़े हुए

10 लाख पुरस्कार राशि वाले ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए तीन भारतीय शिक्षक दावेदार

भाषा। लंदन

यूनेस्को की साझेदारी में होने वाले वार्षिक वर्कले फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज-2020 के लिए 50 संभावित विजेताओं को चुना गया है जिनमें तीन भारतीय शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार के तौर पर 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है।

इस पुरस्कार के लिए 140 देशों के करीब 12 हजार शिक्षकों को नामांकित किया गया था जिनमें से 50 शिक्षकों को संभावित विजेताओं के रूप में चुना गया है। इनमें राजस्थान के शिक्षा निकेतन बेयरफुट कालेज में नागरिकता के शिक्षक शुवजीत पायने, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितावाडी स्थित जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में शिक्षक रंजीतसिंह दिसाले, दिल्ली स्थित एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षिका विनीता गर्ग शामिल हैं।

दिसाले ने कहा, यह किसी सपने जैसा है। मैं और मेरे छात्र शीर्ष 50 संभावित विजेताओं में अपने चुने जाने से खुश हैं। हमारी कड़ी मेहनत की यह पारितोषी है। उल्लेखनीय है कि उन्हें तकनीक का इस्तेमाल कर प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का श्रेय दिया जाता है। दिसाले ने क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक योजना के तहत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में ऑडियो-वीडियो सामग्री लिंक की है। शुवजीत पायने ने कहा, मेरा मानना है कि पुरस्कार से मिली पहचान से लोग प्रोत्साहित होंगे। इससे उनके काम भी लोगों के सामने आएगा। उल्लेखनीय है कि पायने ग्रामीण भारत की जरूरतों के अनुरूप अनौपचारिक रूप से चल रहे 50 सामुदायिक स्कूलों के संचालन और पाठ्यक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल टीचर प्राइज का यह छठा संस्करण है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है एवं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) साझेदार है।

यात्रा प्रतिबंधों के कारण सिंगापुर में फंसे 97 भारतीय यात्री

भाषा। सिंगापुर

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए भारत के यात्रा प्रतिबंधों के कारण करीब 100 भारतीय यात्री सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे पर फंसे हुए हैं और स्वदेश लौटने में असमर्थ हैं।

सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को बताया कि वह 97 फंसे भारतीयों को विमान से भारत लाने का प्रबंध करने की दिशा में काम कर रहा है।उसने बताया कि इन भारतीय यात्रियों में अधिकतर फिलीपीन और मलेशिया से आए हैं।उच्चायोग ने बताया कि सिंगापुर ने आसियान क्षेत्र से या वहां से होकर आने वाले यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं जिसके कारण यात्री सिंगापुर में प्रवेश नहीं कर सकते। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ ने बृहस्पतिवार को पीटीआई भाषा से कहा, हम इन भारतीयों को उनके घर वापस ले जाने का प्रबंध करने के लिए विदेश मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अशरफ ने कहा, हम एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और चांगी हवाईअड्डे के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इन फंसे यात्रियों को वापस भारत लाया जा सके और उन्हें मदद मुहैया कराई जा सके।

चांगी हवाईअड्डे पर उच्चायोग के अधिकारी 97 यात्रियों को भोजन एवं अन्य सहायता मुहैया करा रहे हैं। इनमें से अधिकतर यात्री मलेशिया से आए हैं। मलेशिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं और विदेशियों को प्रवेश करने से रोक दिया है। उसने अपने नागरिकों से भी यात्रा नहीं करने को कहा है।भारत ने भी मलेशिया और फिलीपीन समेत कुछ देशों से यात्रियों के आगमन पर रोक लगा दी है। सिंगापुर एयरलाइंस ने फंसे यात्रियों को भारत ले जाने पर सहमति जताई है क्योंकि बृहस्पतिवार को एयर इंडिया की कोई उड़ान सिंगापुर से भारत जाने के लिए निर्धारित नहीं है।दिल्ली प्रशासन भारत में इन यात्रियों के प्रवेश के प्रबंध कर रहा है।विश्व भर के 157 देशों और क्षेत्रों में इस संक्रमण के कारण 8,809 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,18,631 लोग इससे संक्रमित हैं।

भारतीय दूतावास ने अमेरिका से भारत के छात्रों की दिक्कतों को दूर करने का अनुरोध किया

वाशिंगटन (भाषा)। भारतीय दूतावास ने कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर यहां अमेरिकी सरकार से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थान बंद होने के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे भारतीय छात्रों की परेशानियों को दूर करने का अनुरोध किया है। 2,00,000 से अधिक भारतीय छात्र विभिन्न अकादमिक संस्थानों में खासतौर से विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। 300 से अधिक शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने परिसर बंद कर दिए हैं, कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं और छात्रों से छात्रावास छोड़ने के लिए कहा है।

भारत और अमेरिका दोनों देशों में यात्रा पाबंदियों और केवल कक्षाओं के लिए ही अमेरिका में रहने की अनुमति देने वाली वीजा शर्तों के कारण भारतीय छात्र मुश्किल में फंस गए हैं। अमेरिका में चीन के बाद भारतीय छात्र सबसे अधिक संख्या में पढ़ाई करने आते हैं। ह्यूस्टन, अटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में पिछले कई दिनों से चौबीसों घंटे हेल्पलाइन चला रहे भारतीय दूतावास और उसके पांच वाणिज्य दूतावासों ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय और नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं से संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि भारत के छात्रों को देश में रहने को लेकर मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने यहां भारतीय छात्रों के लिए जारी संशोधित परामर्श में कहा, अमेरिकी सरकार ने संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पैदा हुई स्थिति पर करीबी नजर रख रही है। परामर्श में कहा गया है कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (एसईवीपी) अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा पर मार्गदर्शन देना जारी रखेगा। एसईवीपी ने हाल ही में पुष्टि की कि अंतरराष्ट्रीय छात्र कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में या उसके बाहर अस्थाई तौर पर दूरस्थ शिक्षा ले सकते हैं।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा कि अगर कोई स्कूल बिना ऑनलाइन दिशा निर्देश या अन्य वैकल्पिक शिक्षण माध्यमों के अस्थाई तौर पर बंद होता है तो छात्र तब तक स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफोर्मेशन सिस्टम (एसईवीआईएस) में सक्रिय रहेंगे जब तक उनकी कक्षाएं बहाल नहीं हो जाती। उसने कहा कि अगर कोई स्कूल अस्थाई रूप से बंद है लेकिन वह ऑनलाइन दिशा निर्देश या अन्य वैकल्पिक तरीके से पढ़ा रहा है तो गैर प्रवासी छात्र इसमें भाग ले सकते हैं और वह एसईवीआईएस में सक्रिय रहेंगे। भारतीय दूतावास और उसके पांच वाणिज्य दूतावासों ने परामर्श में भारतीय छात्रों से गैर आवश्यक घरेलू या अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है, यह अभूतपूर्व स्थिति है लेकिन हम शांत दिमाग से फैसले लेकर इससे सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। कृपया बुद्धिमानी से स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरते और सूचना तथा यात्रा परामर्शों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दें। परामर्श में कहा गया है, 18 मार्च 2020 तक अगर आप अमेरिका से भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको आगमन पर चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और जरूरत पड़ने पर सरकारी केंद्र में कम से कम 14 दिनों के लिए पृथक रहना पड़ सकता है।

ब्रिटेन में बुजुर्ग सिख को धक्का दे कर सुपरमार्केट से बाहर निकालने पर तीखी आलोचना

लंदन (भाषा)। ब्रिटेन में कोरोना वायरस माहामारी को लेकर मची अफरा तफरी के बीच एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति को पूर्वी लंदन में सुपरमार्केट के कर्मचारी द्वारा बदसलूकी कर बाहर निकाले का वीडियो वायरल हुआ है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरस वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति को इल्फोर्ड स्थित आइसलैंड स्टोर में कमर्चारी द्वारा बहस होने पर धक्का देते हुए दिखाया गया है। वीडियो में व्यक्ति लगातार कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी ने उसे धक्का दिया है जिसके बाद उससे दुकान से बाहर निकलने को कहा गया। वीडियो का स्रोत अभी भी अज्ञात है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कर्मचारियों के प्रति गुस्से का प्रदर्शन कर रहे है। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, यह समय आइसलैंड कर्मी द्वारा बुजुर्ग ग्राहक पर हमला करने का नहीं है। हम राष्ट्रीय आपदा का सामना कर रहे और बजुर्ग लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं।

ट्रंप के बाद निक्की हेली ने भी कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तरीके की आलोचना की

भाषा। वाशिंगटन

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली ने घातक कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तरीके की आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विषय पर चीन की आलोचना की थी।

राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों तथा रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक कम से कम 8,736 लोग संक्रमित हैं और 149 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में न्यूयॉर्क (2,900 मामले) और वाशिंगटन (1,187 मामले) शामिल हैं। हेली ने ट्वीट किया, चीन अब यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि संकट से किस तरह से निपटा जाता है और वह उसका सटीक उदाहरण है जबकि सच्चाई यह है कि उसके शुरुआती कदमों के कारण ही वायरस दुनिया भर में फैल गया।

हेली ने अपनी इस टिप्पणी के लिए एक अध्ययन का संदर्भ दिया कि अगर चीनी प्राधिकारियों ने जो कार्वाई की, वह उन्होंने तीन हफ्ते पहले की होती तो कोरोना वायरस के मामले 95 प्रतिशत तक कम हो सकते थे और उसका वैश्विक प्रसार सीमित हो जाता। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आरोप लगाया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने वायरस की शुरुआती खबरों को दबाया और पत्रकारों एवं चिकित्सकों को सजा दी जिसकी वजह से चीनी एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ वैश्विक महामारी को रोकने से चूक गए। हेली के इस ट्वीट से कुछ घंटों पहले ट्रंप ने कहा था कि चीन ने वायरस के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समय रहते नहीं बताया। कोरोना वायरस को लेकर पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और चीन में वाक युद्ध चल रहा है।

कोविड-19 को लेकर छाई निराशा के बीच संरा प्रमुख ने नवरोज के सकारात्मक संदेश लाने की जताई उम्मीद

संयुक्त राष्ट्र (भाषा)। दुनिया भर में घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते छाई निराशा एवं व्यग्रता के माहौल के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने उम्मीद जताई है कि नवरोज का त्योहार सौहार्द लाएगा और साझा मानवता का जश्न मनाने का मौका देगा। अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस के मौके पर दिए अपने संदेश में महासचिव गुतारेस ने कहा कि हर साल नवरोज को नई शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है जब हम उम्मीद और खुशियों के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं। हम प्रकृति के नवीनीकरण और बसंत के पहले दिन का जश्म मनाते हैं। हालांकि गुतारेस ने कहा कि इस साल दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलना बेचैनी, दर्द, पीड़ा और मौत लेकर आया है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के एक ट्रैकर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से उभरे कोरोना वायरस के इस प्रकोप ने 157 देशों एवं क्षेत्रों में 8,809 लोगों की जान ले ली।

कोहली को कैलेंडर वर्ष में शतक का इंतजार

भाषा। नई दिल्ली

विराट कोहली पिछले छह वर्षों में किसी कैलेंडर वर्ष में खेली गई तीसरी पारी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ देते थे लेकिन वर्ष 2020 में पहले खराब फार्म और अब कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कप्तान का इंतजार लंबा खिंच गया है।

कोहली ने इस साल टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 में कुल मिलाकर 16 पारियां खेली हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 89 रन रहा है जो उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरू में 19 जनवरी को एकदिवसीय मैच में बनाया था। यही नहीं 2010 के बाद कोहली के करियर में यह पहला अवसर होगा जबकि वह साल के पहले दो महीनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सैकड़ा नहीं जमा पाए। कोहली वर्ष 2020 में अब तक घरेलू सरजमीं पर श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 और आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे खेले हैं जबकि न्यूजीलैंड दौरे में उन्होंने चार टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेले। इन मैचों की 16 पारियों में वह 30.46 की औसत से 457 रन ही बना पाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।

उम्मीद थी कि कोहली आईपीएल से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे में अपनी फार्म दिखाएंगे लेकिन इस श्रृंखला का धर्मशाला में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जबकि बाकी दो मैच कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिए गए। यह श्रृंखला बाद में खेली जाएगी लेकिन इसका आयोजन इस महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगी जिसके कारण दुनियाभर की खेल प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई हैं। आईसीसी के भविष्य के दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के अनुसार भारत को अपनी अगली श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ जून-जुलाई में खेलनी है जिसमें तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी शामिल हैं। भारत अगस्त में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे की श्रृंखला खेलेगा, जिसके बाद एशिया कप का आयोजन होगा लेकिन ए सभी श्रृंखलाएं कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर होंगी। पिछले कुछ वर्षों में यह पहला अवसर है जबकि कोहली इतनी अधिक पारियों तक तिहरे अंक में नहीं पहुंच पाए। इस स्टार बल्लेबाज ने अपना पहला शतक 24 दिसंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में लगाया था। यह उस कैलेंडर वर्ष में उनकी नौवीं पारी थी। इसके बाद उन्हें केवल 2013 में शतक के लिए आठवीं पारी तक इंतजार करना पड़ा था। कोहली पिछले छह वर्षों में बेहतरीन फार्म में रहे हैं। इस बीच 2014, 2015 और 2017 में तो उन्होंने वर्ष की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय पारी में ही शतक लगाया था जबकि 2016, 2018 और 2019 में उन्हें केवल तीसरी पारी तक इंतजार करना पड़ा था। भारतीय कप्तान ने 2010 से लेकर 2019 तक दस वर्षों में आठ अवसरों पर जनवरी में ही सैकड़े से शुरुआत कर दी थी जबकि दो बार (2011 और 2013) उन्होंने फरवरी तक इंतजार किया। कोहली के नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी 70 शतक दर्ज हैं। इनमें से आधे से अधिक (36) शतक उन्होंने पिछले चार वर्षों (2016 से 2019 तक) लगाए। इस बीच 2017 और 2018 में उन्होंने 11 सैकड़े जमाए लेकिन वर्ष 2020 में शुरू से ही उनका बल्ला कुंद पड़ा हुआ है। कोहली ने वर्ष 2020 में दो टेस्ट मैचों में केवल 38 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 19 रन रहा। उन्होंने इस साल अब तक जो छह वनडे खेले हैं उनमें से तीन में वह 50 रन के पार पहुंचे लेकिन अर्धशतक को शतक में बदलने में माहिर यह करिश्माई बल्लेबाज वर्ष 2020 में अभी तक ऐसा नहीं कर पाया। कोहली ने छह वनडे में 43.00 की औसत से 258 रन बनाए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने सात मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम पर 161 रन दर्ज हैं और उनका उच्चतम स्कोर 43 रन है।

खराब फार्म और कोविड-19 बना कारण

कप्तान और कोच मेरी बल्लेबाजी शैली का महत्व समझते हैं : पुजारा

भाषा। नई दिल्ली

चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि स्ट्राइक रेट को लेकर उनकी आलोचना अनुचित है और उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम प्रबंधन का उन्हें पूरा समर्थन हासिल है जो उनकी बल्लेबाजी शैली के महत्व को समझता है। अब जबकि धूमधड़ाके वाली क्रिकेट का जमाना है तब पुजारा स्ट्राइक रेट की परवाह किए बिना क्रीज पर टिके रहने को महत्व देते है। पिछले सप्ताह रणजी ट्राफी फाइनल में बंगाल के खिलाफ 237 गेंदों पर 66 रन बनाने पर भी उनकी आलोचना हुई थी। उन्होंने जबकि तब बुखार और गले में संक्रमण के बावजूद अर्पित वासवदा के साथ मिलकर मैच का पासा पलटने वाली साझेदारी निभाई थी जिससे सौराष्ट्र पहली पारी में बढ़त हासिल करके पहली बार रणजी चैंपियन बनने में सफल रहा था। सौराष्ट्र हो या भारत पुजारा कहीं से भी खेल रहे हों उन्हें हमेशा अपने स्ट्राइक रेट के कारण आलोचना सहनी पड़ती है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर की खेल गतिविधियां ठप्प पड़ जाने के कारण परिवार के साथ समय बिता रहे पुजारा ने पीटीआई से कहा, मुझे नहीं लगता कि टीम के अंदर इसको लेकर ज्यादा बात होती है। मीडिया में इसका विश्लेषण भिन्न तरह से होता है लेकिन टीम प्रबंधन इस मामले में पूरी तरह से मेरा साथ देता है। कप्तान, कोच या किसी अन्य की तरफ से कोई दबाव नहीं है। अब तक 77 टेस्ट मैचों में 48.66 की औसत से रन बनाने वाले पुजारा ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो लोग टीम प्रबंधन की राय की बात करने लगते हैं लेकिन मुझ पर इसका किसी तरह का दबाव नहीं होता है। टीम प्रबंधन मेरे खेल की शैली और उसके महत्व को समझता है। सोशल मीडिया पर (रणजी फाइनल के दौरान) सवाल किया गया कि मैं इतने रन बनाने के लिए इतना समय क्यों ले रहा है। क्या मैंने ऐसी बातों पर ध्यान दिया। नहीं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि टीम को जीत मिले। लोगों की एक व्यक्ति पर उंगली उठाने की आदत होती है लेकिन यह केवल मुझ तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी भी टेस्ट श्रृंखला पर गौर करो जहां मैंने थोड़ा अधिक समय लेकर रन बनाए हों वहां विरोधी टीम के बल्लेबाजों ने भी उतनी ही अधिक गेंदें खेली। मैं समझता हूं कि मैं डेविड वार्नर या वीरेंद्र सहवाग नहीं बन सकता लेकिन अगर कोई सामान्य बल्लेबाज क्रीज पर समय ले रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। न्यूजीलैंड में सभी भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा और भारत टेस्ट श्रृंखला में 0-2 से हार गया। पुजारा ने इस सत्र में पांच अर्धशतक जमाए हैं लेकिन वह अपने 18 टेस्ट शतकों में कोई इजाफा नहीं कर पाए।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयन कम्पाउण्ड, वेरावाल, गुजरात – 362 266
सीआईएन : U65990GJ1991PLC064603
परिशिष्ट – IV
[नियम 8 (1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 21–06–2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/सह–कर्जदारों मैसर्स बिदुर ऐण्ड कम्पनी प्रा. लि. से इसके निदेशकों/गारंटरों श्री मधुर माधव, श्री केशव माधव, श्रीमती मालती माधव, श्रीमती नूपुर माधव से सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 3,72,66,660.68 (रूपए तीन करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर लाख छियासठ हजार छह सौ साठ तथा पैसे अड़सठ मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 18 मार्च, वर्ष दो हजार बीस को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 की बकाया राशि रू. 3,72,66,660.68 (रूपए तीन करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर लाख छियासठ हजार छह सौ साठ तथा पैसे अड़सठ मात्र) तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन :–
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री केशव माधव और श्रीमती मालती माधव द्वारा संयुक्त रूप से स्वाधिकृत बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति अपार्टमेंट नंबर 02 (कमरा नंबर 502), 5वां तल, रॉयल रिट्रीट–2, चार्म्सवुड विलेज, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। पूरब : सामने अपार्टमेंट नंबर 504, पश्चिम : सामने अपार्टमेंट नंबर 501, उत्तर : खुला, दक्षिण : आकाश/लिफ्ट लॉबी की ओर खुला।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली — हस्ता./–
तिथि : 20–03–2020 — प्राधिकृत अधिकारी

पेस ने कहा, घबराएं नहीं, फर्जी खबरों से बचें

भाषा। नई दिल्ली

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में लोगों को घबराना नहीं चाहिए और फर्जी खबरों के जाल में फंसने से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। घातक कोरोना वायरस के कारण विश्व भर के 157 देशों में अब तक 8809 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2,18,631 लोग संक्रमित हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 169 पर पहुंच गई है। पेस ने ट्वीट किया, अभी हम जंग में एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं जो तेजी से विश्व भर में अपने पांव पसार रहा है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम समाज में अपनी भूमिका निभाएं और स्वस्थ समाज सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने इस संबंध में कई ट्वीट किए हैं और लोगों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह को मानने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हम डब्ल्यूएचओ और भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करें। घबराएं नहीं और फर्जी खबरों के जाल में न फंसे। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस बारे में शिक्षित करने में मदद करें जैसे कि कामगार, जिनके पास आसानी से जानकारी नहीं पहुंचती है।

कोविड-19 के कारण अब वार्न की डिस्टलरी में शराब के बजाय सैनीटाइजर

भाषा। मेलबर्न

कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए महान क्रिकेटर शेन वार्न की डिस्टलरी में अब एल्कोहल युक्त सैनीटाइजर बनाना शुरू कर दिया है जो पहले जिन (एक तरह की शराब) बनाती थी। इस महामारी से अब तक पूरी दुनिया में दो लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 9000 लोगों की जान चली गई है। आस्ट्रेलिया में हाथ धोने के लिए सैनीटाइजर की कमी हो रही है।

वार्न की कंपनी 708 जिन ने अब 17 मार्च से मेडिकल ग्रेड का 70 प्रतिशत एल्कोहल युक्त सैनीटाइजर बनाना शुरू कर दिया है जो आस्ट्रेलिया के दो अस्पतालों के लिए होगा। वार्न ने बयान में कहा, यह आस्ट्रेलिया के लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इस बीमारी से बचने और लोगों को बचाने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मदद के लिए वो सब करना होगा जो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं कि सेवनजीरोऐट ऐसा बदलाव कर सकती है और अन्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आस्ट्रेलिया में अब तक 565 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि छह लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते मामलों से आस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में हैंड सैनीटाइजर की काफी मांग बढ़ गई है और इसे खरीदने को लेकर अफरातफरी मच रही है।

NOTICE
REDCLIFFE LIFESCIENCE PRIVATE LIMITED
CIN: U74999HR2017PTC070597
Notice is hereby given that with effect from 18-03-2020 the Registered Office of company has been changed from DCT 908, DLF CITY COURT, SIKANDERPUR, GURGAON, HARYANA, INDIA 122002 to H-55, SECTOR-63, ELECTRONIC CITY NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA 201301. All further communication should henceforth be made at the aforesaid address. The Lab Address is also shifted from BUILDING NO 14, 2ND FLOOR, KAUSHALYA PARK, HAUZ KHAS, NEW DELHI, INDIA 110016 to H-55, SECTOR 63, ELECTRONIC CITY NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA 201301. By order of the Board
for REDCLIFFE LIFESCIENCE PRIVATE LIMITED.
Ashish Kumar Dubey
Director
DIN : 08208093
Dated: 18/03/2020

PUBLIC NOTICE
Be it known to all that my client Mr. Bharat Lal Sharma (Father), S/o Sh. Badri Nath & Smt Rani Sharma (Mother), W/o Sh. Bharat Lal (herein referred to as Father & Mother of Mr. Harish Sharma respectively), R/o B-181, Tagore Garden Extn. West Delhi, Delhi-110027, are divesting and debarring their son Mr. Harish Sharma, R/o B-181, Tagore Garden Extn. West Delhi, Delhi- 110027 from being in their relation & of all his rights accrued because of being in their relation. Since he has been divested and debarred of all his rights and have no prerogative whatsoever in any manner with my clients, He is also debarred from all moveable and immoveable properties. Anybody/ individually or in a group/person / corporate, whatsoever, is in relation with Mr. Harish Sharma or in anyways deal with him would be solely responsible for his/their acts and deeds.
Sanjeev Kohli (Advocate)
Ch. No.-393, Pataila House Court,
New Delhi-110001

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरि सिंह पुत्र स्व श्री शाम सिंह पता ए–28/7, डी.एल.एफ.कुतुब इन्कलेव, फेज–1, गुडगांव–122002 हरियाणा निम्नलिखित संपत्ति के कानूनी आंशिक/सह–मालिक है।

2616 (सभी तल और खंड 2616/2, 2616–A, 2616 C को छोड़कर)	म्यूनिसिपल न0 2616, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2632–2635 (खंड 1–F)	खंड '1-F' म्यूनिसिपल न0 2632–2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2632–2635 (खंड 2–G)	खंड '2-G' म्यूनिसिपल न0 2632–2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2632–2635 (खंड 6–K)	खंड '6-K' म्यूनिसिपल न0 2632–2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2632–2635 (खंड 10–O)	खंड '10-O' म्यूनिसिपल न0 2632–2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2632–2635 (खंड 11–P)	खंड '11-P' म्यूनिसिपल न0 2632–2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2633 (सभी तल और खंड 2633–A को छोड़कर)	म्यूनिसिपल न0 2633, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2636 (सभी तल और खंड)	म्यूनिसिपल न0 2636, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2607 (सभी तल और खंड)	म्यूनिसिपल न0 2607, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.
2626 (सभी तल और खंड 2626–B, 2626–C को छोड़कर)	म्यूनिसिपल न0 2626, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006
2632 (सभी तल और खंड)	म्यूनिसिपल न0 2632, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006
2635 (सभी तल और खंड)	म्यूनिसिपल न0 2635, खंड कश्मीरी गेट, वार्ड नं0 01, जोरावर सिंह मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006

उपर्युक्त संपत्ति में से किसी पर अपने एकमात्र स्वामित्व प्रदर्शित करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी और स्वामित्व रिकॉर्ड के खिलाफ होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकारपूर्वक ऐसा मान लेना या पंजीकृत करना इत्यादि, उसके स्वयं के जोखिम, लागतों और परिणामों पर निर्भर करेगा। इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा ऐसे पंजीकृत या अपंजीकृत प्राधिकारी को गैर कानूनी माना जायेगी। इस सूचना की प्रकाशन तिथि से ऐसे अधिकारों को वापस ले लिया जाये। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, पट्टेदार किसी अनधिकृत व्यक्तियों को किराए या किरायेदारी के अधिकार का भुगतान करने वाले, उपरोक्त जोखिमों, लागतों और परिणामों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगें और सभी किराए और उनके द्वारा लिए गए मुनाफे के लिए श्री हरि सिंह के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। यह अधिसूचित किया जाता है कि किसी भी अधिकार या अधिकार के तहत कब्जे में किसी भी स्थायी या अस्थायी संरचना, जो कि आसपास के क्षेत्र में या सहज क्षेत्र के भीतर और न केवल मार्ग के क्षेत्र तक सीमित है, श्री हरि सिंह के सह–स्वामित्व में होगा। हरि सिंह ऐसे क्षेत्र से किसी भी उपयोग बिक्री की आय श्री हरि सिंह को देय हिस्सा होगी और उसे केवल विधिवत रूप से अभिदाता पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में, कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
नेल्सन स्टड वेल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका सीआईएन : यू74999डीएल2016एफटीसी299623 है तथा वर्तमान पंजीकृत कार्यालय ए–115, वकील चैम्बर्स चैम्बर नंबर 210–211, शकरपुर, नई दिल्ली–110092 में स्थित है, के विषय में,
.....आवेदक कम्पनी
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तमिलनाडु राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 18 मार्च, 2020 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन (14 दिन) के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति याचिकादाता कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
"ए–115, वकील चैम्बर्स चैम्बर नंबर 210–211, शकरपुर, नई दिल्ली–110092"
कृते एवं हिते
नेल्सन स्टड वेल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
श्रीधरन सुब्रमनियन
तिथि : 20–03–2020 — डीआईएन : 08126666
स्थान : दिल्ली — निदेशक

बनर्जी की स्थिति अब भी नाजुक

भाषा। कोलकाता

अपने जमाने के दिग्गज फुटबालर और दो बार के ओलंपियन पी के बनर्जी को गुरूवार को फिर रक्त चढ़ाया गया और उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। बनर्जी का अभी मेडिका सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है जिन्होंने गुरूवार को यह जानकारी दी और कहा कि निमोनिया के कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें सेप्सिस है। अस्पताल के अनुसार, उन्हें फिर से रक्त चढ़ाया गया। उन्हें अब भी हेमोडायलिसिस पर रखा गया है और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बनर्जी के कई अंगों ने निमोनिया के कारण काम करना बंद कर दिया है। वह पर्किन्सन, डिमेन्शिया और हृदय संबंधी रोगों से भी पीड़ित रहे हैं। बनर्जी को पिछले दो सप्ताह से भी अधिक समय से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।

पीएसएल के दौरान किए गए कोविड-19 के सभी परीक्षण नेगेटिव रहे : पीसीबी

भाषा। कराची

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गुरुवार को दावा किया कि पीएसएल में शामिल रहे खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ, मैच अधिकारियों, प्रसारकों और टीम मालिकों के कोविड-19 को लेकर किए गए कुल 128 परीक्षण में किसी को भी इस घातक बीमारी से संक्रमित नहीं पाया गया। पीसीबी ने 17 मार्च को ए परीक्षण किए थे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स ने सोमवार को कोविड-19 के 17 परीक्षण किए और इनके परिणाम भी नेगेटिव रहे।

पीसीबी के मुख्य कार्यकारी वसीम खान ने कहा, यह पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अखंडता और विश्वसनीयता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि टूर्नामेंट के आखिर तक यहां रुके रहने का फैसला करने वाले सभी खिलाड़ियों, सहयोगी कर्मचारियों, प्रसारकों और मैच अधिकारियों के कोविड-19 के लिए किए गए परीक्षण नेगेटिव रहे। पीसीबी परीक्षणों के परिणाम से खुश है और उसे खुशी है कि सभी खिलाड़ी और अधिकारी किसी तरह की स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के बिना अपने परिजनों से जुड़ सकते हैं। पीसीबी को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण पाकिस्तान सुपर लीग को नाकआउट चरण से स्थगित करना पड़ा था। इस बीच सूत्रों ने कहा कि बोर्ड प्रसारण से जुड़े 29 भारतीय सदस्यों के लिए वापसी की उड़ान की व्यवस्था कर रहा है। इन सभी को बुधवार को बाघा- अटारी बार्डर से भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। सूत्रों ने कहा, भारतीय स्टाफ को वाघा के जरिए सड़क के रास्ते स्वदेश लौटना था लेकिन उन्हें रोक दिया गया और अटारी से उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके यात्रा दस्तावेजों के अनुसार वे केवल हवाई यात्रा से ही वापस लौट सकते थे।

इंग्लैंड में फुटबाल मैच 30 अप्रैल तक बंद

भाषा। लंदन

इंग्लैंड ने प्रीमियर लीग और इंग्लिश फुटबाल लीग (ईएफएल) के बीच हुई आपात बैठक के बाद गुरूवार को फुटबाल मुकाबले 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। इंग्लिश फुटबाल संघ, प्रीमियर लीग, ईएफएल, खिलाड़ियों और मैनेजरों की संस्थाओं द्वारा संयुक्त बयान के अनुसार, हमने मिलकर फैसला किया है कि इंग्लैंड में पेशेवर मैचों को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। इसके मुताबिक, हम अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं कि 2019-20 फुटबाल संघ को फिर से शुरू करने का तरीका निकालेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी घरेलू और यूरोपीय क्लब लीग और कप मैच जल्द से जल्द खेले जाएं जैसे ही इनका आयोजन संभव हो और ऐसा करना सुरक्षित हो।

कार्यालय ग्राम पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर, विकास खण्ड भोजपुर (गाजियाबाद)
पत्रांकः– ..../नि–प्रकाशन/ग्रा0पं0 किल्हौड़ा रघुनाथपुर/2019–20 — दिनांकः– 14.03.2020
अतिअल्पकालीन निविदा सूचना
ग्राम पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर विकास खण्ड भोजपुर गाजियाबाद में राज्य वित्त आयोग/14वॉ वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 के सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नलिखित निर्माण कार्यो की निविदाऐं दिनांक 20/03/2020 को अपरान्ह 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 15/03/2020 से 20/03/2020 तक कार्यालया समय मे ग्राम पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर, विकास खण्ड भोजपुर (गाजियाबाद) से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा अधिकृत अधिकारियों द्वारा इच्छुक ठेकेदारो की उपस्थिति में दिनांक 21/03/2020 को उपरान्ह 02:00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 स0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रू0 मे)	धरोहर राशि (रू0 मे)	निविदा मूल्य	कार्या अवधि
1.	मैन रोड़ से बाबू तक नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य	331624/–	6800/–	150+GST+500	1 माह

नियम व शर्तेः–
1. अरनेस्ट मनी निविदा डालने के समय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/पास बुक के रूप मे दी जा सकती है जो ग्राम पंचायत पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर, विकास खण्ड भोजपुर (गाजियाबाद) के पदनाम से बन्धक की जा सकती है।
2. कार्य पी0डब्लू0डी0 की विशिष्टियो के अनुरूप होगा
3. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
4. निविदा केवल सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारो को ही देय होगी।
5. ठेकेदार का पंजीयन उप श्रमायुक्त हापुड़ के यहा होना चाहिए तथा ठेकेदार को प्रत्येक कार्य का पंजीकरण उप श्रमायुक्त कार्यालय हापुड़ में कराना अनिवार्य होगा।
6. निविदा प्रपत्र के साथ 100रू क नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रसीदी टिकिट के साथ लगाए।
7. नियमानुसार सभी शासकीय कटौतिया की जायेगी।
8. अन्य नियम व शर्तें लागू रहेंगी।

प्रधान — सचिव
ग्राम पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर — ग्राम पंचायत किल्हौड़ा रघुनाथपुर
विकास खण्ड भोजपुर — विकास खण्ड भोजपुर

THE PIONEER CLASSIFIEDS
CHANGE OF NAME
I, Shuaib Akhtar S/o Shri Faheem Akhtar R/o House No. T-406/5, Gali No-20, Near Water Tank, Gautampuri Delhi-110053, hereby declare that my old name is Shauib Akhtar and my new name is Shuaib Akhtar. henceforth I Shall be known as Shuaib Akhtar for all future purposes.
PD(8864)C

दुखद है कि सब कुछ ठप्प पड़ गया है : स्टेन

भाषा। जोहानिसबर्ग

कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान में होटल में कैद की स्थिति झेलने के बाद अब स्वदेश में आराम फरमा रहे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि यह दयनीय स्थिति है कि इस महामारी की वजह से दुनिया भर की खेल प्रतियोगिताएं रद्द कर दी गई हैं। स्टेन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पाकिस्तान से स्वदेश लौट गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घंटों में पूरी स्थिति बदल गई उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वह पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाईटेड की तरफ से खेल रहे थे। इस लीग को सेमीफाइनल से पहले ही निलंबित कर दिया गया था। स्टेन ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से कहा, यह वास्तव में दयनीय स्थिति है सब कुछ ठप्प पड़ गया है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में हम पूर्व में संस्कृति, धर्म, जातीय पृष्ठभूमि के कारण कई तरह की परेशानियों को झेलते रहे हैं और ऐसे में हमें एक चीज साथ में लाती थी और वह था खेल। लेकिन अभी वह भी नहीं हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में हम ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जो लोगों को एकजुट करती हो। जब खेल नहीं हो रहे हों तो अब क्या होगा। मुझे याद है कि नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में कहा था कि खेल लोगों को जिस तरह से एकजुट करता है वैसा कुछ और नहीं कर सकता।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 मार्च, 2020

आईपीएल न खेलने पर आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को होगा बड़ा नुकसान

भाषा। मेलबर्न

आस्ट्रेलिया की एक दिवसीय टीम के कप्तान आरोन फिंच ने कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल और उनके घरेलू सत्र का आयोजन नहीं हो पाता है तो उनके देश के क्रिकेटरों को बड़ा वित्तीय नुकसान होगा लेकिन उन्हें स्थिति को स्वीकार करना होगा क्योंकि इसमें हम सब एक साथ हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया पहले ही कह चुका है कि वह आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को दिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की समीक्षा करेगा और अब सरकार ने यात्रा पाबंदियां भी लगा दी है जिससे इस टी20 लीग के बाद में शुरू होने पर भी उसमें आस्ट्रेलियाई

क्रिकेटरों का भाग लेना मुश्किल हो सकता है। आईपीएल पहले 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन अब उसे 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। फिंच ने रेडियो स्टेशन एसईएन से कहा, जब आप राजस्व साझा करने के मॉडल का हिस्सा होते हैं तो ऐसे में संगठन के मुश्किल में पड़ने पर आप भी प्रभावित होते है। हम समझते हैं कि

● फिंच ने कहा हम सब साथ हैं

इसमें हम सब एक साथ है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लंबे समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब होगा। आस्ट्रेलिया के कम से कम 17 क्रिकेटरों का आईपीएल के साथ अनुबंध है। इसके अलावा उसके कई अन्य लोग भी मैदान से इतर इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। आस्ट्रेलिया को इस साल के आखिर में टेस्ट श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए भारत की मेजबानी करनी है। फिंच को भरतीय कप्तान विराट कोहली की अगुवाई वाली रायल चैलेंजस बेंगलोर से खेलना है। उन्होंने कहा, हमने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया। यात्रा को लेकर सलाह पिछले कुछ घंटो में बदल गई है। यह दो सप्ताह या तीन सप्ताह में बदल सकती है। कुछ भी योजना बनाना मुश्किल है। आईपीएल नीलामी में आस्ट्रेलिया के पैट कमिन्स सर्वाधिक कीमत पर बिके थे। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल को भी मोटी धनराशि पर खरीदा गया था। रिकी पोंटिंग दिल्ली डेयरडेविल्स के जबकि एंड्रयू मैकडोनाल्ड राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं। पूर्व टेस्ट बल्लेबाज साइमन कैटिच आरसीबी के कोच हैं जहां उनके सहायक एडम ग्रिफिथ हैं।

सोमवार से घर से काम करेंगे आईओए कर्मचारी

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने मुख्यालय से अधिकतर कामकाज को बंद करने के लिए तैयार है और वह अपने कर्मचारियों को अगले सप्ताह से घर से काम करने के लिए कहेगा। आईओए के एक सदस्य ने पीटीआई से कहा, आईओए सोमवार से अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम की सुविधा मुहैया कराएगा। हम अभी यह सुनिश्चित कर रहे है कि घर से सही तरह संचालन के लिए सभी प्रणाली उचित तरीके से काम करें। कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन गंभीर बनता जा रहा है और हम अपने कर्मचारियों को जोखिम में नहीं डाल सकते। इस महामारी के कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मुंबई में अपना मुख्यालय अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है। बीसीसीआई ने अपने कर्मचारियों को 16 मार्च से ही घर से काम करने के लिए कह दिया था।

काउंटी सत्र बचाने के लिए चर्चा में लगा है ईसीबी

लंदन। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) लगातार फैल रही कोविड-19 महामारी को देखते हुए आगामी काउंटी सत्र के लिए संभावित योजना तैयार करने पर लगा हुआ है। ईसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी तरह की क्रिकेट निलंबित कर दी है जिनमें सत्र पूर्व मैत्री मैच और अभ्यास कार्यक्रम भी शामिल है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ईसीबी काउंटी के मुख्य कार्यकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस करके उन पहलुओं पर चर्चा की जिससे काउंटी चैंपियनशिप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल से शुरू हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी ताकि कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट स्थगित या रद्द करने पर फैसला किया जा सके। इसमें कहा गया है कि कान्फ्रेंस के दौरान चैंपियनशिप की छोटा करने, इसे खाली स्टेडियमों में आयोजित करने और इसकी अवधि कम करने पर चर्चा की गई। काउंटी सत्र सितंबर तक चलता है। ईसीबी ने कहा कि सरकार की सामाजिक दूरी की हाल की सलाह के बाद वह निराशा और अनिच्छा के साथ सभी तरह की क्रिकेट को निलंबित करने का फैसला कर रहा है। ईसीबी के बयान में प्रशिक्षण, सत्र से पूर्व के मैत्री मैच और किसी भी तरह की क्रिकेट गतिविधियां शामिल हैं। यूनाईटेड किंगडम कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। वहां अभी तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार से अधिक संक्रमित हैं।

ट्रेनिंग में जुटी भारतीय महिला हाकी टीम

बेंगलुरू। भारतीय महिला हाकी टीम कोविड-19 महामारी के भय के बावजूद योजना के अनुसार अगले हफ्ते से कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देगी और स्ट्राइकर नवनीत कौर का कहना है कि उनकी निगाहें ओलंपिक पर लगी है। हालांकि इस समय ओलंपिक के आयोजन पर संशय बना हुआ है। टीम को 2020 तोक्यो ओलंपिक खेलो के लिए पूल ए में रखा गया है जिसमें उनके साथ शीर्ष रैंकिंग की टीम जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। नवनीत कौर ने कहा, हम ओलंपिक में अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे और हम उनके खिलाफ मुकाबले को लेकर काफी रोमांचित है क्योंकि हमने पहले उनका सामना नहीं किया है। हमें इन टीमों से भिड़ने का भय नहीं है और हम अच्छी तरह तैयारी करने पर ध्यान लगाए है। हम इस समय एक हफ्ते की उबरने की प्रक्रिया में है जिसमें हलका जिम अभ्यास, स्ट्रेचिंग और स्विमिंग पूल में तैरना शामिल है।

दक्षिण अफ्रीकी गोल्फर लेंज कोविड-19 से संक्रमित

लास एंजिलिस। दक्षिण अफ्रीकी गोल्फर विक्टर लेंज को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। पीजीए टूर ने यह जानकारी दी। विश्व में 1215वें नंबर के खिलाड़ी लेंज को मैक्सिको में पीजीए टूर से लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में की गई जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। पीजीए टूर ने बयान में कहा, हम विक्टर के अपनी बीमारी के तुरंत खुलासे की सराहना करते है। इससे पीजीए टूर को उन लोगों को सतर्क करने का मौका मिल गया जो इस सत्र में लेटिन अमेरिका पीजीए टूर के दौरान उनके संपर्क में आए थे। कोरोना वायरस का अन्य खेल प्रतियोगिताओं की तरफ गोल्फ पर भी प्रभाव पड़ा है तथा उसकी दो प्रमुख प्रतियोगिताएं मास्टर्स और पीजीए चैपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है।

चोट के कारण समरसेट की तरफ नहीं खेल पाएंगे वेड

सिडनी। आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड इस सत्र में इंग्लिश काउंटी समरसेट की तरफ से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्हें घुटना चोटिल होने के कारण विश्राम की सलाह दी गई है। इस 32 वर्षीय बल्लेबाज को काउंटी क्रिकेट के पहले सत्र में भाग लेना था लेकिन क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने उन्हें चोट से उबरने के लिए विश्राम करने की सलाह दी है। यह बड़ा झटका है। मै काउंटी क्रिकेट में खेलने की चुनौती के लिए तैयार था लेकिन क्रिकेट आस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम के साथ चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मै समरसेट से जुड़ने की स्थिति में नही हूं। काउंटी सत्र 12 अप्रैल से शुरू होना है लेकिन कोराना वायरस के कारण इसे टाला जा सकता है।

डब्ल्यूटीए, एटीपी ने सात जून तक सत्र स्थगित किया

वाशिंगटन। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट सात जून तक स्थगित कर दिए गए है। एटीपी और डब्ल्यूटीए ने बुधवार को घोषणा की कि क्लेकोर्ट का पूरा सत्र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नही होगा। इससे एक दिन पहले फ्रेंच ओपन ने घोषणा की थी मई मे क्ले कोर्ट पर होने वाला वर्ष का यह दूसरा ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। एटीपी और डब्ल्यूटीए टूर ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह अप्रैल के आखिर या मई के शुरू तक टूर्नामेंटो को निलंबित कर सकता है। नई घोषणा के बाद जिन टूर्नामेंट पर असर पड़ेगा मे उनमें पुरुष और महिलाओं के मैड्रिड और रोम टूर्नामेंट भी शामिल है। जिन टूर्नामेंट को रद्द किया गया है उनमे डब्ल्यूटीए के स्ट्रासबोर्ग (फ्रांस) और रबात (मोरक्को) तथा एटीपी के म्यूनिख, पुर्तगाल, जेनेवा और फ्रांस के लियोन मे होने वाले टूर्नामेंट शामिल है। दोनों टूर ने कहा कि आगामी नोटिस तक रैंकिंग जस की तस बनी रहेगी और उसमे कोई बदलाव नही होगा। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने अपने निचली श्रेणी के टूर्नामेंट को सात जून तक रद्द कर दिया है।

एफआईएच प्रो लीग का स्थगन 17 मई तक बढ़ा

लुसाने। अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रो लीग के सभी मैचो को अब 17 मई तक स्थगित कर दिया है। इनमें भारत के मैच भी शामिल है। एफआईएच ने पिछले शनिवार को प्रो लीग के सभी मैचो को 15 अप्रैल तक स्थगित किया था। विश्व हाकी की सर्वोच्च खेल संस्था ने बयान में कहा, कोविड-19 प्रकोप के ताजा घटनाक्रम के आधार पर और विश्व भर संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर एफआईएच ने सभी भागीदार राष्ट्रीय महासंघ के समर्थन से एफआईएच हाकी प्रो लीग को स्थगित करने की समयसीमा 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। भारतीय पुरुष टीम को 25 और 26 अप्रैल को जर्मनी के खिलाफ बर्लिन में दो मैच खेलने थे जबकि इसके बाद उसने लंदन दो और तीन मई को ग्रेट ब्रिटेन का सामना करना था। भारत को इसके बाद 23 और 24 मई को न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है और फिर उसे पांच और छह जून को अर्जेंटीना से भिड़ने के लिए टुकुमान जाना है। भारत का एफआईएच प्रो लीग मे आखिरी मुकाबला स्पेन से होगा जिससे उसे वेलेसिया मे 13 और 14 जून को खेलना है।

स्थगित हो सकता है ओलंपिक !

● विश्व एथलेटिक्स संस्था के प्रमुख को ने स्वीकारा

भाषा। लंदन

विश्व एथलेटिक्स संस्था के प्रमुख सेबेश्चियन को ने गुरूवार को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण तोक्यो ओलंपिक को इस साल के अंत तक स्थगित किया जा सकता है लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित फैसला करने के लिए यह जल्दबाजी होगी। ओलंपिक प्रमुखों ने बुधवार को स्वीकार किया था कि खिलाड़ियों की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए कोई आदर्श हल नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक खेल कैलेंडर पर काफी असर पड़ा है क्योंकि इससे कारण यूरो 2020 को स्थगित कर दिया गया जबकि टेनिस सत्र निलंबित हो गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थामस बाक ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि उनका लक्ष्य इन खेलों को 24 जुलाई से ही शुरू करने का ही होगा। तोक्यो ओलंपिक समन्वयक आयोग के सदस्य को ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि देरी संभव है। जब को से पूछा गया कि खेलों को सितंबर या अक्टूबर तक स्थगित किया जा सकता है तो उन्होंने कहा, यह संभव है, इस समय कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि खेल ऐसी स्थिति में आ गए हैं और उस दिन आईओसी ओर अन्य महासंघों के साथ बातचीत में जो माहौल था, उसे देखते हुए कोई भी ऐसा नहीं कह रहा था कि कुछ भी हो हमें खेलों का आयोजन करना ही है। को ने कहा, लेकिन यह ऐसा फैसला नहीं है कि इसे इसी समय करना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 2021 तक स्थगित करना समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि सदस्य महासंघ ओलंपिक वर्ष में विश्व चैम्पियनशिप आयोजित नहीं करते।

आईओए को भी उम्मीद, सही समय पर होंगे तोक्यो ओलंपिक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने गुरूवार को आईओसी के इस बयान का समर्थन किया कि तोक्यो ओलंपिक बिना किसी परेशानी के समय पर शुरू होंगे। कोविड-19 के कारण भले ही दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं और अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और तोक्यो खेल आयोजक खेलों को 24 जुलाई से ही शुरू करने पर अडिग हैं।

आईओए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पीटीआई से कहा, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर रखी है लेकिन हमें उम्मीद है कि एक या दो महीने में इस पर काबू पा लिया जाएगा। इस बीमारी के केंद्र में रहे चीन में इस पर नियंत्रण पा लिया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओलंपिक बिना किसी बाधा के सही समय पर शुरू होंगे। लेकिन आईओसी हमारी सर्वोच्च संस्था है और आईओसी जो भी फैसला करेगी हमें उसका पालन करना होगा। अगर आईओसी कहती है कि ओलंपिक होंगे तो फिर कोई भी परेशानी हो हमें उनमें भाग लेना होगा। आईओसी के रवैए से कई खिलाड़ी नाराज है और उन्होंने विश्व संस्था पर उन्हें जोखिम में डालने का आरोप लगाया। कुछ अधिकारियों ने भी आशंकाएं व्यक्त की है। इनके जवाब में आईओसी ने बुधवार को कहा था कि वर्तमान स्थिति का कोई आसान समाधान नहीं है। आईओए ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के कारण उनकी तैयारियां बुरी तरह प्रभावित हुई है लेकिन अगर ओलंपिक खेल होते हैं तो अब भी उसे दस या इससे अधिक पदक जीतने की उम्मीद है। हां, यह सही है कि हमारी तैयारियां प्रभावित हुई हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कई ओलंपिक क्वालीफायर, परीक्षण प्रतियोगिताएं और विदेशों में लगने वाले अभ्यास शिविर स्थगित या रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा भारत के साथ ही नहीं हुआ है। प्रत्एक देश इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है, इसलिए भाग लेने वाले प्रत्एक देश पर इसका बराबर प्रभाव पड़ा है। इसलिए हमें अब भी तोक्यो खेलों से दस या इससे अधिक पदकों की उम्मीद है।

यूनान ने तोक्यो को सौंपी ओलंपिक मशाल

एथेंस। यूनान ने कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक को स्थगित करने की अपीलों के बीच गुरूवार को यहां बंद दरवाजों के अंदर आयोजित किए गए समारोह में तोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंपी। दर्शकों की गैरमौजूदगी में ओलंपिक जिम्नास्ट चैंपियन लेफ्टेरिस पेट्रोनियास मशाल मशाल लेकर दौड़ लगाई जबकि ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन कैटरीना स्टेफनिडी ने पैनथैनेसिक स्टेडियम के अंदर ओलंपिक अग्निकुंड को प्रज्ज्वलित किया। इसी स्टेडियम में 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। इसके बाद यह मशाल तोक्यो 2020 के प्रतिनिधि नाओको इमोतो को सौंप दी गई। इमोतो तैराक हैं और उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। यूनिसेफ की प्रतिनिधि इमोतो को आखिरी क्षणों में नियुक्त किया गया क्योंकि वह यूनान में रहती हैं ओर उन्हें जापान से यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले सप्ताह प्राचीन ओलंपिया में मशाल प्रज्जवलित करने का समारोह भी दर्शकों के बिना आयोजित किया गया था।

15 अप्रैल तक टूर्नामेंट और ट्रायल का आयोजन नहीं कराएं

● मंत्रालय की एनएसएफ को सलाह

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने गुरूवार को सभी राष्ट्रीय महासंघों को 15 अप्रैल तक टूर्नामेंट और चयन ट्रायल आयोजित करने से रोक दिया और साथ ही कहा कि ओलंपिक जाने वाली टीम के खिलाड़ियों को किसी अन्य एथलीट से दूर रखा जाए जो ट्रेनिंग शिविर का हिस्सा नहीं है। ये निर्देश कोविड-19 महामारी के चलते दिए गए हैं जिसने दुनिया भर में खेल प्रतियोगिताओं पर बड़ा असर डाला है। इससे आगामी एथलेटिक्स इंडियन ग्रां प्री के आयोजन पर सवाल उठ गया है जो शुक्रवार से शुरू होनी है। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों को लिखे पत्र में कहा, सभी खेल संस्थाओं और उनकी

मान्यता प्राप्त इकाइयों को 15 अप्रैल 2020 तक किसी भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराने की सलाह दी जाती है जिसमें टूर्नामेंट के अलावा चयन ट्रायल भी शामिल हैं। साथ ही मंत्रालय ने महासंघों से कहा कि वे ओलंपिक ट्रेनिंग शिविर में किसी अन्य एथलीट, कोच या सहयोगी स्टाफ को कोविड-19 महामारी के लिए पृथक रखने के प्रोटोकाल का पालन किए बिना शामिल होने की अनुमति नहीं दें। मंत्रालय ने दो-बिंदु निर्देश में कहा, जहां ट्रेनिंग चल रही हो, उस परिसर में बाहर से एथलीट के संपर्क में आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार, पृथक रखने के प्रोटोकाल का पालन किए बिना किसी कोच, तकनीकीसहायक स्टाफ एथलीट को ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने या मिलने की अनुमति नहीं होगी जो ट्रेनिंग शिविर का हिस्सा नहीं हैं और ट्रेनिंग परिसर में नहीं रह रहे हैं। खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि खिलाड़ियों को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए सभी ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी एथलीट, कोच या सहयोगी स्टाफ यात्रा करने से बचे ताकि किसी अन्य से संपर्क में नहीं आए। किसी भी तरह की सामूहिक सभा पर पूरी तरह रोक है। हमने सिर्फ उन लोगों को छूट दी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है या फिर क्वालीफाइंग के करीब हैं। वे काफी अहम है क्योंकि अगर वे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे तो इससे हमारी तोक्यो ओलंपिक की तैयारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। रीजीजू ने कहा, इसके लिए भी बाहरी लोग प्रतिबंधित होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

कोविड-19 प्रभावित देशों से लौट रहे खिलाड़ियों को पृथक रखा जाएगा: रीजीजू

नई दिल्ली। खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को कहा कि कोविड-19 प्रभावित देशों से लौट रहे खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से पृथक रहना होगा लेकिन उन्होंने आईपीएल और तोक्यो ओलंपिक को लेकर चल रही अटकलबाजियों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी कोरोना-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और उन्होंने खिलाड़ियों के लिए प्रोटोकाल के बारे में बताते हुए कहा कि अन्य सभी के लिए जो अनिवार्य है, खिलाड़ियों को भी उनका पालन करना होगा। रीजीजू ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो खिलाड़ी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से वापस आ रहे हैं, उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार पृथक रहना होगा। इसमें कोई छूट नहीं होगी। जो भी विदेश से आएगा, उन्हें अलग रहना होगा और खिलाड़ियों को भी इसका पालन करना होगा। इस समय शीर्ष शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यात्रा संबंधित पांबदियों के कारण भारत लौटने में विलंब हो रहा है और उन्होंने जर्मनी में खुद को अलग रखा है। पहलवान विनेश फोगाट और भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने वापसी में यूरोप में अपनी ट्रेनिंग छोड़कर लौटने का फैसला किया। इन सभी ने लौटने के बाद खुद को अलग रखा है। भारतीय मुक्केबाजों के बारे में पूछने के बारे में उन्होंने कहा, उनका परीक्षण हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कोविड-19 का पाजीटिव नहीं पाया गया है। उन्हें खतरा नहीं है लेकिन परामर्श यही होगा कि वे अलग रहें।

एएफआई ने इंडियन ग्रां प्री रद्द की

● अगले महीने का फेड कप स्थगित किया

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने गुरूवार को सरकार के कोविड-19 महामारी से बचने के लिए दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कुछ घंटे पहले इंडियन ग्रां प्री को रद्द कर दिया। खेल मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय महासंघों को 15 अप्रैल तक टूर्नामेंट या ट्रायल आयोजित करने से बचना चाहिए। इस टूर्नामेंट का आयोजन शुक्रवार से पटियाला के एनआईएस में होना था।

अगले महीने की फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप (10 से 13 अप्रैल) को भी बाद की तारीख तक स्थगित कर दिया गया जो तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है। भारतीय एथलेटिक्स हाई परफोरमेंस निदेशक वोल्कर हरमान ने पीटीआई से कहा कि एएफआई को सरकारी निर्देश का पालन करना होगा। हरमान ने कहा, पटियाला में होने वाली इंडियन ग्रां प्री शुक्रवार से आयोजित नहीं की जाएगी। यह उन खिलाड़ियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खेलों की तुलना में भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य ज्यादा अहम है। इसलिए हमने शुक्रवार से शुरू होने वाली पहली इंडियन ग्रां प्री को रद्द करने का फैसला किया है। दूसरी ग्रां प्री (भी 25 मार्च से पटियाला में होने वाली थी) को भी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, सभी खेल टूर्नामेंट 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए हैं और एएफआई लोगों के स्वास्थ्य के लिए देश के हित में लिए गए सरकार के फैसले का सम्मान करता है। पटियाला में 10 से 13 अप्रैल तक निर्धारित किए गए फेडरेशन कप के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, एएफआई के पास सरकार के फैसले का सम्मान करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सभी खेल प्रतियोगिताओं पर निलंबन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा तो फेडरेशन कप स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा, हम कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए मई या जून में फेडरेशन कप का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इसके आयोजन के बारे में नहीं बता सकते लेकिन हमें अभी विकल्प खुले रखने होंगे क्योंकि ओलंपिक अब भी होने हैं।

स्पेनिश, मोनाको और डच फार्मूला वन ग्रां प्री स्थगित

पेरिस। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया मे फैलने के कारण गुरुवार को डच, स्पेनिश और मोनाको फार्मूला वन ग्रां प्री रेस को स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने इसकी घोषणा की। सत्र की शुरूआती रेस आस्ट्रेलियाई ग्रां प्री को भी पिछले हफ्ते रद्द कर दिया गया था जबकि चाइनीज, बहरीन और वियतनाम ग्रां प्री रेस को स्थगित किया गया था। फार्मूला वन और एफआईए (अंतरराष्ट्रीय आटोमोबाइल महासंघ) के संयुक्त बयान के अनुसार, दुनिया भर में कोविड-19 से पैदा हुए नाजुक हालात को देखते हुए एफआईए, फार्मूला वन और तीन अन्य प्रोमोटरो ने यात्रा करने वाले स्टाफ, चैम्पियनशिप के प्रतिभागियो ओर प्रशंसको के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ए फैसले लिए।

कश्यप ने आईओसी से कहा, मजाक कर रहे हो क्या?

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय शटलर पारूपल्ली कश्यप ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के खिलाड़ियों को तोक्यो खेलों की तैयारियां जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी बयान को मजाक करार देते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के कारण सारे अभ्यास केंद्र बंद कर रखे हैं। ओलंपिक को टालने की लगातार मांग के बावजूद आईओसी ने बुधवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि ए खेले 24 जुलाई को सही समय पर शुरू होंगे। उसने सभी खिलाड़ियों से तोक्यो 2020 के लिए अपनी तैयारियां जारी रखने के लिए भी कहा। कश्यप ने ट्वीट किया, आईओसी हमें अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कैसे? कहां? आप मजाक कर रहे हो। कश्यप बर्मिंघम में आल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद लौटे हैं और उन्होंने खुद को अलग थलग रखा है।

बेहतर यही होगा कि ओलंपिक को स्थगित किया जाए : गोपीचंद

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद का मानना है कि कोविड-19 के कारण विश्व अभी जिस अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है उसे देखते हुए तोक्यो ओलंपिक खेल स्थगित कर देने चाहिए। तोक्यो में 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित करने की मांग तेजी से उठ रही है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं टाल दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है। इस महामारी के कारण विश्व भर में अब तक 8000 लोगों की जान गई है जबकि दो लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने बुधवार को हालांकि कहा कि उसे उम्मीद है कि तोक्यो खेल अपने सही समय पर शुरू होंगे। गोपीचंद ने पीटीआई से कहा, मुझे ओलंपिक को लेकर संदेह है। इनके आयोजन में अब

ज्यादा समय नहीं बचा है। तैयारियां अभी से शुरू होनी चाहिए थी। इसलिए आईओसी को अभी फैसला करना होगा जिससे हर कोई राहत की सांस ले सके।

मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सारी दुनिया अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सोच रही है, इसलिए परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक खेलों को स्थगित करना ही बेहतर होगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की इस घातक महामारी के फैलने के बावजूद इस महीने के शुरू में आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कड़ी आलोचना की गई थी। साइना नेहवाल सहित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बीडब्ल्यूएफ की वित्तीय लाभ के लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता करने के लिए कड़ी निंदा की थी और गोपीचंद ने भी इस पर अपनी स्पष्ट राय रखी। बर्मिंघम से लौटने के बाद खुद अलग थलग रह रहे गोपीचंद ने कहा, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बीडब्ल्यूएफ की तरफ से यह गलत फैसला था कि उसने आल इंग्लैंड का आयोजन करके खिलाड़ियों को जोखिम में रखा। खिलाड़ियों की आलोचना के बाद बीडब्ल्यूएफ ने अपने सभी टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक स्थगित कर दिए।

वीनस्टीन को 68वें जन्मदिन से पहले जेल भेजा गया

न्यूयॉर्क। मी टू मामले में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न का दोष साबित होने पर मिली 23 साल की कैद की सजा काटने के लिए फिल्म निर्देशक हार्वे वीनस्टीन को बुधवार को न्यूयॉर्क की जेल भेज दिया गया। राज्य जेल अधिकारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार को 68 साल के हो रहे वीनस्टीन को अधिकतम सुरक्षा वाली वेंडे करेक्शनल फैसिलिटी में रखा गया है। मैनहैटन से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जेल में वीनस्टीन कुछ समय के लिए रहेगा। वह जब तक यहां रहेगा, तब तक यह मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन सी जेल उसकी सुरक्षा, चिकित्या, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों से मेल खाती है।

इंदिरा वर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गईं

लंदन। गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार इंदिरा वर्मा ने बताया है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने यह जानकारी तब दी जब दो दिन पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता क्रिस्टोफर हिव्जु ने भी कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि की थी। एचबीओ की मशहूर सीरीज में एलारिया सैंड का किरदार निभाने वाली वर्मा ने इंस्टाग्राम पर यह खबर साझा की। उन्होंने लिखा, मैं बिस्तर पर हूं और मेरी तबीयत नासाज है। सुरक्षित और स्वस्थ रहे और अपने साथ के लोगों के प्रति दयालु रहे। 46 वर्षीय अभिनेत्री लंदन के वेस्ट एंड में द सीगुल नाटक में भी काम कर रही हैं। वैश्विक महामारी के कारण इस नाटक पर अभी रोक है। वर्मा ने कहा, बहुत दुखद है कि दुनियाभर में कई अन्य कार्यक्रम कोविड-19 के कारण काफी प्रभावित हुए हैं। हमें जल्द ही वापसी की उम्मीद है।

रश्मि रॉकेट में तापसी के पति बनेंगे प्रियांशु पेनयुली

मुंबई। अभिनेता प्रियांशु पेनयुली आगामी फिल्म रश्मि रॉकेट में अभिनेत्री तापसी पन्नू के पति के किरदार में नजर आएंगे। इस बारे में उन्होंने कहा, रश्मि रॉकेट में मैं सेना के एक अधिकारी की भूमिका में नजर आउंगा। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। जैसा कि मैं एक सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूं, वर्दी पहनना मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों ही है। प्रियांशु ने कहा कि फिल्म अगले महीने शुरू हो रही है और वे इसकी शूटिंग दिल्ली, कच्छ, देहरादून और मसूरी में होगी। हालांकि यह काल्पनिक फिल्म है, लेकिन यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित फिल्म रश्मि रॉकेट में कच्छ के रण के एक धावक की कहानी है।

'मैडम सर' में सुदेश बेरी निभायेंगे कैमियो किरदार

दिग्गज अभिनेता, सुदेश बेरी सोनी सब के नये, पारिवारिक मनोरंजक शो, 'मैडम सर' में कैमियो करते नज़र आयेंगे। शो 'मैडम सर' कलाकारों की जबर्दस्तस परफॉर्मेंस, लखनऊ में महिला पुलिस ऑफिसर्स के रूप में चार दमदार महिलाओं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति को सुलझाने के उनके अनोखे स्टा?इल से देश में लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो के बेहतरीन कलाकारों में शामिल हो रहे हैं, सुदेश बेरी, जोकि अंगद आचार्य का किरदार निभायेंगे। अपनी भूमिका और अनुभव के बारे में बताते हुए, सुदेश बेरी ने कहा, अंगद का मेरा किरदार काफी ताकतवर और पैसे वाला है। अंगद के विचार और उसकी मान्यहताएं सोच से परे हैं। वह दबंग है और किसी स्थिति से निपटने के लिये वह अपने पद और प्रभाव का इस्तेरमाल करने से नहीं हिचकता। मुझे इस भूमिका को निभाने में बहुत मजा आ रहा है, क?योंकि एक्टिंग मेरे लिये सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं, बल्कि मेरा विश्वारस है।

'सहायक कलाकारों में भी लीड रोल करने की महत्वाकांक्षा होती है'

ओके जानू और जग्गा जासूस और अब कामयाब जैसी हल्की फुल्की फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री **सारिका सिंह** से उनकी अब तक की यात्रा तथा अन्य विषयों पर बात की पायनियर संवाददाता **शालिनी सक्सेना** ने।

❐ क्या आप सदा से अभिनेत्री ही बनना चाहती थीं?

– जी हां, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12-13 सालों से हूं। मेरी यात्रा थियेटर में काम करने से ही प्रारंभ हुई थी। मैं कई नाटकों में काम कर चुकी हूं और मुझे थियेटर की हर चीज अच्छी लगती है। मैंने जब फिल्म उद्योग में प्रवेष किया था उसी समय मुझे पता था कि मेरा चेहरा पारंपरिक हीरोइन जैसा आकर्षक नहीं है। लेकिन थियेटर ने मुझे जस का तस स्वीकारा। वहीं से मुझे इस उद्योग के बारे में सबकुछ पता चला। मैं थियेटर से ही यहां तक पहुंच सकी हूं। पहले मैं फिल्म में एक या दो दृष्यों में ही दिखती थी और उसके बाद मुझे बाई या मां के चरित्र मिले और उसके बाद अब मुझे मुख्य भूमिकाएं भी मिलने लगी हैं।

❐ फिल्म कामयाब में आपकी क्या भूमिका है और फिल्म किस बारे में है?

– फिल्म एक व्यक्ति के बारे में है जिसने अपने जीवन में काफी समय तक साइड करेक्टर का चरित्र निभाया है। इसमें उसके संघर्षों और आकांक्षाओं के बारे में भी बताया गया है। मैंने इसमें इस व्यक्ति की पुत्री का चरित्र किया है। फिल्म में मैंने देखा है कि चरित्र के पिता को किन किन संघर्षों से दो-चार होना पड़ता है। उस इंडस्ट्री में जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन ही खपा दिया उनका उचित सम्मान नहीं होता। फिल्म का विषय और कहानी अत्यंत सुंदर और प्रभावित करने वाली है। इस इंडस्ट्री में लीड भूमिका करना ही सबकुछ नहीं होता। इसमें कई और लोग सहायक भूमिका में भी होते हैं लेकिन लोगों को वो पहलू दिखता ही नहीं है। फिल्म कामयाब में इसके निर्देशक हार्दिक मेहता ने दर्षकों से सहायक कलाकारों को भी उचित महत्व प्रदान करने के लिए आग्रह किया है।

❐ क्या आपको लगता है कि दर्शकों को फिल्म का विषय अच्छा लगेगा?

– क्यों नहीं, विषय अच्छा और नया है। अब लोगों को फिल्म की विषय सामग्री अच्छी चाहिये और कहानी वास्तविक हो। ऐसे में फिल्म को ऐसे लोग तो पसंद करेंगे ही जो ऐसी कहानी चाहते है जिसमें उन लोगों के बारे में बात की गई है जो 70 एमएम परदे पर अधिक ग्लैमरस नहीं लगते।

❐ क्या आप भी इस बात को मानती हैं कि इस परिवर्तन के कारण ही आप जैसे अभिनेत्रियों को भी अधिक अवसर मिलने लगे हैं?

– जी बिलकुल, जैसा कि मैंने पहले बताया, अब मुझे ऐसे रोल मिलने लगे हैं जिनमें मुझे दो या तीन दृश्यों से अधिक का चरित्र निभाना होता है। मुझे अब फिल्म के अनुसार प्रभावी भूमिकाएं मिलती हैं। तब मुझे और भी अच्छा लगता है जब लोग ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिनमें मेरे लिए 10 से 12 दृश्य करने होते हैं।

❐ आपने थियेटर, फिल्में और वेब सीरीज़ भी की हैं। ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं?

– यदि सच कहूं तो एक अभिनेता के अनुसार इनमें कोई अंतर नहीं है। मेरे मस्तिष्क के अनुसार मैं पहले अभिनेत्री हूं, मेरे लिए प्लेटफॉर्म का कोई अर्थ नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि थियेटर में आपके प्रदर्षन पर प्रतिक्रिया त्वरित प्रतिक्रिया होती है। आपको पता चल जाता है कि आप जो कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं या नहीं? या फिर वे आप पर टमाटर और अंडे फेंकने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आज जिस तरह की फिल्में और वेब सीरीज़ बन रही हैं, उनसे मेरे जैसी अभिनेत्री को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर तो मिल ही जाता है।

❐ क्या आपको लगता है कि कामयाब फिल्म की कहानी पर फिल्म बननी ही चाहिये थी?

– जी हां, ये काफी पहले बननी चाहिये थी। अब समय आ गया है कि लोगों को पता होना चाहिये कि अभिनेत्रियों का जीवन कैसे बीतता है। वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, जीवन से उन्हें क्या चाहिये होता है और उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? अभी तक लोगों को उनकी एक ही साइड के बारे में ही पता होता था। जबकि इसके अलावा भी उनका एक और पक्ष होता है जिसके बारे में भी लोगों को पता ही नहीं होता लेकिन वो महत्वपूर्ण होता है और उन्हें भी लीड अभिनेताओं जैसा महत्व मिलना चाहिये।

❐ क्या हमें कामर्शियल सिनेमा और समानांतर सिनेमा में भेद करना बंद कर देना चाहिये?

– देखिये सिनेमा तो सिनेमा होता है। अभिनेता के रूप में हम वही करते हैं जो हमसे कहा जाता है। जब मैंने ओके जानू, जग्गा जासूस और बॉम्बे वेलवेट फिल्में कीं, तो ये सोचकर नहीं की कि ये कॉमर्शियल हैं या समानांतर सिनेमा। लेकिन बाद में इसका वर्गीकरण भी हो गया।

❐ आपकी आने वाली फिल्में कौन-कौन सी हैं?

– थियेटर के अलावा कुछ फिल्में भी हैं जो इसी साल के अंत तक रिलीज़ होंगी। इसके अलावा कई ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो अभी निश्चित नहीं हैं और मैं उनके बारे में अभी बात नहीं कर सकती।

'यदि ठान ले तो महिलाएं हर संकल्प को पूरा कर सकती हैं'

जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री **मलाइका अरोड़ा** ने पायनियर संवाददाता **मुज़्बा हाशमी** के साथ एक बातचीत में एक सशक्त महिला की परिभाषा और आम लोगों को दिये जाने वाले संदेश आदि के बारे में बात की।

❐ एक सशक्त महिला की आपकी परिभाषा क्या है?

– हर महिला जो दूसरी महिला को ऊपर उठने में मदद करती है वो सषक्त होती है। सषक्त होना तो एक मानसिक अवस्था ही है और इससे पता चलता है कि आप जीवन की परिस्थितियों को किस प्रकार से संभालते हैं। आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए और हार न मानना ही साहसी महिला की पहचान होती है। जो महिला स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है और जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान का कारण बन सकती है वो महिला भी सषक्त महिला मानी जा सकती है।

❐ आपको किन महिलाओं ने प्रेरित किया है?

– ऐसी कई महिलाएं हैं। लेकिन मेरी मां मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और वो सब करने और बनने में मेरी मदद की जो मैं आज हूं। मैं उन ग्रहों का धन्यवाद करना चाहती हू कि मैं एक ऐसी मां की बेटी हूं जिसने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया और जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया।

❐ महिला दिवस को लेकर क्या विचार हैं और इसके मनाने पर आप क्या कहना चाहती हैं?

इस बार के महिला दिवस की थीम ईच फॉर इक्वल अर्थात समानता के लिए सभी प्रयास करें। तो मेरा मानना है कि हमें महिलाओं के लिए भी समानता चाहिये। यदि महिला ठान ले तो वो भी जीवन में वो कर सकती है जिसका उसने संकल्प लिया हो। महिला होना विशेष बात है और इस दिन को महिलाओं की अजेय भावना का सम्मान किया जाना चाहिये।

❐ आप क्या संदेश देना चाहेंगी?

– सभी महिलाएं सशक्त बनें। अपने स्त्री होने पर गर्व करें और वो सबकुछ करें जिससे आप आगे बढ़ने में समर्थ हों।

जाह्नवी कपूर मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी: अनन्या

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे का मानना है कि स्टार किड्स होने का एक फायदा यह है कि वह इंडस्ट्री के लोगों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही वह यह भी मानती हैं कि जाह्नवी कपूर उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी हैं।

भाई-भतीजावाद को लेकर हो रही चर्चा पर अनन्या ने कहा, मैं अब भी यह बात मानती हूं कि हमें काफी फायदा है, हम कई लोगों से मिल पाते हैं। इंडस्ट्री के लोगों से हम आसानी से संपर्क कर पाते हैं, क्योंकि हम उनके बीच में ही रहकर बड़े होते हैं, लेकिन अब चूंकि मुझे मौका मिला है, तो मेरे लिए इसे गंवाना व्यर्थ होगा। मैं अपने पिता को गौरवान्वित करना चाहती हूं। अनन्या ने स्टारी नाइट्स जेन वाय के एक एपिसोड में अपने फिल्मी सफर के बारे में बात की। शो में उन्होंने यह भी स्वीकारा कि फिल्म इंडस्ट्री में जाह्नवी कपूर उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी हैं।

शहर से दूर रह कर बच्चे की तरह महसूस कर रही हूं: जीजी हदीद

लॉस एंजेलिस। मॉडल जीजी हदीद का हाल ही में एक नहीं बल्कि चार प्रसिद्ध दोस्तों सेरेना विलियम्स, केंडल जेनर, ब्लेक लिवली और टेलर स्विफ्ट ने साक्षात्कार लिया था।

हार्पर बाजार मैगजीन में प्रकाशित हुए साक्षात्कार में जीजी ने अपने जिंदगी से जुड़ी कई जानकारियों का खुलसा किया। इन्हीं कुछ दिलचस्प बातों के माध्यम से उनके प्रशंसकों को पता चला कि मॉडल को वास्तव में बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से ज्यादा ग्रामीण इलाके की शांति पसंद है।

उन्होंने कहा कि वह अपनी मां योलांडा हदीद के पेनसिल्वेनिया स्थित घर में हैं और वहां वह जिंदगी की साधारण खुशियों का आनंद ले रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जीजी ने कहा, फार्म ने मुझे वास्तव में याद दिला दिया है कि आम खुशियां क्या होती हैं, और मैं अपने जीवन को जी रही हूं। यह मेरे पूरे दिन को उन छोटी चीजों के माध्यम से व्यस्त रखता है जो मुझे खुश करती हैं, जैसे कि कला, बागवानी, योग, खाना बनाना, बाहर रहना और अपने प्रियजनों और जानवरों के साथ समय बिताना, वह भी बिना इस बात की चिंता किए कि मैंने क्या पहना है या मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं या मुझे फोटो खिंचवानी हैं। शहर से दूर और लोगों की आंखों से दूर रह कर मुझे एक बच्चे की तरह महसूस हो रहा है।

अंडरकवर एजेंट विस्मृत नायक हैं: के के मेनन

मुंबई। अभिनेता के के मेनन का कहना है कि उनकी वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स इंडियन इंटेलिजेंस की भूमिका को एक अनूठी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।

शिवम नायक के साथ मिलकर नीरज पांडे ने सीरीज को निर्देशित किया है। आठ एपिसोड वाली हॉटस्टार स्पेशल की इस स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज की कहानी पिछले 19 सालों में भारत में हुए आतंकी हमलों में इंडियन इंटेलिजेंस की भूमिका पर आधारित है, इसमें 26/11 का आतंकी हमला भी शामिल है। के के मेनन इसमें हिम्मत सिंह के किरदार में हैं, जो आतंकी अजमल कसाब से पूछताछ करते नजर आएंगे।

के के ने कहा, 26/11 एक ऐसा दिन था जब पूरा देश चौंक गया था। स्पेशल ऑप्स इंडियन इंटेलिजेंस की भूमिका को एक अनूठी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा, अंडरकवर एजेंट्स आज के जमाने के विस्मृत नायक हैं। स्पेशल ऑप्स ने इन एजेंट्स की जिंदगी को सामने लाने की कोशिश की है, जो आतंकी हमलों की साजिश रचने वालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम सभी उनके ऋणी हैं।

मेनन इस सीरीज में हिम्मत सिंह के किरदार में हैं, जो आतंकी अजमल कसाब से पूछताछ करते नजर आएंगे।

17 मार्च से सात भाषाओं में हॉटस्टार वीआईपी में इसे प्रसारित किया जाएगा।

शाहरुख की फिल्म बाजीगर के दीवाने हैं सिद्धार्थ निगम

मुंबई। अभिनेता सिद्धार्थ निगम सुपरस्टार शाहरुख खान के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्हें शाहरुख का अभिनय बेहद पसंद है। खासकर बाजीगर में वह शाहरुख द्वारा निभाए गए किरदार के मुरीद हैं। सोनी मैक्स 2 के टाइमलेस डिजिटल अवॉर्ड्स से इतर सिद्धार्थ ने कहा, शाहरुख ने बाजीगर और कुछ कुछ होता है में जिस तरह से अपने किरदार को निभाया है, वह मुझे बहुत पसंद है। हर बार जब मैं इन फिल्मों को देखता हूं, वह काफी फ्रेश लगते हैं। बाजीगर मेरी उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म है, इसमें उनका किरदार बहुत सशक्त है। यह किरदार दर्शकों को अच्छा महसूस कराता है, जिसके चलते यह अपने आप में अनोखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे इतने अच्छे तरीके से निभा पाता। सिद्धार्थ फिलहाल टीवी शो अलादीन नाम तो सुना होगा में अपने किरदार से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं।

सशक्त भारतीय महिला के चित्रण में योगदान देना चाहती हैं मानुषी

मुंबई। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म पृथ्वीराज में सुपरस्टार अक्षय कुमार के विपरीत नजर आएंगी। उनका कहना है कि सिनेमा में सशक्त भारतीय महिला का चित्रण करने की दिशा में वह अपना योगदान देने की चाह रखती हैं।

मानुषी ने कहा, यह मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। मैं अपना सब कुछ देकर बहुत कड़ी मेहनत करने का प्रयास कर रही हूं, ताकि जब यह फिल्म रिलीज हो, तब मुझे दर्शकों से ढेर सारा प्यार और खूब सराहना मिले।

मैं सिनेमा में सशक्त भारतीय महिला का चित्रण करने की दिशा में अपना योगदान देना चाहती हूं, जो खूबसूरत, सशक्त, आगे की सोच रखने वाली, मुखर, स्वतंत्र और ईमानदार हैं।

फिल्म में अक्षय वीर शासक पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभा रहे हैं, जबकि मानुषी उनकी पत्नी संयोगिता के किरदार में हैं। उन्होंने आगे कहा, संयोगिता का किरदार मेरे लिए एक ड्रीम रोल है और मुझे इसे निभाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह परियोजना इस साल दीवाली पर रिलीज होगी।